R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 21 । अंक : 12
16 से 31 मार्च 2023
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

मध्य प्रदेश बजट 2023

चुनावी साल... बजट से बेड़ा पार का जुगाड़

शिव'राज'का इंद्रधनुषी दांव

3.14 लाख करोड़ का बजट पेश, 55 हजार करोड़ का घाटा

बहनों और भांजियों की बल्ले बल्ले! युवाओं पर भी फोकस

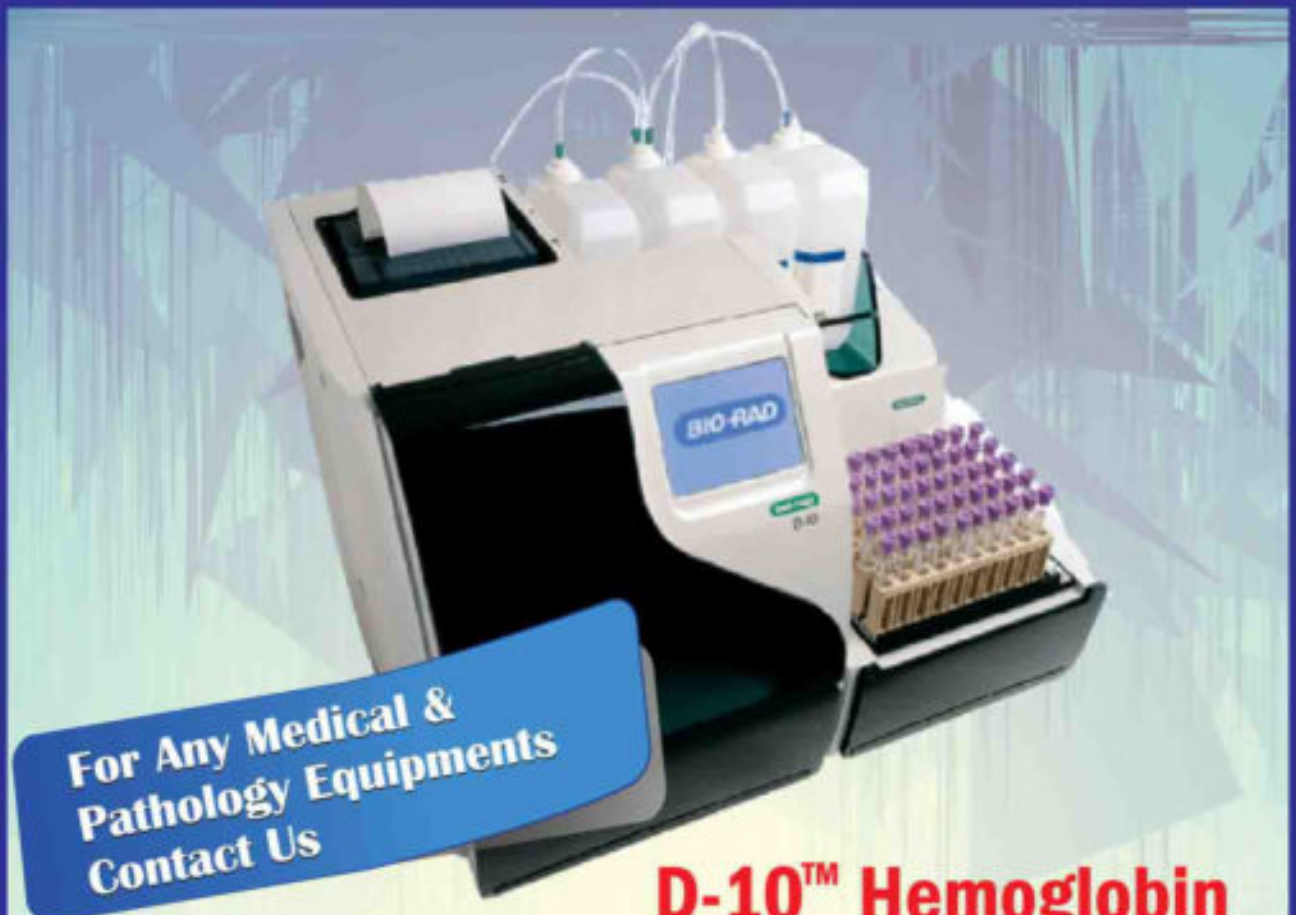

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; it's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or HbA_2/FiA_{1c} testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

इस अंक में

मप्र कांग्रेस

9 | क्या नाथ दिखाएंगे करिश्मा?

मप्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने मप्र में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कमलनाथ पार्टी का चेहरा होंगे।

राजपथ

10-11 | फीडबैक पर टिका 127...

आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की पूरी कोशिश है कि गुजरात की ही तरह जीत का रिकॉर्ड बनाया जाए। इसके लिए पार्टी के रणनीतिकारों ने 200 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य भी बनाया है। इस लक्ष्य को पाने...

मेट्रो

13 | अगस्त से पहले भोपाल...

मप्र के दो बड़े शहर भोपाल और इंदौर में दौड़ने वाली मेट्रो ट्रेन के कोच (बोगियां) गुजरात में बनेंगे। फ्रांस की एल्सटॉम ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड कोच बनाएगी। मेट्रो ट्रेन सेट की यूनिट की 13 मार्च से शुरुआत हुई। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने...

विकास

15 | मप्र में बिछेगा फ्लाईओवर...

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मप्र को फ्लाईओवरों की सौगात दी थी। उनका निर्माण अब सेतुबंध योजना के तहत कराया जा रहा है। 9 शहरों में 17 फ्लाईओवर एमआरडीसी यानी मप्र सड़क विकास निगम करवाएगा। इन फ्लाईओवरों के निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

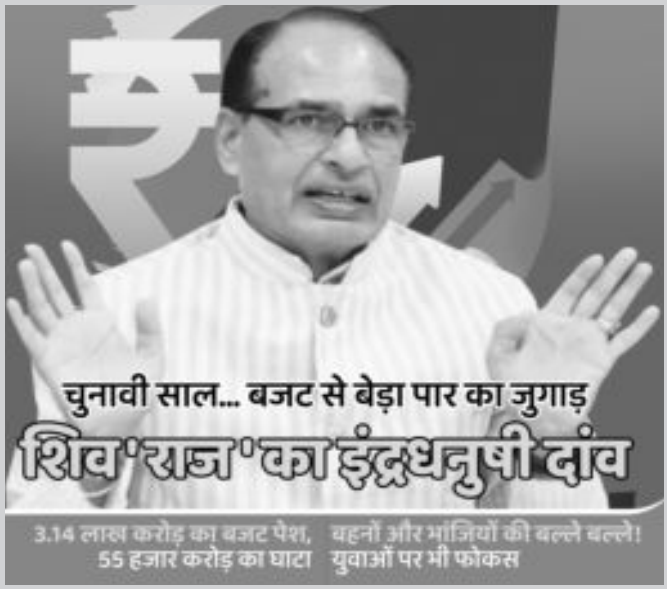

यह साल विधानसभा चुनाव का है। चुनावी साल में मप्र की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बजट से चुनावी बेड़ा पार करने की भरपूर जुगाड़ की है। इसके लिए शिव'राज' ने इंद्रधनुषी दांव चला है। शिवराज सरकार ने 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ का बजट पेश किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश का राजकोषीय घाटा 55,709 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4.2 प्रतिशत रहेगा। इन सबके बावजूद बजट को आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए तैयार किया गया है।

राजनीति

30-31 | गुप्त चुनावी चंदे का दुरुपयोग...

सन् 2017 के बजट सत्र में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने जिस गुप्त चंदा (इलेक्टोरल बॉन्ड) को आधिकारिक सहमति दी थी, उसके नुकसान और दुरुपयोग को लेकर कयास लगते रहे हैं। ऐसे आरोप लग चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास 70 से 80 फीसदी तक गुप्त चंदा आ...

महाराष्ट्र

35 | पवार की चाल से फंसी शिवसेना

महाराष्ट्र में ऑपरेशन शरद पवार शुरू हो चुका है। कांग्रेस और शिवसेना को पीछे छोड़कर शरद पवार आगे निकल गए हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद एनसीपी प्रमुख विपक्षी पार्टी बन गई है। जबकि 2019 के चुनाव नतीजों में एनसीपी तीसरे नंबर की पार्टी थी। अगले विधानसभा...

बिहार

38 | जातीय जनगणना पर सियासत

बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना की शुरुआत करने को बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है, जिससे अन्य राज्यों में भी आगामी लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा फिर गर्मा सकता है। जाहिर है कि नीतीश कुमार और लालू यादव हमेशा इसके पक्ष...

6-7 अंदर की बात
40 विदेश
41 महिला जगत
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

ये राजनीति का खेल, पटवारी हो गए फेल...

विनोद बक्सरी का एक शेर है...

राजनीति में चलता है कुछ इस तरह का खेल
मिलजुल कर दिया जाता है बोलने वालों को फेल

राजनीति में कब क्या हो जाए इसका कोई अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। यही कारण है कि बड़े-बड़े महारथी पलभर में पस्त हो जाते हैं। ऐसे ही महारथियों में शामिल मप्र कांग्रेस के तेज तर्रार विधायक जीतू पटवारी राजनीति के खेल में इस कदर फंस गए कि उन्हें मप्र विधानसभा के बजट सत्र के दौरान निलंबन झेलना पड़ रहा है। दरअसल, पटवारी जिस तरह से मप्र की राजनीति में अपनी वाकपटुता के कारण कद्दावर होते जा रहे हैं, इस कारण वे भाजपा के साथ ही अपनों को भी खटक रहे हैं। पटवारी हमेशा ऐसा कुछ न कुछ करते रहते हैं, जिससे वे सुर्खियों में बने रहते हैं। मप्र के विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया तो इसके शिकार जीतू पटवारी हो गए। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का कहना है कि पटवारी ने आसंदी के आदेशों की अवहेलना की है। तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया है। इसलिए उन्हें निलंबित किया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी पर परोक्ष रूप से की गई टिप्पणी को अमर्यादित मानते हुए विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को पूरे बजट सत्र से निलंबित कर दिया था। पटवारी के निलंबन का प्रस्ताव संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रखा था। इस पर मौखिक वोटिंग कराकर फैसला हुआ। जानकारों का कहना है कि जीतू पटवारी को निलंबित करने के पीछे सत्तापक्ष और विपक्ष की सोची-समझी रणनीति है। दरअसल, जीतू पटवारी जिस तरह पार्टी लाइन के बाहर जाकर बयान दे रहे थे, उससे कांग्रेस भी परेशान थी। यही नहीं कांग्रेस में कमलनाथ को निपटाने के लिए एक धड़ा सक्रिय है। इसका संकेत इससे भी मिलता है कि नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव की जो सूचना दी है, उसमें 45 विधायकों के सिग्नेचर हैं, लेकिन कमलनाथ के साइन नहीं हैं। इस पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा कि वो बेचारा अकेला रह गया। शोले फिल्म जैसी हालत हो गई, आधे इधर जाओ-आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। यही नहीं 13 मार्च को जब विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में जीतू पटवारी के निलंबन को समाप्त करने के लिए सहमति बनाने पर चर्चा हुई। सत्तापक्ष ने कांग्रेस की बात सुन ली, लेकिन किया कुछ भी नहीं। इस कारण पटवारी का निलंबन बरकरार रहा। दरअसल, कांग्रेस भी नहीं चाहती है कि जीतू पटवारी का निलंबन समाप्त हो। शायद यही वजह है कि इस मामले को लेकर कांग्रेस अभी तक आक्रामक मुद्रा में नजर नहीं आई है। उधर, कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अपनी गरिमा के विपरीत निर्णय लिया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जीतू पटवारी के निलंबन के बाद विधानसभा में जिस तरह के हालात देखे गए उससे ऐसा लगा कि कांग्रेस को उनके निलंबन से कोई अधिक दुख नहीं है। उधर, सत्तापक्ष भी इस बात से संतुष्ट नजर आया कि उस पर आरोप लगाने वाला एक विधायक सदन से बाहर हो गया है। अब देखना यह है कि राजनीति के इस खेल में पटवारी की क्या स्थिति होती है। वैसे पटवारी पिछले कुछ साल से अपनी पार्टी और भाजपा दोनों की आंखों में खटक रहे थे। उनके निलंबन से दोनों पार्टियों को फायदा हुआ है।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 21, अंक 12, पृष्ठ-48, 16 से 31 मार्च, 2023

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी
फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,
फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर,
भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर,
मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास
मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

अटक गया मास्टर प्लान

प्रदेश की राजधानी भोपाल का आखिरी मास्टर प्लान 2005 में आया था। इस मास्टर प्लान में तय की गई करीब 26 सड़कें आज तक नहीं बन पाईं। इन मास्टर प्लान की सड़कें अतिक्रमण और भू–अर्जन की वजह से अटकी हुई हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

● **विशाल सोनी,** भोपाल (म.प्र.)

जमीनों की नई गाइडलाइन

मप्र में जमीनों को लेकर कई गाइडलाइंस हैं। कलेक्टर गाइडलाइन में इस बार जमीनों के रेट बढ़ाने का जो प्रस्ताव पंजीयन अफसरों ने तैयार किया है उसमें नए प्रोजेक्ट के साथ दुकानों, मार्केट में अधिक दर पर हुई रजिस्ट्री को भी शामिल किया है, जो कि अच्छा कदम है।

● **सबा खान,** इंदौर (म.प्र.)

मजबूत विपक्ष

किसी भी राजनीति में सत्तापक्ष के खिलाफ खड़े रहने के लिए एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है। चुनावी साल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुट में बंट जाना पार्टी की जीत में कमजोर कड़ी साबित हो सकती है। इसलिए पार्टी को सभी नेताओं को साधना होगा और साथ में लेकर चलना होगा।

● **सुनील सिंह,** ग्वालियर (म.प्र.)

खर्च नहीं हुआ बजट

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मप्र को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में दिन–रात एक किए हुए हैं। मुख्यमंत्री लगातार विभागों की समीक्षा कर अफसरों को निर्देशित करते रहते हैं। वे विकास योजनाओं में तेजी लाते हुए बजट खर्च करने को कहते हैं। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद भी ज्यादातर बड़े विभागों ने 60–70 फीसदी से अधिक पैसा खर्च कर दिया, लेकिन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, राजस्व और वाणिज्यिक कर पीछे चल रहे हैं। खाद्य विभाग और वाणिज्यिक कर तो आधा पैसा भी अभी खर्च नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी राज्य में कई विभागों के आला अफसर तथा मंत्रियों ने सरकार की मंशा के मुताबिक बजट से कार्य कराने में मुस्तैदी नहीं दिखाई।

● **प्रदीप शाक्या,** जबलपुर (म.प्र.)

चुनावी तैयारियां शुरू

देशभर में इस समय चुनाव का माहौल बना हुआ है। 2023 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। इन चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां भाजपा जगह–जगह सभाएं कर चुनावों में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां बैठकें कर चुनावी रणनीति बना रही हैं। सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों के पास धर्म–जाति का झुनझुना है। दोनों चाहते हैं कि बस इसे बजाएं और जनता इसमें उलझी रहे।

● **रोहित नागर,** राजगढ़ (म.प्र.)

स्कूली व्यवस्था दुरुस्त हो

मप्र में इस साल चुनाव होने हैं। जिसके चलते विकास का सरकारी प्रोपगेंडा शुरू हो चुका है। दावों और वादों की बाढ़ आ गई है, लेकिन आज भी प्रदेश के कई स्कूलों में शिक्षा का कोई माई बाप नहीं है। यदि हमें हमारे प्रदेश और देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो सबसे पहले हमें देश के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। सरकारी स्कूलों में सरकार को ध्यान देकर बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था करनी होगी।

● **नेहा पुरोहित,** सीहोर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन–1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ–02, 03, एमपी नगर, भोपाल

महागठबंधन से राजपूतों का मोहभंग

लोकसभा चुनाव 2024 जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे बिहार की राजनीति में उठा-पटक बढ़ती जा रही है। इस बीच आरा से सांसद रहीं मीना सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। मीना से पहले उपेंद्र कुशवाह और आरसीपी सिंह का महागठबंधन और नीतीश का साथ छोड़ चुके हैं। अब मीना के भाजपा में शामिल होने से बिहार की राजनीति में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या राजपूतों का महागठबंधन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मोहभंग हो रहा है? बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद से वे अपनी पार्टी से नाराज चल रही थीं। उनका कहना है कि माफिया राज के चलते राज्य में अपराधियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। भाजपा के खिलाफ देशभर के विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे नीतीश कुमार के लिए यह बड़ा झटका साबित होगा। गौरतलब है कि मीना सिंह अपने पति अजीत सिंह के निधन के बाद वर्ष 2009 में आरा से सांसद चुनी गई थीं। इससे पहले उन्होंने बिक्रमगंज लोकसभा सीट का भी प्रतिनिधित्व किया। अजीत सिंह बिक्रमगंज से सांसद थे और सहकारिता क्षेत्र में देश के बड़े नेता थे।

शर्मा का बढ़ेगा कद

त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं, चुनाव से पहले चर्चा थी कि यह चुनाव जहां भाजपा के लिए अग्निपरीक्षा से कम नहीं है वहीं त्रिपुरा प्रभारी व नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेश शर्मा की प्रतिष्ठा भी दांव पर है।

सब जानते हैं कि वर्ष-2014 में पहली बार गौतमबुद्ध नगर से लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद महेश शर्मा को नागरिक उड्डयन, संस्कृति व पर्यटन जैसे तीन महत्वपूर्ण मंत्रालयों का मंत्री बनाया गया था। वर्ष 2019 में वे और भी अधिक मतों से चुनाव जीतने के बावजूद केंद्र में मंत्री बनने से वंचित रह गए थे। लेकिन उनकी सक्रियता से खुश होकर हाईकमान ने उन्हें त्रिपुरा के प्रभारी पद की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी जिसमें वे सफल भी हो गए। उनके प्रभारी बनने के बाद त्रिपुरा में भाजपा के सांगठनिक ढांचे में मजबूती भी आई और पार्टी को बंपर जीत भी हासिल हो गई। इस जीत के बाद अब सियासी गलियारों में कयास लगाए जाने लगे हैं कि जब भी मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा तब महेश शर्मा को उनकी कैबिनेट में जगह या किसी बड़े पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि त्रिपुरा विधानसभा चुनावी नतीजे शर्मा के राजनीतिक भविष्य की नई इबारत लिखेंगे।

शुरू हुई भावी मुख्यमंत्री पद की जंग

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं लेकिन राज्य की राजनीति में इन दिनों चर्चा है कि अगर भविष्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो यह पद किसे मिलेगा? बीते दिनों जिस तरह एनसीपी कार्यालय के बाहर एक के बाद एक बैनर देखे जा रहे हैं उन्हें लेकर कहा जा रहा है कि एनसीपी में अभी से भावी मुख्यमंत्री पद की जंग शुरू हो गई है। दरअसल एनसीपी में जयंत पाटिल और अजित पवार के बाद अब सुप्रिया सुले का बैनर सामने आया है। इस बैनर पर सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र की पहली भावी महिला मुख्यमंत्री बताया गया है। खास बात यह है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने एनसीपी कार्यालय के बाहर यह पोस्टर लगाया था। लेकिन फौरन इस पोस्टर को हटा दिया गया। क्योंकि इस बैनर पर सुप्रिया सुले के साथ उनके पिता और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तस्वीर लगी हुई थी। इससे पहले एनसीपी के दफ्तर के बाहर अजित पवार का बैनर लगा था जिसमें 'महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री इक्का दादा अजीत दादा' टेक्स्ट लिखा हुआ था। जबकि इससे पहले उनके जन्मदिन पर लगे बैनर पर जयंत पाटिल को महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री के रूप में दिखाया गया था। सामने आने से राज्य की राजनीति में यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या एनसीपी में मुख्यमंत्री पद की रेस शुरू हो गई है।

खामोशी की गूंज

वसुंधरा राजे ने भाजपा को अपनी शक्ति का अहसास करवा दिया है। पार्टी में बेशक उनका परिचय 2018 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का है पर वे खुद इस पद पर कभी भी सक्रिय नहीं दिखीं। आलाकमान उनकी लगातार उपेक्षा करता रहा और वे भी खामोशी से सही वक्त का इंतजार करती रहीं। उनकी अनदेखी कर उनके विरोधी विधायक सतीश पूनिया को पार्टी का सूबेदार बनाया गया और कई बार के लोकसभा सदस्य होने के बावजूद उनके बेटे को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन अब चुनावी वर्ष आया तो वसुंधरा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए सक्रियता बढ़ा दी। आलाकमान को भी समझ आ गया कि वसुंधरा की अनदेखी कर सूबे में सत्ता वापस पाना सरल नहीं होगा। तभी तो पिछले साल हैदराबाद में गृहमंत्री अमित शाह ने पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में उनका परिचय राजस्थान की यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री कहकर कराया था। हालांकि, अभी तक भी आलाकमान ने साफ नहीं किया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा वसुंधरा होंगी।

हर समस्या का उत्तर

हिमंत बिस्वा सरमा भाजपा में नायक बन चुके हैं। पूर्वोत्तर के जिन तीन राज्यों के पिछले दिनों विधानसभा चुनाव हुए, वहां की सरकारों से कांग्रेस का पत्ता साफ करने में अहम भूमिका असम के मुख्यमंत्री सरमा की ही रही। सरमा ने मेघालय में भाजपा को अलग रख सरकार बनवाने के तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी के प्रयासों को नाकाम कर दिया। सबसे बड़ी पार्टी के नेता संगमा को इस बात के लिए रजामंद किया कि वे भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएं। नगालैंड और मेघालय में मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री को बुलवाया। नगालैंड में सर्वदलीय सरकार का गठन करने में भी अहम भूमिका निभाई और त्रिपुरा में माणिक साहा को ही फिर सरकार की कमान दिलाई। भाजपा आलाकमान केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक को मुख्यमंत्री बनाने के मूड में था। सरमा भाजपा में 2015 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर शामिल हुए थे। असम की तीन कांग्रेस सरकारों में भी वे लगातार मंत्री रहे थे।

मंत्री के रसूख पर महिला से दादागिरी

प्रदेश में एक तरफ सरकार के मुखिया महिलाओं के मान-सम्मान में कोई कोरकसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकारी कार्यक्रमों में कन्याओं की पूजा करने वाली सरकार के एक पुलिस अधिकारी मंत्री के रसूख पर महिला से बदसलूकी करने के कारण इन दिनों चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। मामला विंध्य क्षेत्र के एक जिले का है। राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी ये साहब जिले में एडिशनल एसपी के पद पर तैनात हैं। ये साहब प्रदेश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री के साढूभाई हैं। मंत्रीजी का रसूख वर्तमान सरकार में सर्वोच्च पर है। ऐसे में साहब भी उनके रसूख का जमकर फायदा उठा रहे हैं। यानी साहब जिले में जमकर मनमानी कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि साहब की शह पर ट्रैफिक वाले जिले में जमकर वसूली कर रहे हैं। ऐसे ही वसूली का मामला जब विगत दिनों सामने आया तो साहब आगबबूला हो उठे और उन्होंने आव देखा न ताव और कहा कि जब पुलिस वाले वसूली कर रहे थे तो आरटीओ वालों ने उन्हें रोका क्यों नहीं। यही नहीं इस दौरान जब एक महिला ने वसूली पर सवाल खड़े किए तो साहब उससे भी भिड़ गए। उक्त महिला के साथ साहब के हॉट टॉक का ऑडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। लेकिन अभी तक साहब का कोई बाल बांका भी नहीं कर पाया है। दरअसल, साहब को मालूम है कि उनके रिश्तेदार मंत्री के कारण उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

क्यों रुक गया मास्टर प्लान?

देश के हृदय प्रदेश की राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाने का जो सपना सरकार देख रही थी, उस पर पानी फिरने वाला है। वहीं दूसरी तरफ विडंबना यह देखिए कि राजधानी का मास्टर प्लान अभी तक लागू नहीं किया गया है। सरकार ने इस बार पूरा दम दिखाया था कि नए साल में मास्टर प्लान हर हाल में लागू कर दिया जाएगा, लेकिन एक बार फिर मास्टर प्लान न जाने क्यों रुक गया है। राजधानी का मास्टर प्लान कहीं गुम हो गया है या किसी ने दबा दिया है, यह खोज का विषय है। उधर, सूत्रों का कहना है कि शायद मास्टर प्लान भूमाफिया के हत्थे चढ़ गया है। गौरतलब है कि राजधानी का मास्टर प्लान पिछले 17 सालों से लागू नहीं हो पाया है। इसकी वजह यह है कि मास्टर प्लान जब भी बनकर तैयार होता है, भूमाफिया उसकी राह में बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं। इस समय राजधानी में प्रशासन द्वारा संरक्षित एक दलालनुमा माफिया का दबदबा है। सूत्रों का कहना है कि इस माफिया ने कई क्षेत्रों में वैध और अवैध तरीके से जमीनें बना ली हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कहीं इसी माफिया के कारण तो मास्टर प्लान नहीं रुक गया है। वजह कुछ भी हो, लेकिन यह हकीकत है कि मास्टर प्लान के बिना राजधानी का विकास असंतुलित तरीके से हो रहा है।

साहब का रसूख अभी भी कायम

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों 1985 बैच के एक रिटायर्ड प्रमोटी आईपीएस अधिकारी के रसूख की जमकर चर्चा हो रही है। साहब को रिटायर हो बरसों हो गए, लेकिन अभी भी वे पुलिसिया ठाट में नजर आते हैं। गौरतलब है कि ये साहब आईजी रह चुके हैं। ये रिटायर हो गए हैं लेकिन पुलिसिया ठाट-बाट अभी भी कायम है। आलम यह है कि साहब ने अपनी गाड़ी में अभी भी स्टार लगा रखा है। साहब जब गाड़ी में बैठकर निकलते हैं तो स्टार उनके रसूख को दर्शाता है। वहीं जब से गाड़ी में नहीं रहते हैं तो उसे ढंक दिया जाता है। साहब के पुलिसिया रसूख का आलम यह है कि अभी भी वे अपने आपको आईजी ही मानते हैं। वे इसी अंदाज से लोगों को हड़काने से भी नहीं चूकते हैं। सूत्रों का कहना है कि साहब के इस अंदाज से उनके आसपास के लोग भी परेशान हैं। बताया जाता है कि साहब ने अपने मकान के पास खुद अतिक्रमण कर रखा है। लेकिन वे अपने एक पड़ोसी को लगातार चमकाते रहते हैं। बेचारा पड़ोसी जिसने वैध जमीन पर वैध तरीके से मकान बनाया है, वह इस बात से परेशान है कि अतिक्रमण करने वाले साहब उसे आए दिन धमकाते रहते हैं। यही नहीं साहब अपना रसूख दिखाने के लिए लगातार मंत्रियों के यहां दस्तक देते रहते हैं। कभी-कभी तो वे अपने रिश्तेदार पुलिस अधिकारी से लोगों को चमकाने का काम भी करवाते हैं। साहब की इस मनमानी से लोग परेशान हैं।

मंत्री के चढ़ावे से परेशान!

सूखा, आर्थिक तंगी, गरीबी से बदहाल बुंदेलखंड क्षेत्र के एक जिले से आने वाले एक मंत्री को दिए जाने वाले चढ़ावे से क्षेत्र के खनिज व्यवसायी परेशान हैं। गौरतलब है कि साहब जिस जिले से संबंध रखते हैं वह जिला खनिज संपदा के लिए विख्यात है। सूत्रों का कहना है कि साहब जबसे मंत्री बने हैं, उन्होंने सरकार का खजाना भरने की बजाय अपना खजाना भरने पर अधिक ध्यान दिया है। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़े की तर्ज पर उन्हें ओएसडी के रूप में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक ऐसा अधिकारी मिल गया है, जो वसूली के मामले में पहले से ही कुख्यात है। फिर क्या, दोनों मिलकर विभाग का दोहन करने में जुटे हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि स्थिति यह है कि मंत्रीजी के क्षेत्र में रेत, गिट्टी और अन्य खनिज संपदा का वैध या अवैध परिवहन करने वाले ट्रकों को सबसे पहले मंत्रीजी को पेशगी देनी पड़ती है। जो पेशगी देता है, उसकी हर खामी माफ कर दी जाती है, लेकिन जो नहीं देता है, उससे दोगुना, तीन गुना वसूल लिया जाता है। मंत्रीजी तो कम उनके ओएसडी अपने दोनों हाथों से लक्ष्मीजी को बटोरने में जुटे हुए हैं।

लोकायुक्त-सरकार आमने-सामने

प्रदेश में सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का दम भर रही है। प्रदेशभर में सुशासन के दावे किए जा रहे हैं। इन सबके बावजूद प्रदेश में भ्रष्टाचार 26 फीसदी तक बढ़ गया है। यह दावा प्रदेश की जांच एजेंसी लोकायुक्त ने किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार सही है या लोकायुक्त। अगर लोकायुक्त के आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश में रोजाना कहीं न कहीं घूसखोर अधिकारी-कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं। छोटे-छोटे कर्मचारियों के पास बेहिसाब संपत्ति जप्त की जा रही है। यह इस बात का संकेत है कि प्रदेश में सरकार के दावों के अनुसार कहीं भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति काम नहीं कर रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि प्रदेश में जब छोटे अधिकारियों-कर्मचारियों के पास बेतहाशा काली कमाई निकल रही है तो बड़ों की क्या स्थिति होगी। गौरतलब है कि एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है, दूसरी तरफ भ्रष्टों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति नहीं देती है। ऐसे में लोकायुक्त के आंकड़ों को नकारा नहीं जा सकता।

फिल्म आरआरआर के गाने नाटू-नाटू को बेस्ट ऑरिजिनल सॉन्ग कैटेगिरी में ऑस्कर मिलने से मैं काफी उत्साहित हूं। 15 साल बाद भारत को यह अवार्ड मिला है। मैं कभी असमय मृत्यु के डर से डेढ़ साल तक संन्यासी बनकर घूमा हूं।

● **एमएम किरवानी**

मैंने सुना है। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की अच्छी दोस्ती है। गहलोत पर आंच आती है तो वसुंधरा ने पूरी पार्टी उनके लिए खड़ी कर दी। ऐसे ही जब भाजपा राजे पर कार्यवाही कर रही थी, तो गहलोत ने कांग्रेस उनके लिए खड़ी कर दी। लेकिन अब इस राज्य में यह दोस्ती नहीं चलने वाली, क्योंकि हम जनता के सामने हकीकत पेश करेंगे।

● **अरविंद केजरीवाल**

भारत ने ऑस्ट्रेलिया से न केवल लगातार चौथी टेस्ट सीरीज जीती है, बल्कि भारत लगातार दूसरी बार डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचा है। यह इस बात का संकेत है कि भारत में क्रिकेट किस ऊंचाई पर पहुंचा है। आज भारत की क्रिकेट टीम हर फॉर्मेट में मजबूत है। इसके पीछे खिलाड़ियों की मेहनत और लगन है।

● **राहुल द्रविड**

अजान की आवाज से मुझे सिरदर्द होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अल्लाह बहरा है, जो उन्हें बुलाने के लिए लाउडस्पीकर पर चिल्लाना पड़ता है। मैं जहां भी जाता हूं, वहां लाउडस्पीकर पर अजान सुनाई देती है, इससे कई बार मन विचलित होता है।

● **ईश्वरप्पा**

मैं अपने 23 साल के बॉलीवुड कैरियर में कई उतार-चढ़ावों से गुजरी हूं। मुझे अतीत में किए गए फैसलों पर कोई पछतावा नहीं है। एक दशक पहले फिल्म इडस्ट्री में बहुत ज्यादा कॉम्पटीशन रहा करता था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं और मुस्कुराती हूं, क्योंकि मुझे अपनी जर्नी पर प्राउड फील होता है। सैफ अली खान से शादी करने के बाद मेरी लाइफ में सबसे बड़े बदलाव आने शुरू हुए। मैं अब बच्चों को खुद से दूर नहीं रखना चाहती हूं। इसलिए अपनी लाइफ में वर्क बैलेंस बनाकर रखा है। मैंने हमेशा अपनी गलतियों से सीखा है और अब मैं पूरी तरह से अलग इंसान बन चुकी हूं।

● **करीना कपूर**

वाक्युद्ध

मोदी सरकार ने देश में अघोषित आपातकाल लगा रखा है। सीबीआई और ईडी से विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है। न संसद में हमें बोलने दिया जा रहा है और न ही हमारी बातों को महत्व दिया जा रहा है। बेवजह का मुद्दा उछालकर संसद की कार्यवाही को बाधित किया जा रहा है।

● **मल्लिकार्जुन खड़गे**

कांग्रेस अध्यक्ष सबसे पहले अपने अंदर झांककर देखें। उनकी पार्टी के युवराज विदेश में जाकर भारत की छवि खराब कर रहे हैं। जहां तक सीबीआई और ईडी की बात है तो भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्यवाही तो होगी ही। जो भ्रष्टाचारी नहीं हैं उन्हें किस बात का डर। जो भ्रष्ट हैं वे ही ईडी का रोना रो रहे हैं।

● **स्मृति ईरानी**

क्या नाथ दिखाएंगे करिश्मा?

मप्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने मप्र में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कमलनाथ पार्टी का चेहरा होंगे। पहले भी इस तरह का मैसेज पार्टी की ओर से दिया जा चुका है कि मप्र में कांग्रेस पार्टी कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसी के साथ मप्र कांग्रेस के विरोधी दल के नेता और भाजपा ने अपनी-अपनी तलवारें भांजनी शुरू कर दी है। वैसे कमलनाथ को ऐसे राज्य में अपने नेतृत्व के लिए वस्तुत: कोई चुनौती नहीं मिली है, जहां कांग्रेस गुटबाजी के लिए कुख्यात है। कुछ साल पहले आपसी कलह इतनी बुरी थी कि राज्य की प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) को अलग-अलग पार्टी नेता के अलग-अलग प्रवक्ता रहे थे।

अब, राज्य कांग्रेस इकाई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नियमित रूप से कमलनाथ को भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं और ऐसे ही कई पोस्टर राज्य में समय-समय पर सामने आते रहे हैं। मप्र कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पिछले साल भोपाल में पीसीसी कार्यालय में आयोजित एक अनौपचारिक बैठक में कमलनाथ को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश करने का फैसला लिया गया था। हालांकि, इस निर्णय को आलाकमान द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी है। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा के पारिवारिक गढ़ से 76 वर्षीय कमलनाथ 9 लोकसभा चुनावों में जीत और दिसंबर 2018 और मार्च 2020 के बीच मुख्यमंत्री के रूप में एक अल्पकालिक कार्यकाल के बाद, कमलनाथ ने खुद को मप्र में कांग्रेस के शीर्ष नेता के रूप में स्थापित किया है। वरिष्ठता में उनके करीब आने वाले एकमात्र अन्य नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं। ग्वालियर के पूर्ववर्ती शाही परिवार के वंशज, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री पद के शीर्ष दावेदार थे, अब केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री हैं। मार्च 2020 में सिंधिया ने 22 कांग्रेस विधायकों के साथ भाजपा में जाने के बाद 15 महीने पुराने कमलनाथ प्रशासन की सरकार को गिरा दिया था, जिनमें से सभी उनके प्रबल समर्थक थे। इस बात को समझते हुए कि कमलनाथ एक वरिष्ठ नेता हैं, एक पूर्व राज्य पीसीसी प्रमुख ने बताया कि पीसीसी प्रमुख के रूप में कमलनाथ की वर्तमान स्थिति उन्हें कांग्रेस नेताओं के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाने की दौड़ में बढ़त देती है।

नाम न बताने की शर्त पर कांग्रेस के एक नेता बताते है, कमलनाथ सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। आज जैसी स्थिति है, हमें उनके नेतृत्व में काम करना है क्योंकि आलाकमान को उन पर भरोसा है और हमें यह आभास दिया गया है कि वे हमारे नेता होंगे। हम सभी ने मिलकर काम करने का फैसला किया है क्योंकि हमारा एजेंडा सत्ता में वापस आना है। अन्य मुद्दों को बाद में सुलझाया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि मप्र के प्रभारी कांग्रेस महासचिव जेपी अग्रवाल ने पिछले महीने कहा था कि पार्टी ने अभी तक राज्य में अपने मुख्यमंत्री चेहरे को अंतिम रूप नहीं दिया है। अग्रवाल ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को बराबरी पर रखते हुए मीडिया से कहा था, एक प्रक्रिया है जिसका कांग्रेस पार्टी वर्षों से पालन कर रही है। प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। एक बार जब टिकट बांट दिए जाते हैं और चुनाव लड़ा जाता है, तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारिणी और स्थानीय नेता क्या सोचते हैं।

वैसे इस समय पुनर्गठित पीसीसी टीम कमलनाथ के समर्थकों से भरी हुई है। 2018 में कमलनाथ के नाम का पीसीसी प्रमुख के रूप में प्रस्ताव रखने के साथ ही, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के चार कार्यकारी पीसीसी अध्यक्ष रहे थे। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, पांच साल बाद कमलनाथ को खुली छूट मिल गई और वे चार कार्यकारी अध्यक्ष अब कमलनाथ की अध्यक्षता वाली राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य हैं। समिति में उनके बेटे नकुलनाथ, दिग्विजय सिंह, मप्र विधानसभा में विपक्ष के नेता गोविंद सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी और अरुण यादव सहित अन्य शामिल हैं। जिला स्तर पर पार्टी के शीर्ष पदों के लिए चल रहे कुछ नामों को लेकर विरोध की सुगबुगाहट के बाद, अग्रवाल ने पिछले महीने कहा था कि कोई सूची अंतिम नहीं है। राजनीतिक गलियारों में यह सर्वविदित है कि कमलनाथ हमेशा नेहरू-गांधी परिवार के करीबी रहे हैं और अक्सर उन्हें अन्य राज्यों में संकट के समय पार्टी के संकटमोचन की भूमिका निभाने के लिए कहा जाता है। राज्य कांग्रेस के एक नेता ने दावा किया, जब सोनिया गांधी ने उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए बुलाया, तो मैं उनके साथ था, लेकिन कमलनाथ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, उनकी निगाहें मप्र पर हैं।

● **अरविंद नारद**

कमलनाथ लगातार सक्रिय

मप्र के ही एक राजनीतिक टिप्पणीकार का कहना था कि, कमलनाथ मप्र में एक सर्वोच्च कांग्रेस प्राधिकारी हैं और उन्होंने खुद को राज्य के अलावा कहीं और नहीं देखने की शर्त रखी है। वह कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, मेलजोल बढ़ा रहे हैं, उनकी वरिष्ठता को देखते हुए आलाकमान उन्हें भविष्य का मुख्यमंत्री घोषित करने वाले पोस्टरों के बारे में बताने के लिए नहीं कहेगा। हालांकि, उन्होंने कहा, इस तरह का अधिकार पार्टी के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि लोगों का दम घुटने लगता है और बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। कमलनाथ ने भले ही कई चुनाव लड़े और जीते हों, लेकिन उनके पास पूरे चुनाव की निगरानी के लिए स्थानीय समीकरणों और परिस्थितियों का व्यावहारिक अनुभव नहीं है। अगर वह किसी और के अनुभव पर भरोसा करते हैं तो उन्हें (जीत का) श्रेय नहीं मिलेगा। नाम की घोषणा आते ही मप्र कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। वेबकास्टिंग पार्टी की घटनाओं और कमलनाथ के भाषणों से लेकर, भाजपा नेताओं की टिप्पणियों का खंडन करने और राज्य में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की आलोचना करने के लिए मीम्स और डॉक्यूमेंट्री पोस्ट करने तक, पार्टी आक्रामक रही है।

आगामी विधानसभा चुनाव में विकास सबसे बड़ा मुद्दा होगा। इसलिए सत्ता और संगठन का पूरा फोकस विकास पर है। प्रदेश में सरकार ने विकास यात्रा निकालकर सभी 230 विधानसभा सीटों का सर्वे करवाया है, वहीं अपने विधायकों की परफॉर्मेंस का फीडबैक भी तैयार करवा रही है। इसी फीडबैक के आधार भाजपा के 127 माननीयों (वर्तमान विधायकों) का भविष्य तय होगा। यानी किसको टिकट मिलेगा और किसका टिकट कटेगा यह निर्णय लिया जाएगा।

फीडबैक पर टिका 127 माननीयों का भविष्य

आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की पूरी कोशिश है कि गुजरात की ही तरह जीत का रिकॉर्ड बनाया जाए। इसके लिए पार्टी के रणनीतिकारों ने 200 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य भी बनाया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए पार्टी सभी 230 सीटों पर मजबूत उम्मीदवार खड़ी करेगी। अपनी इसी रणनीति के तहत विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा मैदानी आंकलन के आधार पर आगे जमावट करेगी। इसके तहत विकास यात्राओं का भी फीडबैक लेना शुरू कर दिया गया है। इससे विधानसभा सीटों पर विधायकों, हारे नेताओं और मौजूदा मंत्रियों तक के फीडबैक को देखा जाएगा। भविष्य में इन्हीं फीडबैक के आधार पर निर्णय होंगे। दरअसल, भाजपा सभी 230 सीटों पर विकास यात्राओं के जरिए फीडबैक भी लेगी, जिससे आने वाले दिनों में संगठनात्मक कामों को लेकर जिम्मेदारियां देने के निर्णय किए जाएंगे। इसका दूरगामी असर टिकटों तक भी दिखेगा।

भाजपा ने 230 सीटों पर अपने सभी कार्यकर्ताओं को लगा दिया है। इसके तहत बूथ स्तर तक की भी रिपोर्ट बनेगी। इसमें विधायक व अन्य स्थानीय नेताओं को लेकर क्या स्थिति बनी इस पर निगाहें हैं। विकास यात्रा के बाद भाजपा का बूथ सशक्तिकरण अभियान चल रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अपने प्रवास व दौरे भी इन यात्राओं के बाद शुरू करेंगे। वहीं हर सीट पर भाजपा ने प्रभारी तैनात किए हैं। खासतौर पर हारी हुई 103 सीटों को लेकर सबसे ज्यादा गंभीरता है। भाजपा इन सभी सीटों की जरूरत व स्थानीय नेताओं के समन्वय के हिसाब से आगे टीम तैयार करेगी। गौरतलब है कि अब तक दो सर्वे टिकटों को लेकर हो चुके हैं। अब आगे तीसरा सर्वे भी होना है, लेकिन उसके पूर्व ही यात्राओं का फीडबैक भी रहेगा। पिछली बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद इस बार दावेदारी करने वाले नेताओं पर इस फीडबैक का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। खास बात ये कि जो बड़े चेहरे चुनाव हारे थे, उनमें से तो कुछ को स्थानीय प्रभाव के कारण टिकट मिल सकता है, लेकिन जो जद्दोजहद वाले चेहरे हैं उनके लिए फीडबैक मायने रखेगा। अभी संगठन के पास कई सीटों पर समन्वय में दिक्कत की शिकायतें हैं। इनसे जुड़े फैसलों पर भी फीडबैक असर डालेगा।

भाजपा सूत्रों के अनुसार जहां सरकार ने विकास की भरपूर सौगात दी है, वहीं विधायकों और नेताओं की लोकप्रियता का आंकलन भी कराया जा रहा है। जिन विधानसभा क्षेत्रों में इसका विरोध हो रहा है, वहां के विधायकों के बारे में मतदाताओं की राय और उनके कार्यों की जमीनी हकीकत का पार्टी पता लगाएगी। पार्टी यह भी देखेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह पार्टी की गुटबाजी का नतीजा है या फिर विरोध कांग्रेस प्रायोजित है। पार्टी को यदि यह जनविरोध लगा तो आगे प्रत्याशी बदलने के बारे में भी विचार किया जा सकता है। दरअसल, पार्टी मिशन-2023 के लिए किसी तरह का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है और न ही वह 2018 के चुनाव में टिकट देने से जुड़ी गलतियों को दोहराना चाहती है। पार्टी की तैयारी यह है कि सर्वे रिपोर्ट, विकास यात्रा की सफलता और कार्यकर्ताओं की सहमति से ही विधानसभा चुनाव का टिकट दिया जाए। इसी कारण संभावना है कि आने वाले चुनाव में भाजपा आधे से ज्यादा नए चेहरे उतार सकती है। विकास यात्रा में विधानसभावार विकास कार्यों का लेखा-

निर्णायक रणनीति तय की जाएगी

प्रदेश संगठन अपने स्तर पर सभी क्षेत्रों में निकलने वाली विकास यात्राओं का फीडबैक ले रहा है। इसके साथ ही जिलाध्यक्षों से भी कार्यकर्ताओं की सक्रियता को लेकर रिपोर्ट ली जा रही है। उसके बाद लगातार मैराथन बैठकों में निर्णायक रणनीति बनाई जाएगी। पार्टी ने 100 से अधिक हारी सीटों पर करीब छह महीने पहले प्रभारी तैनात किए थे। इन्हें आकांक्षी सीटों का नाम दिया गया था। इन प्रभारियों को इन सीटों पर हार के कारणों की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए कहा गया था। इन सीटों के प्रभारियों को भी बैठक में बुलाया गया है। इनसे सीटों के वर्तमान हालात का फीडबैक लिया जाएगा। बताया जाता है कि इन सीटों के कई प्रभारियों ने संगठन से कहा है कि अब उन्हें इस प्रभार से मुक्त कर दें। इनमें से अधिकांश प्रभारी खुद विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदार हैं। इनमें पूर्व विधायक और अन्य नेता शामिल हैं। अधिकांश पूर्व विधायक इस बार फिर दावेदारी ठोक रहे हैं। भाजपा का फोकस उन सीटों पर सबसे ज्यादा है जहां पिछले चुनाव में पांच हजार या उससे कम मतों से हार मिली थी।

जोखा तैयार किया गया है। इसके आधार पर भाजपा सदन से लेकर मैदानी स्तर तक कांग्रेस को घेरेगी। दरअसल, कांग्रेस विधानसभा के बजट सत्र में विभिन्न मुद्दे उठाकर और आरोप पत्र के माध्यम से सरकार को घेरकर इसकी शुरुआत कर दी है। सरकार ने विभागवार और विधानसभावार विकास कार्यों का लेखा-जोखा तैयार कराया था। इसे प्रभारी मंत्रियों के साथ-साथ संबंधित विधायक को भी उपलब्ध कराया गया था ताकि जब भी विपक्ष की ओर से कोई प्रश्न उठाया जाए तो उसका तथ्यात्मक उत्तर दिया जा सके और कई हद तक विधानसभा में हुई बहस में ये रणनीति काम भी आई। जानकारी के अनुसार विकास यात्रा की निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की गई। प्रत्येक जिले से प्रतिदिन प्रतिवेदन लिया गया। इसमें विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास के साथ विभिन्न योजनाओं के लिए प्राप्त आवेदन और उनके निराकरण की स्थिति ली गई।

भाजपा 8 महीने बाद मप्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण की गाइडलाइन तय करने की तैयारी कर रही है। पार्टी उम्रदराज और कई बार चुनाव जीत चुके नेताओं से पल्ला झाड़ने के बारे में भी विचार कर रही है। इसी तरह एक-दो या अधिक चुनाव में हार रहे चेहरों को प्रत्याशी बनाने से भी पार्टी परहेज कर सकती है। पार्टी लगभग 100 सीटों पर युवा और नए प्रत्याशियों की तलाश कर रही है। इसकी एक वजह यह भी है कि संगठन में पीढ़ी परिवर्तन के बाद विधानसभा चुनाव में भी नई पीढ़ी को मौका मिले। पार्टी के अपने अध्ययन में आगामी चुनाव को लेकर स्थितियां चुनौतीपूर्ण मानी गई हैं। टिकट की उक्त गाइडलाइन के अलावा जिन सीटों पर पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, वहां पहले प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। दरअसल, भाजपा सत्ता विरोधी रुझान से अवगत है। संगठन की रणनीति है कि विकास यात्रा के जरिए जिन विधायकों से जनता नाराज है, वहां के लोग मुखर होंगे। टिकट काटने का यह बड़ा आधार बन सकेगा। अगले चरण में इन सीटों पर मुख्यमंत्री और संगठन के बड़े नेता जाकर जन आक्रोश ठंडा कर सकेंगे। भाजपा के मिशन

2023 में गुजरात फॉर्मूले का साफ असर दिखाई पड़ेगा। दरअसल, 2018 में भी भाजपा ने पांच मंत्री सहित 52 विधायकों के टिकट काटे थे। इनमें कई कद्दावर भी शामिल थे। बाबूलाल गौर, सरताज सिंह, रामकृष्ण कुसमरिया, कन्हैया लाल अग्रवाल, हर्ष सिंह, सूर्यप्रकाश मीणा जैसे कई दिग्गज शामिल थे।

पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि विकास यात्रा भाजपा की जीत में मील का पत्थर बनेगी। इसलिए भाजपा के रणनीतिकारों ने विकास यात्रा पर पूरी तरह नजर गड़ाए रखी। भाजपा विकास यात्रा के आधार पर चुनावी रणनीति बनाएगी और फिर मैदानी मोर्चा संभालेगी। भाजपा ने 230 सीटों पर अपने सभी कार्यकर्ताओं को लगा दिया है। इसके तहत बूथ स्तर तक की भी रिपोर्ट बनेगी। इसमें विधायक व अन्य स्थानीय नेताओं को लेकर क्या स्थिति बनी इस पर निगाहें हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा मैदानी आंकलन के आधार पर आगे जमावट करेगी। इसके तहत विकास यात्राओं का भी फीडबैक लेना शुरू कर दिया गया है। इससे विधानसभा सीटों पर विधायकों, हारे नेताओं और मौजूदा मंत्रियों तक के फीडबैक को देखा जाएगा। भविष्य में इन्हीं फीडबैक के आधार पर निर्णय होंगे। दरअसल, भाजपा ने सभी 230 सीटों पर विकास यात्राओं के जरिए फीडबैक भी लिया है, जिससे आने वाले दिनों में संगठनात्मक कामों को लेकर जिम्मेदारियां देने में निर्णय किए जाएंगे। इसका दूरगामी असर टिकटों तक भी दिखेगा। वहीं विधानसभा चुनाव में भाजपा का खास फोकस महिला वोट बैंक पर है। लाडली बहना योजना के बाद अब नई आबकारी नीति में अहाते और स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थलों के पास शराब दुकाने प्रतिबंधित कर भाजपा ने महिलाओं को खुश करने का प्रयास किया है। शराब दुकानों को लेकर प्रदेश में कई जगह महिलाओं के प्रदर्शन होते रहते हैं। अब लाडली बहना योजना के साथ भाजपा कार्यकर्ता नई शराब नीति से होने वाले फायदे भी लोगों को बताएंगे। गौरतलब है कि 2008 के विधानसभा चुनाव में लाडली लक्ष्मी योजना भाजपा के लिए बेहद सहायक सिद्ध हुई थी।

विकास यात्रा के दौरान भाजपा प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों की स्कैनिंग भी करवा रही है। इसके तहत विधायकों और वर्तमान दावेदारों की स्थिति का आंकलन किया जा रहा है। पार्टी का सबसे अधिक फोकस हारी सीटों पर है। हर सीट पर भाजपा ने प्रभारी तैनात किए हैं। खासतौर पर हारी हुई 103 सीटों को लेकर सबसे ज्यादा गंभीरता है। भाजपा इन सभी सीटों की जरूरत व स्थानीय नेताओं के समन्वय के हिसाब से आगे टीम तैयार करेगी।

● **कुमार राजेन्द्र**

मंत्रियों से मिले फीडबैक से उत्साह

भाजपा सूत्रों का कहना है कि गत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में सभी मंत्रियों के साथ विकास यात्रा की समीक्षा की तो उसमें मिले फीडबैक से सत्ता और संगठन में उत्साह है। मंत्रियों ने अपने गृह जिले और प्रभार के जिलों की जानकारी दी। इन यात्राओं में विधायक, सांसद, मंत्री जिस तरह से जनता को लाभ दे रहे हैं उससे काफी सकारात्मक वातावरण बना है। भाजपा का संकल्प है कि ज्यादा से ज्यादा विकास पहुंचे। हर विधायक और मंत्री अपने-अपने जिलों में व्यापक स्तर पर जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 5 फरवरी से चल रही विकास यात्रा से विश्वास का वातावरण बना है। हमने जो कहा वह करके दिखाया है। कांग्रेस ने एक हजार रुपए पेंशन देने की बात कही थी लेकिन किसी को भी इसका लाभ नहीं मिला। कर्ज माफी हो या फिर किसानों के हित में उठाए जाने वाले अन्य कदमों के वादे भी पूरे नहीं किए। जबकि, हमने न केवल किसानों को सम्मान निधि दी बल्कि उनके कल्याण के लिए कई कार्यक्रम भी संचालित किए हैं। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने का काम किया गया है।

अमृत सरोवर निर्माण में मप्र ने मारी बाजी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल अमृत सरोवर ने प्रदेश में जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है। आजादी के 75वें वर्ष में लक्ष्य तो एक जिले में 75 सरोवर बनाने का था, लेकिन प्रदेश में इसकी उपयोगिता को देखते हुए पांच हजार से अधिक अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अमृत सरोवर बनाने में मप्र, देश का दूसरा बड़ा राज्य बन गया है। पहले स्थान पर उप्र है। प्रदेश में अब तक 2,657 अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं और इस साल के जून माह तक टारगेट के अनुसार सभी 5,372 सरोवरों का निर्माण पूरा हो जाएगा। यह सरोवर जल संरक्षण का काम तो करेंगे ही, किसानों की आय बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका निभाएंगे। दो लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा। वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मछली पालन और सिंघाड़ा की खेती भी होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का प्लान राज्यों को दिया था। माध्यम 75 का आंकड़ा इसलिए तय किया था कि देश आजादी का अमृत पर्व मना रहा है। देश में पानी बनाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में मप्र में वर्ष 2022-23 में टारगेट से अधिक 5,372 अमृत सरोवर बनाने का काम हाथ में लिया गया। सबसे ज्यादा सरोवरों का निर्माण ग्राम पंचायतों को गया है। अमृत सरोवर बनाने के पीछे बड़ा उद्देश्य है कि तालाबों में सिंघाड़ा की खेती के साथ मत्स्य पालन भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मप्र में बनाए गए अमृत सरोवर की तारीफ कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात में मंडला जिले में कान्हा-किसली ग्राम पंचायत के मोचा में बनाए गए अमृत सरोवर का उल्लेख करते हुए कहा था कि इससे जल और पर्यावरण संरक्षण होगा और वन्यजीव भी अपनी प्यास बुझाएंगे।

आजादी के अमृत महोत्सव काल में निर्मित किए जा रहे अमृत सरोवर जल संग्रहण के उद्देश्य के साथ-साथ स्थल विशेष से जुड़ी गौरव गाथाओं, इतिहास, विरासत, स्थानीय महान विभूतियों, धरोहरों, सामाजिक व धार्मिक आंदोलन, वैचारिक, संस्कृति व क्षेत्र की अन्य विशेषताओं को चिर स्थाई बनाने के लिए भी निर्मित किए जा रहे हैं। यह सरोवर पर्यावरण, जैव विविधता तथा पर्यटन के व्यापक उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी उपयोगी रहेंगे। इन जल संग्रहण के कार्यों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जा सकेगा। यह सरोवर आजादी के अमृत महोत्सव की स्मृति के साथ-साथ प्रदेश की समृद्धि एवं विकास के लिए शुरू किए गए एक नए अध्याय के रूप में भी जाने जाएंगे। प्रदेश में 5372 अमृत सरोवर के निर्माण कार्य प्रारंभ हुए, जिनमें से 2657 पूर्ण हो गए हैं। अमृत सरोवर निर्माण के लिए मप्र में योजना में केवल नवीन कार्य ही लिए गए और अंतर्विभागीय समन्वय पर भी जोर दिया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ जल-संसाधन, वन, मत्स्य विकास सहित नेशनल हाईवे अथॉरिटी एवं रेलवे जैसे संस्थान सहयोगी बने हैं। वित्तीय स्त्रोत के रूप में मनरेगा, वॉटर शेड विकास, 15वें वित्त आयोग और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की राशि का उपयोग किया गया। जन-सहभागिता से कार्य आसान हुए हैं। अमृत सरोवर निर्माण में जो जिले आगे हैं, उनमें छिंदवाड़ा, मुरैना, बैतूल, मंदसौर और बुरहानपुर शामिल हैं। सरोवर निर्माण में 4 हजार से अधिक पंचायत प्रतिनिधि, 5 हजार से अधिक पंचायत स्तरीय अधिकारी और सवा 2 हजार उपयोगकर्ता समूह सहभागी बने हैं। विकास आयुक्त मलय श्रीवास्तव का कहना है कि वर्ष 2022-23 में 5,372 अमृत सरोवर बनाने का टारगेट हाथ में लिया गया। इनमें 2,657 पूरे हो चुके हैं। हम निर्माण करने में देश में दूसरे स्थान पर हैं। शेष बचे सरोवरों का निर्माण इस साल जून माह तक पूरा कर लेंगे। वर्ष 2023-24 में नए अमृत सरोवर बनाने का प्लान नहीं है।

अमृत सरोवरों पर 3 हजार 955 फ्लैग पोस्ट बनी हैं। जहां स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर ध्वज फहराने का कार्य भी हुआ है। यही नहीं सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों के नाम 63 अमृत सरोवर समर्पित किए गए हैं। इसी तरह ऐतिहासिक महत्व के 116 स्थान के निकट सरोवर बनाए गए हैं। प्रदेश में धार्मिक महत्व के 231 स्थान के निकट और जैव विविधता-संरक्षण की दृष्टि से 342 अमृत सरोवर निर्मित हुए हैं। बहुउद्देशीय आर्थिक लाभ के लिए भी सरोवर चिन्हित किए गए हैं। मत्स्य उत्पादन में 2409, सिंघाड़ा उत्पादन में 1505 और पर्यटन के उद्देश्य से 199 सरोवर का उपयोग किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान के अंतर्गत 43 हजार से अधिक जीर्ण-शीर्ण तालाबों का भी जीर्णोद्धार होगा। इस संरचनाओं के जीर्णोद्धार पर लगभग 1100 करोड़ रुपए व्यय होंगे। प्रारंभ में 37,651 तालाबों का चयन किया गया था, लेकिन इसमें वर्तमान में केवल 27 हजार 710 तालाबों का ही जीर्णोद्धार किया जा सका है। शेष 9,941 जीर्ण-शीर्ण तालाबों का जीर्णोद्धार अब तक अधूरा है। 37,651 तालाबों से 28 हजार 933 तालाबों का चयन सिंचाई कार्य के लिए किया है। 6,439 तालाबों में मत्स्य पालन और दो हजार 164 तालाबों में सिंघाड़ा उत्पादन किया जाएगा।

● **जितेंद्र तिवारी**

क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं अमृत सरोवर

जहां एक तरफ अमृत सरोवरों का निर्माण हो रहा है, वहीं कई जिलों में सरोवर क्षतिग्रस्त भी हो रहे हैं। बैतूल के चिचोली ब्लॉक के आलमपुर में 44 लाख रुपए की लागत से बनाया गया अमृत सरोवर पहली बारिश भी नहीं झेल पाया और फूट गया। यहां के रिटेनिंग वॉल का 10 से 15 फीट हिस्सा फूटा था। हालांकि सबसे अधिक सरोवर बनाने के मामले में बैतूल जिला प्रदेश में टॉप-5 में शामिल है। सिवनी जिले के घंसौर की ग्राम पंचायत पहाड़ी के निचली गांव में तेज वर्षा के कारण अमृत सरोवर योजना के तहत बना अधूरा तालाब फूट गया था। डिंडोरी जिले में बना अमृत सरोवर पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया। बुरहानपुर जिले के खकनार तहसील के ग्राम नागझिरी में पंचायत द्वारा बनाया गया अमृत सरोवर फूट गया जिससे कुछ किसानों की फसल प्रभावित हुई। दमोह जिले के हटा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत दमोतीपुरा के ग्राम सूरजपुरा में बनाए गए अमृत सरोवर के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली थी। इसका कारण मूसलाधार बारिश का होना बताया गया।

अगस्त से पहले भोपाल आएंगे मेट्रो के कोच

3248 करोड़ में खरीदेंगे कोच

मेट्रो प्रोजेक्ट का काम भोपाल-इंदौर में तेज गति से चल रहा है। दोनों जगह अगस्त-सितंबर में ट्रायल रन का लक्ष्य रखा गया है। पिछले दिनों एल्स्टॉम ट्रांसपोर्ट इंडिया को भोपाल-इंदौर मेट्रो में लगने वाले 156 कोच यानी डिब्बों का ठेका दिया गया, जिसकी राशि 3248 करोड़ होती है। इसमें कंपनी 15 साल तक रखरखाव के साथ सिग्नलिंग और ट्रेन नियंत्रण और दूर संचार प्रणालियों का भी 7 साल तक रखरखाव करेगी। 31 अगस्त तक 3-3 कोच की 1-1 मेट्रो ट्रेन भोपाल और इंदौर पहुंच जाएगी। मप्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी मनीष सिंह ने कार्यभार संभालने के बाद दोनों जगह प्रोजेक्टों के निर्माण की गति बढ़वा दी, ताकि मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप अगस्त-सितंबर में ट्रायल रन हो सके। इंदौर में मेट्रो ट्रेन के प्रायोरिटी कॉरिडोर जो कि साढ़े 5 किलोमीटर लंबा है उस पर ट्रायल रन लिया जाना है। लिहाजा अभी जो पटरियों की खेप इंदौर पहुंची है उसे डिपो और प्रायोरिटी ट्रैक पर बिछाने की तैयारियां भी जोर-शोर से जारी हैं। दूसरी तरफ रेलवे कोच को तैयार करवाने का काम भी कंपनी की फैक्ट्री में शुरू हो रहा है।

मप्र के दो बड़े शहर भोपाल और इंदौर में दौड़ने वाली मेट्रो ट्रेन के कोच (बोगियां) गुजरात में बनेंगे। फ्रांस की एल्सटॉम ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड कोच बनाएगी। मेट्रो ट्रेन सेट की यूनिट की 13 मार्च से शुरुआत हुई। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यूनिट का भोपाल से वर्चुअली शुभारंभ किया। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कंपनी के अधिकारियों से कहा कि मेट्रो की डेटलाइन तय है। 31 अगस्त तक भोपाल में ट्रायल पूरा करना है। इससे पहले कोच भोपाल ले आएं। मंत्री सिंह पहले बड़ोदरा जाकर यूनिट का शुभारंभ करने वाले थे, लेकिन वे नहीं जा सके। इसलिए भोपाल से ही वर्चुअली यूनिट की शुरुआत की गई। 31 अगस्त तक 3 कोच की एक ट्रेन भोपाल आएगी। इंदौर में भी इतने ही कोच की ट्रेन आएगी। भोपाल-इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। मेट्रो यूनिट के शुभारंभ के बाद पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि मेट्रो का भूमिपूजन कांग्रेस ने किया था। दिसंबर-2023 या जनवरी-2024 को कांग्रेस ही मेट्रो का लोकार्पण करेगी। मेट्रो कांग्रेस की देन है। मेट्रो का सफर कांग्रेस सरकार में शुरू होगा।

अभी मप्र शासन ने जो अपना सालाना बजट पेश किया उसमें 710 करोड़ रुपए मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए रखे गए हैं, जिसमें से इस वर्ष 20 फीसदी शेयर आवंटन किए जाएंगे, यानी 142 करोड़ रुपए की राशि शासन देगा। जबकि 20 फीसदी का शेयर केंद्र सरकार से मिलेगा, जिससे दोनों प्रोजेक्टों को गति मिलेगी। पहली खेप में 6 कोच भोपाल-इंदौर को ट्रायल रन के लिए मिलेंगे। भोपाल में 6.22 किमी और इंदौर में 5.9 किमी लंबे मेट्रो रूट का काम चल रहा है। भोपाल में सितंबर तक मेट्रो दौड़ने और इंदौर में ट्रायल किए जाने का टारगेट है। भोपाल में पिलर और गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो चुका है। अब मेट्रो स्टेशन और पटरी बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। इंदौर में भी काम की रफ्तार तेज कर दी गई है। ताकि, विधानसभा चुनाव से पहले मेट्रो दिखाई देने लगे।

जानकारी के अनुसार, 1400 करोड़ रुपए में एल्सटॉम ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी भोपाल के लिए 81 और इंदौर के लिए 75 बोगियां बना रही हैं। ये बोगियां कई मायने में खास होंगी। एक ट्रेन सेट में तीन बोगी होंगी। इसमें 970 यात्री सफर कर सकेंगे। एल्सटॉम बोगियों को ऐसे तैयार कर रही हैं, ताकि भीड़ बढ़ने पर भी यात्री आसानी से सफर कर सकें। हर कोच 2.9 मीटर चौड़ा और 22 मीटर लंबा होगा। कंपनी ने यात्रियों का जो कैलकुलेशन किया है, उस हिसाब से एक वर्ग मीटर में 8 यात्री होंगे। इनमें खड़े और बैठने वाले यात्री शामिल हैं। इस हिसाब से एक बोगी को 970 यात्रियों लायक बनाया जा रहा है।

एम्स से सुभाष नगर अंडरब्रिज तक 8 स्टेशन एम्स, अलकापुरी, डीआरएम ऑफिस, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, डीबी सिटी, एमपी नगर जोन-1, आयकर भवन और सुभाषनगर अंडरब्रिज में बन रहे हैं। कुछ स्टेशनों का काम दिखाई देने लगा है तो कुछ का काम अभी काफी बाकी है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और डीबी सिटी जैसे चहल-पहल वाले स्थानों पर फुटओवर ब्रिज बनेंगे। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट का तीसरा बड़ा काम डिपो का है, जो 323 करोड़ रुपए से सुभाषनगर अंडरब्रिज के पास स्टड फॉर्म की 26.41 हेक्टेयर (65.26 एकड़) जमीन पर बनाया जा रहा है। यहां एक साथ 4 मेट्रो ट्रेन खड़ी हो सकेंगी। यहां न केवल मेट्रो का रखरखाव होगा, बल्कि कंट्रोलिंग सिस्टम भी यहीं होगा। सिग्नलिंग, कम्युनिकेशन, पावर सप्लाई सबकुछ यहीं से होगा। एम्स से सुभाषनगर का रूट बनने के बाद सुभाषनगर से करोंद के बीच यानी बाकी के 9.83 किलोमीटर मेट्रो रूट का काम होगा। इस रूट पर 39 एकड़ से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। अलग-अलग लोकेशन की लगभग 8 एकड़ जमीन पर 5 प्लाजा, 6 स्टेशन, 4 पार्किंग, 2 यार्ड बनेंगे। पुराने शहर में अतिरिक्त पार्किंग व्यवस्था पर फोकस है। पुल बोगदा के पास मेट्रो का जंक्शन बनेगा, यहां दोनों लाइनें आकर मिलेंगी। पुल बोगदा से मेट्रो अंडरग्राउंड हो जाएगी। पहला अंडरग्राउंड स्टेशन मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ बनेगा। जहां ईरानी डेरे की जमीन ली गई है। नादरा बस स्टैंड का मेट्रो स्टेशन भी अंडरग्राउंड रहेगा। इंदौर मेट्रो ट्रेन प्रायोरिटी कॉरिडोर में गांधीनगर से लेकर रेडिसन-रोबोट चौराहे तक का काम तेजी से चल रहा है। इसकी लंबाई 17.2 किलोमीटर है, जिसमें 5.9 किमी का काम पहले पूरा होगा। 11.6 किमी का काम बाद में होगा। गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर के बीच में 5 किलोमीटर रूट पर सितंबर 2023 में मेट्रो ट्रेन चलाकर ट्रायल किया जाएगा। इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने में फिलहाल अधिकारी जुटे हैं। गांधीनगर से रेडिसन स्टेशन तक कुल 17.2 किमी के 16 स्टेशन प्राथमिकता में है। गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर तक 5 किलोमीटर में सितंबर तक 6 स्टेशन का काम पूरा करने का प्लान है। फरवरी-मार्च 2024 तक सबके लिए मेट्रो ट्रेन शुरू होने की उम्मीद है।

● **प्रवीण सक्सेना**

अलग-अलग राज्य का मुद्दा गर्माया

चुनावी साल में मप्र में आदिवासी राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। भाजपा और कांग्रेस सहित लगभग हर पार्टी की कोशिश है कि वे आदिवासी वोटबैंक को अपनी ओर कर ले। इसके लिए तरह-तरह के उपक्रम किए जा रहे हैं। वहीं पार्टियों का रूझान देखते हुए आदिवासी समाज के अंदर अलग भील प्रदेश की चाह उठने लगी है। आदिवासियों की मंशा को भांपकर जय आदिवासी युवा शक्ति (जयस) ने इस मुद्दे को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल कर लिया है। इससे यह संकेत मिल रहे हैं कि आगामी चुनाव में भील प्रदेश चुनावी मुद्दा बनेगा।

गौरतलब है कि प्रदेश में लंबे समय से अलग बुंदेलखंड और विंध्य प्रदेश की मांग उठ रही है। जब भी चुनाव होते हैं यह मुद्दा गरमा जाता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड और विंध्य प्रदेश के साथ ही अलग भील प्रदेश की मांग भी जोर पकड़ सकती है। जयस ने हाल में इसे अपने एजेंडा में शामिल करने की घोषणा की है। प्रदेश के लिए ये मांग नई है पर गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में भील समाज दशकों से अलग भील राज्य की मांग पर अड़ा हुआ है। महाराष्ट्र और मप्र के कई जिले भी इस प्रस्तावित राज्य का हिस्सा हैं।

जयस के नेताओं का दावा है कि अलग भील प्रदेश की मांग करने वालों की आबादी 3 करोड़ से अधिक की है। चार राज्यों के संयुक्त आदिवासी क्षेत्र को मिलाकर इस कल्पित राज्य में मप्र (21.1 प्रतिशत), गुजरात (14.8 प्रतिशत), राजस्थान (13.48 प्रतिशत), और महाराष्ट्र (9.35 प्रतिशत) आबादी आती है। प्रस्तावित भील प्रदेश में मप्र, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुल 39 जिले शामिल हैं। जिसमें मप्र के रतलाम ग्रामीण, धार, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन और खंडवा जैसे इलाके शामिल हैं। जनजातीय क्षेत्रों में चल रही जयस की आदिवासी अधिकार यात्रा में अन्य मांगों के अलावा इस मांग को भी शामिल किया गया है। जयस पदाधिकारियों के मुताबिक धार, झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर आदि में जमीनी स्तर पर जनजातीय समाज इस मांग से जुड़ चुका है। जयस के कार्यकारी अध्यक्ष रविराज बघेल ने कहा कि संगठन इस मांग से सहमत है और जल्द ही इसे जयस के एजेंडा में शामिल किया जाएगा। संगठन का आधार मालवा-निमाड़ क्षेत्र में अधिक है जहां सबसे बड़ी संख्या भिलाला समुदाय की है, उसके बाद बारला और भील समुदाय का नंबर आता है। इस क्षेत्र में भील प्रदेश संगठन भी अस्तित्व में है।

भील जनजाति गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में रहती है। भील वंश को लोग महाभारत के चरित्र एकलव्य से जोड़कर देखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि भी भील थे। जयस का कहना है कि दूरस्थ आदिवासी गांवों तक सरकार की पहुंच नहीं होती है। कई गांवों तक विकास नहीं पहुंचा। अधिकारी गांवों का नाम तक नहीं जानते हैं। हर साल वादा किया जाता है लेकिन विकास गांव तक नहीं पहुंचता है। प्रशासनिक और सरकारी उपेक्षा की वजह से आदिवासी समुदाय प्रभावित है। इसको देखते हुए जयस आदिवासियों को संगठित करने की कोशिश में यह पार्टी जुटी हुई है। जयस की यह मांग है कि बीते 75 साल में आदिवासियों के लिए अलग से कुछ नहीं हुआ है। अगर ऐसे में भील प्रदेश बन जाता है तो उनके लिए क्या काम हुआ है इसकी सटीक जानकारी मिल सकती है।

शहडोल, रीवा, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया और कटनी के कुछ हिस्सों को मिलकर विंध्य क्षेत्र माना जाता है। अलग छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड राज्य बनने के समय तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस सरकार ने एनडीए सरकार को एक संकल्प पारित करके विंध्य प्रदेश के लिए भेजा था पर केंद्र ने इसे खारिज कर दिया था। इसी तरह मप्र और उप्र के बुंदेलखंड क्षेत्र में आने वाले जिलों को मिलाकर अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग भी बहुत पुरानी है।

वहीं चुनावी वर्ष में अलग महाकौशल राज्य की मांग उठने लगी है। महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी ने अलग महाकौशल राज्य की मांग उठाई है। पार्टी का कहना है कि महाकौशल विकास के मामले में लगातार पिछड़ता जा रहा है। सालों से महाकौशल की उपेक्षा हो रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सतीश नागजी के मुताबिक 24 जिलों को मिलाकर महाकौशल राज्य की घोषणा की जा सकती है। इन जिलों में जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, पन्ना, कटनी, दमोह, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, होशंगाबाद आदि जिले शामिल किए जा सकते हैं।

● **लोकेंद्र शर्मा**

25 जिलों को मिलाकर बने रेवाखंड

प्रदेश में कुछ सामाजिक संगठन विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड के 25 जिलों को मिलाकर रेवाखंड की मांग कर रहे हैं। रेवाखंड राज्य की मांग करने वालों का कहना है कि आजादी के बाद से इन क्षेत्रों को महत्व नहीं मिला। इसलिए यहां का विकास अवरुद्ध है, जबकि प्राकृतिक रूप से यह इलाका बहुत समृद्ध है। लौह अयस्क, लाइम स्टोन, तांबा, जस्ता, बाक्साइट, हीरा, फास्फेट और कोयला के बड़े भंडार मौजूद हैं। जंगल और अकूत जलस्रोत भी हैं, लेकिन क्षेत्र के विकास को लेकर कांग्रेस-भाजपा दोनों ने चिंता नहीं की। 67 फीसदी शुद्धता वाला लौह अयस्क है, लेकिन प्लांट नहीं लगाया गया। बेहतरीन गुणवत्ता वाला हीरा है, लेकिन पॉलिशिंग और कटिंग के लिए गुजरात पर निर्भर हैं। अगले विधानसभा चुनाव तक प्रस्तावित 25 जिलों में पूरी ताकत के साथ आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर जनता का भरोसा जीतेंगे और सरकार को अलग राज्य बनाने के लिए राजी करेंगे। जबलपुर हाईकोर्ट के कार्यक्षेत्र को आधार मानकर रेवाखंड का नक्शा बनाया गया है। हाईकोर्ट के कार्यक्षेत्र में 28 जिले हैं, जिनमें से भोपाल, रायसेन व सीहोर को अलग रखा गया है। प्रस्तावित रेवाखंड के अंतर्गत प्रदेश के 5 संभाग सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और होशंगाबाद के 25 जिलों को जोड़ा गया है। इनमें सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, नरसिंहपुर, कटनी, डिंडौरी, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली इसमें शामिल हैं।

मप्र में बिछेगा फ्लाईओवर का जाल

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मप्र को फ्लाईओवरों की सौगात दी थी। उनका निर्माण अब सेतुबंध योजना के तहत कराया जा रहा है। 9 शहरों में 17 फ्लाईओवर एमआरडीसी यानी मप्र सड़क विकास निगम करवाएगा। इन फ्लाईओवरों के निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और टेंडर भी जारी किए जा रहे हैं। दरअसल जिन शहरों में ये फ्लाईओवर बनना है वहां अतिक्रमण से लेकर ओवरब्रिज निर्माण में कुछ बाधाएं भी हैं, जिन्हें स्थानीय प्रशासन, निगम की सहायता से हटवाया जाएगा।

एमपीआरडीसी के एमडी आशीष सिंह के मुताबिक इन 17 फ्लाईओवरों के निर्माण से शहरों के यातायात को सुगम करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने इन फ्लाईओवरों के लिए एक हजार करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। भोपाल के अलावा इंदौर, सागर, ग्वालियर, खंडवा, विदिशा और धार में ये फ्लाईओवर बनाए जाना है। इंदौर में देवास नाका चौराहा पर जो फ्लाईओवर बनेगा उसकी लंबाई लगभग 600 मीटर होगी, तो इतनी ही लंबाई का फ्लाईओवर सत्यसांई चौराहे पर और तीसरा फ्लाईओवर आईटी चौराहा और चौथा मूसाखेड़ी चौराहा पर बनना है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी केंद्रीय सड़क अधोसंरचना निधि से इन फ्लाईओवरों के लिए शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता राशि की मांग की थी, जिसके चलते सेतु बंधन योजना के तहत इन फ्लाईओवरों को मंजूरी दी गई है।

ये फ्लाईओवर शहरों के सबसे व्यस्ततम और भीड़-भाड़ वाले चौराहों में बनाए जाएंगे। इनके निर्माण के लिए मप्र सड़क विकास निगम डीपीआर तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया है। निर्माण कार्य अगले वर्ष से शुरू होने की संभावना है। इन चौराहों और मार्गों से प्रतिदिन करीब 20 हजार से अधिक वाहन गुजरते हैं। पीक ऑवर में यहां जाम जैसे स्थिति बन जाती है। सभी 9 शहरों में फ्लाईओवर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने करीब एक हजार करोड़ रुपए जारी किए हैं। इनकी चौड़ाई करीब 7 मीटर से ज्यादा होगी, जबकि लंबाई अलग-अलग है। डीपीआर बनने के बाद निर्माण कार्यों की लागत राशि बढ़ने की संभावना है। डीपीआर बनाने एमपीआरडीसी ने एजेंसियों को 3 से 4 माह का समय दिया है। इसके बाद निर्माण लागत और फ्लाई ओवर 600 मीटर होगी। की लंबाई का वास्तविक आंकलन किया जा सकेगा। फ्लाईओवर कहां बनेंगे, इसका निर्धारण कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। डीपीआर तैयार होने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। कई शहरों में जहां फ्लाईओवर बनाया जाना प्रस्तावित है, वहां अतिक्रमण और निजी भूमि पर भवन और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स हैं। निर्माण एजेंसी को भूमि खाली कराने में करीब 6 माह और साल भर का समय लग सकता है। एमपीआरडीसी के एमडी आशीष सिंह का कहना है कि सेतुबंधन योजना के तहत 9 शहरों में फ्लाईओवर तैयार करने का काम एलएंडटी को दिया गया है। जल्द ही इनके निर्माण के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे।

भोपाल व्यापमं चौराहे से 6 नंबर बस स्टाप तक फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 540 मीटर होगी। अयोध्या बायपास से करोंद तक फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 600 मीटर होगी। काली परेड से अयोध्या तक छोला आरओबी बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 600 मीटर होगी। इंदौर देवास नाका चौराहे पर फ्लाई ओवर बनाया जाएगा, सत्य साई चौराहे पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 590 मीटर, आईटी चौराहे पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा, लंबाई 595 मीटर होगी। मुसाखेड़ी चौराहे पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 590 मीटर, सागर सिविल लाइन से मकरोनिया चौराहे तक फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 650 मीटर होगी। सोनार नदी से गदेरी नदी तक सागर-दमोह मार्ग पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा, लंबाई 700 मीटर होगी। ग्वालियर पुराना कम्पू बस स्टैंड से गोरखी महाराज बाड़ा तक फ्लाई ओवर होगा, जिसकी लंबाई 1000 मीटर होगी। वहीं महलगांव और हरिशंकरपुम के बीच अंडर पास निर्माण होगा, इसकी लंबाई 30 मीटर होगी। मोहना रेलवे स्टेशन के पास फ्लाईओवर का निर्माण होगा, जिसकी लंबाई 445 मीटर होगी। खंडवा गणेश गौशाला चौराहा से पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 600 मीटर होगी। विदिशा सागर-विदिशा मार्ग पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 800 मीटर होगी। थार महू घाटा बिल्लौद स्टेट हाइवे क्रमांक 38 इंडो रामा चौरहे पर 4 लेन फ्लाईओवर बनाई जाएंगी, जिसकी लंबाई 600 मीटर होगी।

● **राकेश ग्रोवर**

क्वालिटी कंट्रोल बहुत जरुरी

मप्र के शहरों और कस्बों में सड़कों के मेंटेनेंस के लिए अब आर्थिक संकट बाधा नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश के 413 निकायों को सड़कों की मरम्मत के लिए 750 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पहली किश्त के तौर पर मुख्यमंत्री ने 350 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर भी कर दी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा, हमारे हाईवे तो सारे चकाचक हो गए, लेकिन शहर के अंदर की सड़कें, वार्डों की सड़कें ठीक नहीं हैं। कई जगह ये शिकायत मिलती थी कि मरम्मत नहीं हो रही है। सड़कों की मरम्मत की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों की होती है। बाकी सड़कें शानदार और वार्ड में उड़ रही धूल, तो सुबह-सुबह लोग पार्षद को ही पकड़ेंगे। पहली बार राज्य के बजट से सड़कों की मरम्मत के लिए पैसा दिया है। 750 करोड़ में से 350 करोड़ खातों में डाले हैं। मुख्यमंत्री ने सभी निकायों के अधिकारियों से कहा, 15 से 20 दिन में टेंडर की प्रोसेस पूरी हो जानी चाहिए। मई में काम खत्म करना है। इसके बाद बारिश आ जाएगी। मंत्री और अधिकारी इसका ध्यान रखें। कोई इस चक्कर में न पड़े कि ये ठेकेदार आ जाए, पहचान का आए, तो बहुत अच्छा। इस सब में न पड़ें। सही एजेंसी का चयन हो जाए। क्वालिटी कंट्रोल बहुत जरूरी है। डामर चुपड़ दिया, बाद में वो उखड़ गया, ऐसा न हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पेयजल, सीवेज की लाइन डालने के बाद सड़क खोद दी जाती है। इसके लिए जरूरी है कि सड़कें रीस्टोरेशन का काम भी किया जाए। जेसीबी से सड़क खोदकर लोग निकल जाते हैं। सड़क कटर से कटनी चाहिए और उसका रीस्टोरेशन होना चाहिए।

मप्र में बीते तीन वर्षों के दौरान स्टार्टअप की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 2018 तक करीब 1700 स्टार्टअप हुआ करते थे, जो अब बढ़कर 2500 से ज्यादा हो गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1400 स्टार्टअप इंदौर में हैं। जबलपुर और ग्वालियर में भी स्टार्टअप 400 से ज्यादा हो गए हैं। प्रदेश में स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की कोशिश में कई तरह के प्रमोशन किए जा रहे हैं। स्टार्टअप नीति भी तैयार हुई है। जिसका फायदा युवाओं को हो रहा है।

युवा बन रहे आत्मनिर्भर

भारत विश्व में स्टार्टअप्स 'हॉटस्पॉट' के रूप में उभरा है। आज देश में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं। वहीं अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में मप्र स्टार्टअप हब बन रहा है। मप्र देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है, जो स्टार्टअप्स के लिए विश्व स्तरीय ईको सिस्टम प्रदान करते हैं। मप्र सरकार की स्टार्टअप फ्रेंडली नीतियों के परिणाम स्वरूप प्रदेश स्टार्टअप्स का हब बन रहा है। मप्र देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है, जो स्टार्टअप्स के लिए विश्व स्तरीय ईको सिस्टम प्रदान करते हैं। स्टार्टअप ब्लिंक की रिपोर्ट के अनुसार देश में इंदौर 14वें स्थान पर और भोपाल 29वें स्थान पर है। मप्र के 2500 से अधिक स्टार्टअप भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में पंजीकृत हैं। इनमें से 1100 से अधिक स्टार्टअप महिला उद्यमियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में 45 से अधिक इनक्यूबेटर्स प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप को विकसित करने के लिए सतत् कार्यरत हैं। केंद्र सरकार का कपड़ा परिधान मंत्रालय का इनक्यूबेशन सेंटर ग्वालियर में है।

देश में स्टार्टअप आंदोलन को गति देने और आत्मनिर्भर मप्र के रोडमैप 2023 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने मप्र स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2022 शुरू की है। इससे मप्र के मौजूदा ईको सिस्टम को और बेहतर बनाने के साथ ही जनता के बीच उद्यमिता और नवाचार की भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है। योजना का उद्देश्य स्टार्टअप रैंकिंग में राज्य को अग्रणी बनाना है। इसके लिए योजना में स्टार्टअप और इन्क्यूबेटर के लिए सिंगल विंडो एजेंसी स्थापित करते हुए मप्र स्टार्टअप सेंटर (एमपीएससी) स्थापित किया गया है। एमपीएससी स्टार्टअप को सदस्यता देता है और मंजूरी पाने और पूंजी जुटाने में सहायता करता है।

मप्र की स्थापना के 67 साल बाद ही सही प्रदेश का औद्योगिक परिवेश अब लगातार और बेहतर हो रहा है। बेहतरी की इसी कड़ी में नया आयाम है, राज्य सरकार द्वारा राज्य में स्टार्टअप्स के लिए एक जीवंत और अनुकूल ईको सिस्टम विकसित करने की प्रतिबद्धता। पिछले कुछ समय में ही मप्र को युवाओं, निवेशकों और भारत सरकार से लगातार मिले समर्थन से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप गतिविधियों में आशा से अधिक वृद्धि देखी गई है। प्रदेश में वर्ष 2016 में डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त सिर्फ 7 स्टार्टअप थे, अब डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त लगभग 2584 से अधिक स्टार्टअप प्रदेश में हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इनमें 44 फीसदी से अधिक स्टार्टअप की प्रवर्तक महिलाएं हैं। मप्र के स्टार्टअप्स एरोनॉटिक्स, रक्षा, कृषि, एआई, एनीमेशन, फैशन, फिन-टेक, खाद्य प्र-संस्करण जैसे विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत है। इन स्टार्टअप में शीर्ष 5 क्षेत्र आईटी परामर्श, निर्माण और इंजीनियरिंग, कृषि-तकनीक, खाद्य प्र-संस्करण, व्यवसाय सहायता सेवाएं प्रमुख हैं। प्रदेश के अधिकांश स्टार्टअप ने पिछले 6 वर्षों में धीरे-धीरे आईडीएशन स्टेज से अपनी यात्रा

अब नौकर नहीं, मालिक बनने का जुनून

स्टार्टअप की संख्या के मामले में प्रदेश का नाम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस लिहाज से देश के टॉप 10 नगरों में इंदौर का भी नाम शामिल हो गया है। स्टार्टअप की संख्या नगर में अचानक बढ़ी है। 2020 तक करीब 300 स्टार्टअप हुआ करते थे, लेकिन जनवरी 2023 तक यह संख्या करीब 800 हो गई है। इस वर्ष की शुरुआत में स्टार्टअप के लिए पहली बार बड़े स्तर पर कार्यक्रम कराने के दौरान पता लगा कि कई स्टार्टअप घरों में शुरू हो गए हैं। अब इनका डाटा तैयार किया जा रहा है। सबसे ज्यादा आईटी क्षेत्र के स्टार्टअप संचालित हो रहे हैं और अब तेजी से इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए भी युवा आगे आ रहे हैं। पीथमपुर में ई-वाहन बनाने के लिए तीन बड़ी परियोजनाएं नगर के युवाओं ने शुरू की हैं। इसमें से एक ई-फाई स्टार्टअप ने खुद से 5 करोड़ रुपए का निवेश किया। पहले तक एक जैसे आईडिया पर काम करने वाले स्टार्टअप अब नवाचार को बढ़ा रहे हैं। इन्वेस्ट इंदौर के सचिव सावन लड्ढ़ा का कहना है कि 800 स्टार्टअप में से करीब 100 ऐसे स्टार्टअप हैं, जिनका निवेश 10 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कुछ स्टार्टअप 1 हजार से 2 हजार करोड़ रुपए तक के बन गए हैं। 2 ऐसे स्टार्टअप भी हैं, जिनका निवेश 6 हजार करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। शहर में आईटी क्षेत्र में काम करने वाले 250 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। इनमें से कई की शुरुआत कोरोना महामारी के दौरान हुई है। दुनियाभर में ऑटोमेशन की मांग बढ़ने से आईटी क्षेत्र में बूम की स्थिति है।

शुरू करने के बाद आज सफल व्यवसाय स्थापित कर महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। प्रदेश का स्टार्टअप ईको सिस्टम अब मप्र स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के नियमों के तहत काम करने लगा है। पॉलिसी का क्रियान्वयन एमएसएमई विभाग कर रहा है। विभाग अपने स्टार्टअप ईको सिस्टम के विकास के लिए डीपीआईआईटी और स्टार्टअप इंडिया के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। डीपीआईआईटी द्वारा जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग के दोनों संस्करण में मप्र अग्रणी रहा है। यही नहीं राज्य के स्टार्टअप ईकोसिस्टम की और भी कई उपलब्धियां रही हैं। स्टार्टअप से जुड़े सभी हितधारकों जैसे स्टार्टअप, इन्क्यूबेटर, सेंटर, निवेशक, स्टार्टअप पार्टनर, राज्य सरकार और मप्र स्टार्टअप सेंटर को स्टार्टअप पोर्टल से जोड़ा गया है।

मप्र स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2022 का उद्देश्य स्टार्टअप रैंकिंग में राज्य को अग्रणी बनाना है। इसके लिए योजना में स्टार्टअप्स और इन्क्यूबेटर्स के लिए सिंगल विंडो एजेंसी स्थापित करते हुए मप्र स्टार्टअप सेंटर (एमपीएससी) स्थापित किया गया है। एमपीएससी स्टार्टअप्स को मेंटरशिप प्रदान करता है और मंजूरी पाने और पूंजी जुटाने में भी सहायता करता है। एमपीएससी कई स्त्रोतों से मार्केट इंटेलीजेंस एकत्र कर ईकोसिस्टम प्लेयर्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। मार्केट इंटेलीजेंस का उपयोग सरकार की गतिविधियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए किया जाता है, जो राज्य की आगामी नीतियों के लिए उपयोगी साबित होगा। प्रदेश सरकार ने 21 स्टार्टअप को 20 लाख रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस सहायता का उपयोग नए बाजारों में प्रवेश करने, उत्पाद विकास, व्यवसायों को बढ़ाने और कई अन्य मामलों के लिए किया जा रहा है। सहायता न केवल मौद्रिक शर्तों पर बल्कि कंपनी की मार्केटिंग एवं प्रमोशन के लिए भी प्रदान की जाती है। राज्य सरकार 5 भारतीय एआईएफ (वैकल्पिक निवेश कोष) में 10 करोड़ रुपए का निवेश करने की भी योजना बना रही है, जो राज्य के स्टार्टअप में कई गुना निवेश करेगा।

मप्र के 2500 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हैं। इनमें से 1100 से अधिक स्टार्टअप महिला उद्यमियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को अतिरिक्त सहायता भी प्रदान करती है। प्रदेश में वर्ष 2016 में डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त सिर्फ सात स्टार्टअप थे, अब डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त लगभग 2584 से अधिक स्टार्टअप प्रदेश में हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इनमें 44 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप की प्रवर्तक महिलाएं हैं। मप्र के स्टार्टअप एरोनाटिक्स, रक्षा, कृषि, एआई एनिमेशन, फैशन, फिन-टेक, खाद्य प्रसंस्करण जैसे विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत है। इन स्टार्टअप में शीर्ष पांच क्षेत्र आईटी परामर्श, निर्माण और इंजीनियरिंग, कृषि-तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, व्यवसाय सहायता सेवाएं प्रमुख हैं। जहां के इंदौर में भारत का सबसे बड़ा चाय स्टार्टअप में स्थित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 8 महीनों में मप्र में महिला स्टार्टअप की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। राज्य में इस समय कुल 2597 स्टार्टअप हैं। इसमें 1143 (44.01 प्रतिशत) महिलाएं हैं। खास बात ये है कि 8 महीने पहले इनकी संख्या 800 थी। जो बढ़कर 1143 हो गई है। इसमें 43 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अभी भी प्रदेश में पुरुषों के स्टार्टअप की संख्या महिलाओं के स्टार्टअप से 6 फीसदी ज्यादा है।

महिलाओं के स्टार्टअप में ग्रोथ के कारण की बात करें तो इसमें ये कारण भी हो सकता है कि सरकार को पुरुषों की तुलना में महिलाओं को 20 प्रतिशत अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करना होती है। बता दें कि इन सभी स्टार्टअप्स को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से मान्यता मिली है। साथ ही साथ महिला स्टार्टअप में सरकार ने 578 करोड़ रुपए का निवेश किया है। बता दें कि मप्र सरकार ने 49 इन्क्यूबेशन सेंटर खोले हैं। जहां महिलाओं को मार्केटिंग और स्टार्टअप से जुड़ी जानकारियां और गुण सिखाए जा रहे हैं। महिलाओं में नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है। वो किस तरह पूरे घर को संभालती हैं। साथ ही साथ कई महिलाएं तो ये दोनों काम करती हैं। यही खूबी उन्हें बिजनेस में सबसे अलग बनाती है। जिसके कारण स्टार्टअप को मैनेज करने की उनकी क्षमता अच्छी होती है और लोगों के साथ उनका व्यवहार अच्छा होता है। बता दें कि सरकार ने कई स्टार्टअप्स को प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आमंत्रित किया है। जिसमें मार्केट, रिसर्च, इनोवेशन और आईटी सेक्टर के स्टार्टअप शामिल हैं। इसमें महिलाओं के स्टार्टअप भी हैं। स्टार्टअप को दफ्तर के साथ कम्प्यूटर, इंटरनेट, कांफ्रेंस हाल और अन्य सुविधाएं भी तैयार करके दिए जा रहे हैं।

● **सुनील सिंह**

स्टार्ट अप नीति सरल और आसान

मप्र का स्टार्टअप ईकोसिस्टम विभिन्न क्षेत्र के स्टार्टअप के वर्गीकरण के साथ विकसित हुआ है। राज्य सरकार ने इसके लिए एक स्वतंत्र निकाय का गठन किया है। नई नीति में स्टार्टअप के लिए कई प्रक्रियाओं को सरल और आसान बनाया गया है। सार्वजनिक खरीद को आसान बनाने से लेकर नई स्टार्टअप नीति में इन्क्यूबेटरों को ज्यादा समर्थन की पेशकश की गई है। प्रदेश की नीति के प्रमुख तत्वों में से एक प्रदेश के स्टार्टअप सेंटर की स्थापना है। यह सेंटर राज्य के स्टार्टअप को सुविधाएं और जरूरी सहायता देगा। सेंटर राज्य में स्टार्टअप तंत्र को बढ़ावा देने, उन्हें मजबूत करने और सुविधा देने के लिए एक समर्पित एजेंसी के रूप में काम करेगा। मप्र की स्टार्टअप नीति 2022 की अनेक विशेषताएं हैं, जो इसे देश में अलग पहचान देती है। संस्थागत रूप से विषय-विशेषज्ञों के साथ मप्र स्टार्टअप सेंटर की स्थापना, मजबूत ऑनलाइन पोर्टल का विकास, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से जरूरी शैक्षणिक सहायता का आदान-प्रदान का प्रावधान नीति की विशेषताएं हैं। वित्तीय सहायता के रूप में नीति में सेबी, आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों से सफलतापूर्वक निवेश प्राप्त करने पर 15 प्रतिशत की दर से अधिकतम 15 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। यह सहायता अधिकतम 4 बार दी जाएगी। इसी तरह महिलाओं के स्टार्टअप के लिए 20 प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान है।

3000 अरब का खजाना

जम्मू के रियासी जिले में मिले लिथियम के बड़े भंडार की जल्द नीलामी करने की सरकार ने तैयारी कर ली है। इस भंडार का ऑक्शन अप्रैल-जून तिमाही में करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए जल्द ही सरकार बोलियां आमंत्रित करेगी। दरअसल, बोली की प्रक्रिया इतनी जल्दी शुरू करने की वजह है कि लिथियम के भंडार के बारे में सरकार को पूरा भरोसा है। अगर ये लिथियम के मिलने के शुरुआती संकेत होते तो जरूर पुख्ता प्रमाण मिलने तक सरकार इंतजार करती। लेकिन यहां पर मिले भंडार को लेकर किसी तरह का संशय नहीं है, लिहाजा सरकार इसकी नीलामी जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश में है।

नीलामी को लेकर सरकार की योजना है कि ये आमतौर पर अपनाई जाने वाली नीलामी प्रक्रिया की तरह सभी के लिए ओपन रहेगी। इसमें कोई भी बोली लगा सकता है। हालांकि बोली जीतने वाले को लिथियम का इस्तेमाल भारत में ही करना होगा। लेकिन फिलहाल भारत में लिथियम रिफाइनिंग की प्रक्रिया मौजूद नहीं है। ऐसे में इस भंडार से लिथियम निकालना भी एक चुनौती होगी। देश में मिले लिथियम भंडार की कुल क्षमता 59 लाख टन है जो दुनिया का सातवां सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। भारत से आगे बोलिविया, अर्जेंटीना, अमेरिका, चिली, ऑस्ट्रेलिया और चीन हैं। लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल है, जिसका इस्तेमाल मोबाइल-लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत कई आइटम्स के लिए चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। इस रेअर अर्थ एलिमेंट के लिए भारत अभी दूसरे देशों के भरोसे है। फिलहाल चीन में एक टन लिथियम की कीमत करीब 51,19,375 रुपए है, जबकि भारत में जो खजाना मिला है, उसमें 59 लाख टन लिथियम मिलने की संभावना है। इस हिसाब से उसकी कीमत करीब 3000 अरब रुपए आंकी गई है।

भारत के लिए ये खोज बड़ी करामाती साबित होने जा रही है। अभी तक भारत में जरूरत का 96 फीसदी लिथियम आयात किया जाता है। इसके लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 में लिथियम ऑयन बैटरी के आयात पर 8,984 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके अगले साल यानी 2021-22 में भारत ने 13,838 करोड़ रुपए की लिथियम ऑयन बैटरी इम्पोर्ट की थीं। भारत लिथियम का सबसे ज्यादा आयात चीन और हांगकांग से करता है। साल दर साल आयात की मात्रा और रकम में जोरदार इजाफा हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक भारत 80 फीसदी तक लिथियम का चीन से आयात करता है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस बढ़ाने के बाद से भारत लिथियम आयात करने के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर रहा है। लिथियम का भंडार मिलने और इसकी नीलामी होने के बावजूद लिथियम ऑयन बैटरी का निर्माण करना आसान नहीं होगा। दरअसल, लिथियम का उत्पादन और रिफाइनिंग एक बेहद मुश्किल काम है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक की जरूरत होगी। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि 7.9 मिलियन टन भंडार वाले ऑस्ट्रेलिया में लिथियम का खदान उत्पादन 69 हजार टन है। वहीं चिली में 11 मिलियन टन भंडार के बावजूद महज 39 हजार टन का उत्पादन हो पाता है। ऐसे में भारत के लिए इस भंडार से उत्पादन करना आसान नहीं है। भारत अगर अपने भंडार से लिथियम उत्पादन में कामयाब हो जाता है तो फिर ग्राहकों को फायदा मिल सकता है। इससे इलेक्ट्रिक बैटरी सस्ती हो सकती है जिससे इलेक्ट्रिक कारें ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। दरअसल, इलेक्ट्रिक कारों की कीमत में करीब 45 फीसदी हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक कारों में लगे बैटरी पैक की होती है। उदाहरण के तौर पर नेक्सन ईवी में लगे बैटरी पैक की कीमत 7 लाख रुपए है जबकि इस कार की कीमत करीब 15 लाख रुपए है।

भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत में चलने वाली 30 प्रतिशत निजी कारें, 70 प्रतिशत कमर्शियल वाहन और 80 प्रतिशत टू-व्हीलर्स इलेक्ट्रिक हो जाएं। जाहिर है इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत में लिथियम ऑयन बैटरी का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। लेकिन ये केवल लिथियम का भंडार मिलने से मुमकिन नहीं होगा। इसके लिए लिथियम का इस्तेमाल बैटरी निर्माण में करना जरूरी है। इसके लिए भारत को चीन से सीखने की जरूरत है। चीन ने 2030 तक 40 फीसदी इलेक्ट्रिक कारों का लक्ष्य तय किया है। दुनियाभर में इस्तेमाल होने वाली हर 10 लिथियम बैटरी में से 4 का इस्तेमाल चीन में होता है। इसके उत्पादन में भी चीन दूसरों से आगे है। दुनियाभर के लिथियम बैटरी के कुल उत्पादन का 77 फीसदी चीन में होता है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए चीन ने 2001 में ही योजना तैयार कर ली थी। 2002 से ही उसने इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण की योजना में निवेश शुरू कर दिया था।

अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा लिथियम ऑयन बैटरी का आयात होता है। अमेरिका में करीब 1.65 लाख, भारत में 1.54 लाख और तीसरे नंबर पर मौजूद वियतनाम में 75 हजार लिथियम ऑयन बैटरी का आयात किया गया। भारत में सबसे ज्यादा बैटरी आयात चीन, जापान और वियतनाम से होता है। अब इस मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत को एक तकनीक विकसित करनी होगी जिससे वो देश में लिथियम ऑयन बैटरी का उत्पादन कर सके। 2030 तक के लक्ष्य के मद्देनजर भारत को सालाना 1 करोड़ लिथियम ऑयन बैटरी का उत्पादन करने की जरूरत होगी।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

20 साल से ईवी पर काम कर रहा चीन

चीन ने फैक्ट्रियां बनाने के साथ ही ये भी तय कर लिया था कि कच्चे माल की कमी ना हो। इसके लिए उसने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में लिथियम के खनन में निवेश किया। चीन के निवेश का नतीजा ये निकला कि टेस्ला और एप्पल समेत दूसरी कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रियां चीन में लगाईं। चीन ने 20 साल पहले ईवी की रणनीति पर काम शुरू कर दिया था जबकि 10 साल पहले तक यानी 2012 में दुनियाभर में करीब 1 लाख 30 हजार इलेक्ट्रिक कारों की ही बिक्री हुई थी। 2020 तक ये आंकड़ा बढ़कर 30 लाख और 2021 में 66 लाख पर पहुंच गया। अनुमान है कि 2035 तक दुनिया की सड़कों पर चलने वाली आधी गाड़ियां इलेक्ट्रिक कारें होंगी। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कारों का कुल बाजार 100 अरब डॉलर से ज्यादा का होगा। ऐसे में भारत को भी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत होगी। इस खोज के पहले आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत को 2030 तक लिथियम ऑयन बैटरी के लिए 10 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत होगी।

नदियों की हालात जस की तस

मप्र के लिए वाटर पॉल्यूशन भी चुनौती बन रहा है। दिनों-दिन प्रदूषित होते भूजल के कारण भविष्य में पीने के पानी का संकट नजर आ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक मप्र से गुजरने वाली 22 नदियां जल प्रदूषण की शिकार हैं। चार नदियों चंबल, बेतवा, क्षिप्रा और कान्ह नदी का पानी तो आचमन करने के लायक भी नहीं है। राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग कार्यक्रम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नदियों में वॉटर क्वालिटी की मॉनीटरिंग करता है। आपको बताते हैं कि कौन सी नदी मप्र के किस इलाके में सबसे ज्यादा प्रदूषित हो रही है।

मप्र की गिनती देश में तीसरे ऐसे राज्य के तौर पर होती है जहां की नदियां सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। गत दिनों देशभर के वैज्ञानिक और विशेषज्ञों ने राजधानी में आकर नर्मदा के संरक्षण को लेकर बात जरूर की, लेकिन हकीकत यह है कि नर्मदा के अलावा भी 21 ऐसी नदियां है जो प्रदूषित हो चुकी हैं। यह खुलासा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट से हुआ है। देश में तमाम ऐसी छोटी व सहायक नदियां जो प्रदूषण के चलते अपना अस्तित्व खो चुकी हैं, ऐसी नदियों के लिए केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने नीति तैयार की है। इस नीति के तहत जनभागीदारी के साथ इन नदियों को **पुर्नजीवत करने की योजना बनाई** है। रिपोर्ट के अनुसार मप्र में जो नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं उनमें बेतवा, बैनगंगा, क्षिप्रा, बंजार, बिचिया, चंबल, चिल्लर, देनवा, गोहद, गौर, जैमर, कलीसोट, खान, कोलार, मालेई, कुंदा, नर्मदा, पार्वती, शिवना, ताप्ती, टोंस शामिल हैं। नदियों के प्रदूषण की मुख्य वजह इनमें सीवेज छोड़ा जाना है। इनमें से क्षिप्रा, ताप्ती, बेतवा नदी तो अपना लगभग अस्तित्व ही खो चुकी हैं। इस बात को खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मान चुके हैं।

वर्ष 2018 में एनजीटी की प्रिसिंपल बेंच के निर्णय के अनुसार मप्र में चित्रकूट की मंदाकिनी सहित 22 प्रदूषित नदी क्षेत्र घोषित किए गए थे। इनमें पाया गया था कि शुष्क मौसम में नदियों का बहाव अपने औसत बहाव का 15 से 20 फीसदी भी नहीं रह जाता है। इससे नदियों का ई-फ्लो (इन्वायरमेंट फ्लो) प्रभावित होता है। एनजीटी का आदेश था कि इस तरह की व्यवस्था की जाए कि इन नदियों का ई-फ्लो बना रहे। पांच साल बाद अब एनजीटी ने इस दिशा मे किए गए काम की विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जरिए प्रस्तुत करने राज्य सरकार को निर्देशित किया है। राज्य सरकार ने इन चिन्हित 22 नदियों में ई-फ्लो बनाने रखने के लिए नदी पुनरुद्धार समिति गठित की थी। समिति के निर्णयों का पालन कराने जनवरी 2020 में जलसंधान विभाग के ईई को संबंधित नदियों का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। अब एनजीटी द्वारा रिपोर्ट चाहे जाने पर जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता ने नोडल अधिकारियों से ई-फ्लो के संबंध में किए गए कामों की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

सतना जिले की मंदाकिनी नदी के नोडल अधिकारी ईई जल संसाधन सतना बनाए गए थे। इनका काम था कि पुनरुद्धार के लिए एक्शन प्लान तैयार कर नदी पुनरुद्धार समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन कराना। लेकिन जब ईई आरएस नट से इस संबंध में चर्चा की गई तो उन्होंने 2020 में नोडल अधिकारी बनाए जाने की जानकारी से ही इंकार कर दिया। वे वर्तमान ई-फ्लो की जानकारी भी नहीं दे सके। बताया कि एसडीओ को कहा गया है कि वे एक्शन प्लान बनाएंगे।

ई-फ्लो को पर्यावरणीय प्रवाह कहा जाता है। किसी नदी व उसके किनारे का पारिस्थितिकीय तंत्र सही रखने सहित पानी को ताजा बनाए रखने के लिए नदी में आवश्यक जल की मात्रा, अवधि, आवृत्ति व गुणवत्ता युक्त बहाव पर्यावरणीय प्रवाह कहा जाता है। एनजीटी के अनुसार नदियों का जो ई-फ्लो तय किया गया है वह एवरेज लियन सीजन फ्लो का 15 से 20 फीसदी ई-फ्लो बनाए रखना है। सामान्य भाषा में समझे तो गर्मी के मौसम में भी नदी में इतना पानी बहते रहना चाहिए कि उसकी शुद्धता बनी रहे और जलीय जीव जंतुओं का पारिस्थितिकीय तंत्र न बिगड़े। ईई जल संसाधन आरएस नट ने बताया कि नर्मदा जल को मंदाकिनी में मिलाने के लिए प्लान तय किया गया है। इसके लिए दौरी सागर बांध में नर्मदा जल डाला जाएगा। यहां से मंदाकिनी नदी में जनवरी माह के बाद 5 क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड की दर से पानी छोड़ा जाएगा। जिससे इसका अनवरत प्रवाह बना रहेगा। ई-फ्लो नदी में बांध बना देने से प्रभावित होता है। इसके अलावा पानी की धारा को पूर्ण या आंशिक तौर पर मोड़ने से, वनों की कटाई और नदी जलग्रहण क्षेत्र बाधित करने से, जलग्रहण क्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में खनन करने से, नदी के तल पर रेत खनन करने से और नदी मे प्रदूषित मल, जल और गंदगी मिलाने से नदी का ई-फ्लो प्रभावित हो रहा है।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

मंडीदीप से विदिशा तक बेतवा का जल सबसे प्रदूषित

शहरों के सीवेज और उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी नदियों की सेहत बिगाड़ रहा है। मप्र में 22 नदियां ऐसी हैं, जिनका जल प्रदूषित है। इन नदियों में बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) का स्तर ज्यादा है। भोपाल के करीब से गुजरने वाली बेतवा नदी का जल मंडीदीप से विदिशा तक सबसे ज्यादा प्रदूषित है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग कार्यक्रम की बीते 31 मार्च की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में कान्ह नदी, बेतवा, चंबल और क्षिप्रा नदियों में बीओडी की मात्रा खतरनाक स्तर पर है।

तेंदूपत्ता संग्राहकों के लाभांश पर राजनीति

2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मप्र की शिवराज सरकार प्रदेश के 40 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को साड़ियां, जूते-चप्पल, छाता और पानी की बोतलें देने की तैयारी में है। इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वनमंत्री विजय शाह को दी है। प्रदेश सरकार द्वारा मप्र लघु वनोपज संघ के माध्यम से जंगल क्षेत्र में तेंदूपत्ता संग्रह करने वाले आदिवासियों एवं परंपरागत वन निवासियों को इस साल साड़ियां, जूते-चप्पल, छाता और पानी की बोतल बांटने को लेकर प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा- 2017-18 में हमने यह योजना शुरू की थी। बीच में दूसरी सरकार आई, जिसने यह योजना बंद कर दी। लेकिन हम इसे फिर से चालू करेंगे।

मप्र की भाजपा सरकार इस तरह से जहां आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं विपक्ष ने आदिवासियों-परंपरागत वन निवासियों के लघु वनोपज के हक के पैसे यानी लघु वनोपज के शुद्ध लाभ की राशि लगभग 261 करोड़ रुपए का बंदरबांट करने का आरोप लगाया है। मप्र के मनावर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक आदिवासी नेता डॉ. हिरालाल अलावा ने मप्र के राज्यपाल को पत्र लिखकर इस संबंध में अपना विरोध दर्ज कराया है। डॉ. अलावा ने पत्र में लिखा है- लघु वनोपज पर ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत को भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून-1996 एवं वन अधिकार कानून 2006 में नियंत्रण, प्रबंधन सहित समस्त अधिकार सौंपे गए हैं। इसके संबंध में मप्र शासन वन विभाग द्वारा 15 मई, 1998 को जारी आदेश के तहत लघु वनोपजों के व्यापार से प्राप्त लाभांश राशि, जो वर्तमान में लगभग 1500 करोड़ से भी ज्यादा है, को प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से संग्राहकों को नकद वितरित की जानी थी। लेकिन मप्र लघु वनोपज सहकारी संघ लघु वनोपज के व्यापार से प्राप्त लाभांश की राशि का सन् 1998 से लगातार दुरुपयोग करते रहा है। अत: लघु वनोपज के लाभांश की राशि से सामग्री क्रय कर वितरित किए जाने की कार्यवाही को तत्काल रोका जाए और 15 मई, 1998 के आदेशानुसार नकद राशि संग्राहकों को वितरित किया जाए।

मप्र लघु वनोपज के अंतर्गत आने वाले तेंदूपत्ते का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बीड़ी बनाने के काम में आने वाले ये पत्ते जंगल क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों-परंपरागत वन निवासियों को सर्वाधिक मौसमी आय उपलब्ध कराते हैं। लघु वनोपज आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासी समुदायों के जीवनयापन का हमेशा से मुख्य आधार रहा है। संविधान की 11वीं अनुसूची, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम-1996 तथा वनाधिकार अधिनियम-2006 के तहत सभी तरह के लघु वनोपज पर समस्त अधिकार, नियंत्रण एवं प्रबंधन ग्राम सभा को सौंपा गया है एवं वन विभाग को इन नियंत्रणों से मुक्त कर दिया गया है। इसके अनुसार 15 मई, 1998 को वन विभाग मंत्रालय मप्र शासन ने मप्र लघु वनोपज सहकारी संघ को आदेश दिया कि लघु वनोपज के व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ की संपूर्ण राशि प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को प्रदान की जाएगी। उक्त सहकारी समितियां वनोपज के शुद्ध लाभ की संपूर्ण राशि का 50 प्रतिशत संग्राहकों को नकद वितरित करेंगी, 25 प्रतिशत राशि ग्रामीण विकास कार्यों पर खर्च करने और शेष 25 प्रतिशत राशि वन विकास कार्यों पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। जनवरी, 2006 में इसमें आंशिक संशोधन कर संग्राहकों की राशि 60 प्रतिशत, ग्रामीण विकास और वन विकास मद की राशि 20-20 प्रतिशत राशि तथा फरवरी 2012 में पुन: संशोधन कर संग्राहकों की राशि 70 प्रतिशत, ग्रामीण विकास और वन विकास मद की राशि 15-15 प्रतिशत खर्च करने का प्रावधान कर दिया गया। लेकिन मप्र लघु वनोपज संघ सन् 1998 से ग्रामीण विकास एवं वन विकास मद की 50, 40 और 30 प्रतिशत की राशियों को आज तक प्राथमिक सहकारी समितियों को नहीं दिया और उक्त राशियों को मनमाने ढंग से खर्च करता रहा है। अब उसी राशि में से सामग्रियां खरीदने व वितरित करने के मामले में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी है।

13 जनवरी, 2023 को वन विभाग के अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया की अध्यक्षता में मप्र लघु वनोपज संघ के संचालक मंडल की बैठक में 261 करोड़ रुपए के साड़ियां, जूते-चप्पल, छाता, पानी की बोतल की क्वालिटी, डिजाइन और खरीदी की मंजूरी दे दी गई। बैठक में कहा गया कि 2022 में तेंदूपत्ता जमा करने का काम करने वाले कार्डधारी संग्राहकों को ही ये सामग्री दी जाएगी। संग्राहकों के 15 लाख 24 हजार परिवारों को 285 रुपए वाली पानी की बोतल एवं 200 रुपए वाला छाता दिया जाएगा, जबकि परिवार के एक पुरुष को 291 रुपए का जूता एवं एक महिला को 195 रुपए की चप्पल दी जाएगी, जबकि परिवार की सभी 18 लाख 21 हजार महिला सदस्यों को 402 रुपए वाली साड़ी वितरित की जाएगी। जीएसी, परिवहन एवं वितरण पर 40 करोड़ 51 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे।

● **विकास दुबे**

पिछली बार बांटे थे चरणपादुका

ज्ञात हो कि वर्ष 2018 में राज्य विधानसभा चुनाव के पूर्व भी चरण पादुका योजना के तहत 261 करोड़ रुपए की सामग्री तेंदूपत्ता संग्राहक आदिवासियों-परंपरागत वन निवासियों को बांटकर लुभाने का प्रयास किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने बांटे गए जूतों से कैंसर फैलने की बात उठाकर माहौल को गरमा दिया था। संग्राहकों के पक्ष में उतरे विधायक डॉ. अलावा का आरोप है कि ग्रामीण विकास मद की लगभग 1,000 करोड़ और वन विकास मद की 500 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि मप्र लघु वनोपज सहकारी संघ ने प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को उपलब्ध नहीं करवाई और उस राशि का दुरुपयोग कर अपव्यय करता रहा है।

खेती में आमदनी बढ़ाने की चुनौती

60 फीसदी आबादी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खेती से जुड़ी हुई है। मगर विकास की भरपूर संभावना वाला कृषि क्षेत्र हमेशा से उपेक्षा का शिकार रहा है। कृषि को अभी तक सरकारें सिर्फ देश की जनता का पेट भरने का साधन मानती आई हैं। इसके माध्यम से देश की जीडीपी बढ़ाने पर कभी गहन मंथन नहीं हुआ। इस समय किसानों की स्थिति में भले कुछ परिवर्तन नजर आता हो, पर इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। गौरतलब है कि 2016 में केंद्र सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, जब देश अपनी आजादी के पचहत्तर साल पूरे करेगा। यह ठीक है कि सरकार का इस दौरान पूरा ध्यान पैदावार और किसानों की आमदनी बढ़ाने पर रहा है। वह कृषि क्षेत्र को पटरी पर लाने में जुटी है। यह कोशिश सिर्फ उत्पादन के लक्ष्यों तक सीमित नहीं है। अन्य कई मोर्चों पर भी पहल की जा रही है। आय बढ़ाने से जुड़े अभियान में उत्पादन को ऊंचे स्तर पर ले जाने, जुताई का खर्च घटाने और फसल का मूल्य बढ़ाने पर जोर है, ताकि किसानों को ज्यादा मुनाफा मिल सके। इस दृष्टि से कई योजनाएं शुरू की गई हैं और नीतिगत स्तर पर भी काफी सुधार हुए हैं। साथ ही, इन योजनाओं को वित्तीय मदद मुहैया कराने के लिए कृषि क्षेत्र से जुड़े बजटीय आवंटन में बढ़ोतरी की गई है। मगर किसानों की आय दोगुनी होने का लक्ष्य अब भी काफी पीछे है। अब तो वह समय सीमा भी खत्म हो रही है, जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी।

मार्च 2022 में कृषि पर बनी संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में दो सर्वेक्षणों के आंकड़े बताए थे, जो 2015-16 और 2018-19 के थे। इनके आधार पर संसदीय समिति ने बताया था कि 2015-16 में देश के किसानों की महीने की औसत आमदनी 8059 रुपए थी, जो 2018-19 तक बढ़कर 10,218 रुपए हो गई। यानी चार साल में महज 2159 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। किसानों की आमदनी अगर बढ़ी है, तो खर्च भी बढ़ रहा है। पिछले साल नवंबर में सरकार ने बताया था कि किसान हर महीने 10,218 रुपए कमाते हैं, तो 4,226 रुपए खेती पर खर्च हो जाते हैं। किसान हर महीने 2959 रुपए बुआई और खाद-पानी पर और 1267 रुपए पशुपालन पर खर्च करता है। यानी, किसानों के हाथ में छह हजार रुपए भी नहीं आते। इसी में उसे अपना घर चलाना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई, मां-बाप की दवाई, सबकुछ उसे उन्हीं पैसों में करना पड़ता है। छह हजार रुपए होते क्या हैं, यह सब जानते हैं। इतनी कम कमाई के चलते ही किसान कर्ज लेने को मजबूर हो जाता है। सबसे ज्यादा कमाई मेघालय के किसानों की है। वहां के किसान की हर महीने की आमदनी 29,348 रुपए है। दूसरे स्थान पर पंजाब है, जहां के किसान 26,701 रुपए महीना कमाते हैं। तीसरे स्थान पर 22,841 रुपए की कमाई के साथ हरियाणा के किसान हैं। देश में 4 राज्य ऐसे हैं जहां किसानों की आमदनी कम हो गई है। वे हैं- झारखंड, मप्र, ओडिशा और नगालैंड।

झारखंड के किसानों की हर महीने की कमाई 2173 रुपए कम हो गई है। वहीं, नगालैंड के किसानों की आमदनी 1551 रुपए, मप्र के 1400 रुपए और ओडिशा के किसानों की आमदनी 162 रुपए घट गई है। किसान को यूं तो देश का अन्नदाता कहा जाता है, मगर हकीकत यह है कि वह अपना पेट भरने के लिए जिंदगी भर संघर्ष करता रह जाता और कभी-कभी इतना मजबूर हो जाता है कि उसके सामने आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाता है।

आजकल किसानों को ऋण बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, पर फसल बर्बाद होने पर उस कर्ज की भरपाई कैसी की जाए इसका कोई उपाय किसानों के पास नहीं होता और न ही सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाती है। इसलिए किसानों का जीवन बहुत अधिक सुखद नहीं माना जा सकता। संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि सरकार को एक विशेष टीम बनानी चाहिए, जो इन राज्यों में किसानों की घटती आमदनी के कारणों का पता लगाए। इन राज्यों को सही कदम उठाने का सुझाव भी दिया है। इन साक्ष्यों से स्पष्ट है कि किसानों के हालात अब भी दयनीय बने हुए हैं। इसलिए किसानों की स्थिति सुधारने और आय को बढ़ाने के लिए भगीरथ प्रयास की जरूरत है। देश की दो तिहाई जनसंख्या ग्रामीण है।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

खेती पर लागत 8.9 फीसदी बढ़ी

खाद, बिजली, डीजल के दाम को एक साथ जोड़ें तो खेती पर लागत पहले के मुकाबले 8.9 फीसदी बढ़ गई है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने खेती पर लागत बढ़ने संबंधी रिपोर्ट इस साल मई में जारी की थी। उसमें कहा गया था कि 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में खेती पर लागत बीस फीसदी तक बढ़ गई। यह रिपोर्ट उपभोक्ता मांग पर आधारित थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि महंगाई बढ़ने से कंपनियों की आमदनी में तो इजाफा होगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से उत्पाद की मांग कम होगी, क्योंकि किसानों के पास उत्पाद खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा। खेती से उनकी आमदनी इसलिए नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि खेती पर लागत बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों से कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एकमात्र चमकता क्षेत्र रहा है। खेती समग्र अर्थव्यवस्था की विकास दर का भार उठा रही है। कोरोना महामारी के दौरान भी, कृषि क्षेत्र ने उत्पादन और निर्यात के मोर्चे पर आशा के संकेत दिखाए। ऐसे में यह साफ हो जाना चाहिए कि आने वाले समय में खेती-किसानी ही अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत रहेगी। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना होगा। 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हासिल करने के लिए कृषि विकास दर का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर चढ़ना जरूरी है। इसके लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण को अभी और कारगर प्रयासों की जरूरत है। कृषि क्षेत्र जितना मजबूत और फायदेमंद होगा, देश उतना मजबूत होगा। खेती के प्रति लोगों की उत्सुकता और लगाव बढ़ाने की जरूरत है, ताकि खेती अगली पीढ़ी के लिए आकर्षक बने और खेती करने वालों को खेती के लिए रोका जा सके।

वन सुरक्षा में मप्र फिसड्डी

मप्र के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30.72 फीसदी वन क्षेत्र है। 94,689 वर्ग किमी क्षेत्रफल में से आरक्षित वन 61,886 वर्ग किमी (65 फीसदी), संरक्षित वन 31098 वर्ग किमी (33 फीसदी) और अवर्गीकृत वन 1705 वर्ग किमी (2 फीसदी) है। प्रदेश सरकार हर साल करीब 24 अरब रुपए जंगलों की सुरक्षा और वनों के विकास पर खर्च करती है। इसके बाद भी सूबे में जंगलों का क्षेत्रफल न केवल लगातार कम होता जा रहा है, बल्कि जंगलों का घनत्व भी कम होता जा रहा है। इसकी वजह है वनों की अवैध कटाई पर लगाम नहीं लग पाना। इसकी बड़ी वजह है वन विभाग के अमले की लापरवाही। अगर सरकारी आंकड़ों को देखें तो हर साल प्रदेश में औसतन 43 हजार से अधिक मामले जंगलों में अवैध कटाई के दर्ज होते हैं। यह कटाई सभी 16 वृत्तों और नेशनल पार्क में की जाती है। इस मामले में सबसे खराब हालात जबलपुर वन वृत्त की बनी हुई है। इस वृत्त में प्रदेश में सबसे अधिक प्रकरण दर्ज होते हैं, जो करीब एक साल में पांच हजार के आसपास रहते हैं।

बीते साल के अगर अवैध कटाई के आंकडें देखें तो जबलपुर में 4,879, शहडोल में 3,353, बैतूल में 3,339, छिंदवाड़ा में 3,112, सागर में 3,034 मामले दर्ज हुए हैं। इसी तरह से अगर अवैध अतिक्रमण के आंकड़े देखे जाएं तो ग्वालियर में 294, शिवपुरी में 183, रीवा में 155, भोपाल में 138 और सागर में 121 मामले सामने आए थे। प्रदेश में प्राय: जंगलों में दो तरह से पेड़ों की अवैध कटाई की जाती है। इसमें भी सर्वाधिक अवैध रूप से वनों की कटाई स्थानीय लोगों के द्वारा की जाती है। यह लोग अपने खेतों के आसपास के जंगल को काटकर उस पर खेत बना लेते हैं। दूसरी तरह की कटाई लकड़ी बेचने के लिए की जाती है। इस तरह की कटाई का आंकड़ा बहुत कम रहता है। प्रदेश में बीते तीन-चार सालों में अवैध कटाई के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इसकी मुख्य वजह वन अधिकार पत्र वितरण और सरकार द्वारा वनों के जरिए स्थानीय लोगों की आजीविका सुनिश्चित किया जाना है। जिन वृत्तों में जंगलों की अवैध कटाई खेत बनाने को लेकर की जा रही है, उनमें बुरहानपुर, सागर, शिवपुरी, ग्वालियर, रीवा, छिंदवाड़ा, बैतूल और भोपाल वन वृत्त शामिल हैं। इन जिलों में प्रतिवर्ष हजारों हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा कर लिया जाता है। वन विभाग इस मामले में औसतन हर साल करीब 1700 प्रकरण दर्ज करता है। अतिक्रमण के मामले में रीवा, सागर, शिवपुरी, भोपाल के आसपास के जिले सबसे आगे बने हुए हैं। इस मामले में एक पूर्व वन अफसर का कहना है कि वन अधिकार पत्र के तहत जो पट्टे दिए जा रहे हैं, उससे स्थानीय लोगों में वनों की अवैध कटाई कर अतिक्रमण की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। अतिक्रमण को हटाने के लिए मैदानी अमले को सरकार की तरफ से पूरी तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता है। यही वजह है कि प्रदेश में विदिशा जिले के लटेरी जैसी घटना होती है।

सूबे का वन विभाग ऐसा विभाग है जहां, कानून भी जंगल की ही तरह काम करता है। विभाग के अफसरान ऐसे हैं कि वे न तो सरकार की छवि की चिंता करते हैं और न ही विभाग के मंत्री को ही तवज्जो देते हैं। हालात यह हैं कि जिस सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस के और सुशासन के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, उसमें दागी अफसरों की बल्ले-बल्ले बनी रहती है। हद तो यह है कि विधानसभा में दिए जाने वाले मंत्री के आश्वासानों को भी विभाग पूरा करने में कोई रूचि नहीं लेता है। इसके उलट चहेते अफसरों को बचाने के लिए पूरी ताकत से विभाग के आला अफसरान लग जाते हैं। इसका उदाहरण है वन मंत्री विजय शाह द्वारा दिसंबर माह में विधानसभा सत्र के दौरान वनीकरण क्षतिपूर्ति घोटाले में उलझे दक्षिण सागर वन मंडल डीएफओ नवीन गर्ग को हटाने की घोषणा। अब जबकि बजट सत्र जारी है, लेकिन मजाल है कि गर्ग को हटाया गया हो। इस बीच आईएफएस अफसरों की नई पदस्थापना की दो-दो सूचियां जारी हो चुकी हैं, लेकिन उनमें उनका नाम ही शामिल नहीं किया गया है।

बताया जाता है कि क्षतिपूर्ति में हुई गड़बड़ी में दोषी करार दिए गए दक्षिण सागर वन मंडल के डीएफओ नवीन गर्ग को हटाने संबंधित आश्वासन वनमंत्री विजय शाह ने विधानसभा में दिया था, लेकिन इसके बाद भी उनका प्रस्ताव मंत्रालय तक भेजा ही नहीं गया है। जबकि वनमंत्री विजय शाह के आश्वासन के बाद बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र में आई वन भूमि के बदले में गैर वन भूमि और बिगड़े वन में पौधारोपण कराने में हुई गड़बड़ी में दक्षिण मंडल में पदस्थ रहे प्रशांत कुमार सिंह, एमएस उईके और वर्तमान डीएफओ नवीन गर्ग को दोषी माना गया है। इनमें से प्रशांत कुमार सिंह को दक्षिण सागर से हटाकर खरगोन और एमएस उईके को दमोह पदस्थ कर दिया गया है। जबकि नवीन गर्ग अभी भी दक्षिण सागर वन मंडल में पदस्थ हैं। दिलचस्प पहलू यह है कि महकमे के आला अफसरों ने एमएस उईके तत्कालीन प्रभारी डीएफओ दक्षिण सागर वन मंडल को इस मामले में क्लीन चिट दे दी, जबकि नवीन गर्ग को उसी मसले में आरोपों के घेरे में खड़ा कर दिया है।

● **बृजेश साहू**

सजा की जगह दे दिया ईनाम

तत्कालीन छिंदवाड़ा के डीएफओ बृजेंद्र श्रीवास्तव के खिलाफ 21 जुलाई 2022 को नियम-10 के तहत आरोप पत्र जारी किया गया था। इन पर आरोप है कि स्थानांतरण नीति के विरुद्ध जाकर कर्मचारियों के तबादले किए। उनके द्वारा आरोप पत्र का जवाब तक नहीं दिया गया। इस पर कार्रवाई करने की जगह उन्हें हाल ही में ग्वालियर से पूर्व छिंदवाड़ा वन मंडल जैसे महत्वपूर्ण जगह पदस्थ कर दिया गया। इसी तरह से मुख्यालय में पदस्थ भारत सिंह बघेल को आरोप पत्र 22 मई 2006 को जारी किया गया था। बघेल ने अपने प्रभाव अवधि के दौरान पूर्व लांजी क्षेत्र में प्रभार अवधि में राहत कार्य अंतर्गत कार्यों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की थी। इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत का इंतजार कर रहा है। उधर, खंडवा में डीएफओ के पद पर पदस्थ प्रशांत कुमार को आरोप पत्र 4 सितंबर 2020 को जारी हुआ था। प्रशांत कुमार को पश्चिम बैतूल वन मंडल में अनियमितता के मामले में हुई जांच में दोषी पाया जा चुका है, जिसमें महज विभाग ने एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दंड आरोपित कर अंतिम निर्णय के लिए संघ लोक सेवा आयोग भेजा है।

44 लाख पेड़ों को काटने की तैयारी

क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी इलाके में जहां पहले से ही पेड़-पौधों की संख्या कम हो, लेकिन आने वाले समय में उसी इलाके के 44 लाख पेड़ काटने की तैयारी की जा रही हो। यह इलाका है मप्र और उप्र के 13 जिलों में फैला बुंदेलखंड क्षेत्र। जो पिछले डेढ़ दशक से सूखे की मार से अभिशप्त है। ऐसे विपरीत हालात में इस इलाके के लाखों पेड़ काटे जाने के बाद क्या यह उम्मीद बच पाएगी कि भविष्य में इस इलाके से सूखा खत्म हो जाएगा? बुंदेलखंड के बक्सवाहा (छतरपुर, मप्र) के जंगलों में हीरा खदान के लिए 4 लाख से अधिक पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ दायर याचिका को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने 28 फरवरी 2023 को खारिज कर दिया। इसका मतलब है कि अब हर हाल में 4 लाख पेड़ काटे ही जाएंगे। एनजीटी ने याचिका को अपरिपक्व करार दिया। हालांकि इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता पीजी पांडे ने पुनर्विचार याचिका दायर की है।

ध्यान रहे कि मप्र ने बुंदेलखंड के बांदा, चित्रकूट व महोबा की सीमा से लगे बक्सवाहा में हीरा खनन के लिए एक्सेल माइनिंग कंपनी को पेड़ काटने के लिए अभी तक 364 हेक्टेयर भूमि का पट्टा आवंटित किया है। इस जंगल में केवल पेड़ ही नहीं है, बल्कि यहां के पत्थरों व चट्टानों पर दुर्लभ ऐतिहासिक शैलचित्र भी मौजूद हैं। इनके भी अब नष्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। मप्र पुरातत्व विभाग ने इस क्षेत्र में एक व्यापक सर्वे किया था और उसमें यह बात निकलकर आई थी कि बक्सवाहा के जंगल में पाषाणकालीन रॉक पेंटिंग्स मौजूद हैं। इसके अलावा इस जंगल में कल्चुरी और चंदेल काल की कई मूर्तियां और स्तंभ भी मौजूद हैं, जिनका खनन की वजह से नुकसान पहुंच सकता है।

यही नहीं, इसी इलाके में केन-बेतवा लिंक बांध परियोजना में पन्ना टाइगर रिजर्व के 23 लाख पेड़ काटे जाने की भी तैयारी है। यह बात परियोजना के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में लिखित तौर पर दर्ज है। यदि इसकी सैटेलाइट सर्वेक्षण संख्या को देखें तो लगभग 40 लाख पेड़ काटे जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना को लागू करने के लिए 6,017 हेक्टेयर वन भूमि को खत्म किया जाएगा। यह वन भूमि 8,427 फुटबॉल के मैदान के बराबर है। पन्ना के जंगलों में सागौन, महुआ, बेलपत्र, आचार, जामुन, खैर, कहवा, शीशम, जंगल जलेबी, गुली, आंवला समेत अन्य प्रमुख प्रजातियों के बहुत पुराने पेड़ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इसके साथ-साथ यहां घड़ियाल अभयारण्य और गिद्धों का प्रजनन केंद्र भी गंभीर रूप से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा।

सिंचाई एवं पेयजल का मिल सकेगा लाभ

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को दो चरणों में लागू किया जाना है, जिसमें से पहले चरण में केन नदी के पास में स्थित दौधन गांव में एक बांध बनाया जाएगा, जो 77 मीटर ऊंचा और 2,031 मीटर लंबा होगा। इसके अलावा 221 किलोमीटर लंबी केन-बेतवा लिंक नहर बनाई जाएगी, जिसके जरिए केन का पानी बेतवा बेसिन में डाला जाएगा। दौधन बांध के चलते 9,000 हेक्टेयर का क्षेत्र डूबेगा, जिसमें से सबसे ज्यादा 5,803 हेक्टेयर पन्ना टाइगर रिजर्व का होगा, जो कि बाघों के रहवास का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। इस योजना के चलते 6,017 हेक्टेयर वन भूमि को पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा, जिसमें बेहद संवेदनशील पन्ना टाइगर रिजर्व का 4,141 हेक्टेयर वन क्षेत्र भी शामिल है। वहीं दूसरी ओर केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इस दलील पर आधारित है कि केन नदी में पानी की मात्रा ज्यादा है, इसलिए दोनों नदियों को जोड़कर केन के पानी को बेतवा में पहुंचाया जाएगा, जिससे लोगों को सिंचाई एवं पेयजल का लाभ मिल सकेगा। वैसे देखा जाए तो केन और बेतवा दोनों नदियां प्राकृतिक रूप से एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जो अंत में जाकर यमुना नदी में मिल जाती हैं, लेकिन सरकार जिस कृत्रिम तरीके से इन्हें जोड़ना चाह रही है, उसे पर्यावरण विशेषज्ञों ने पूरी तरह से विनाशकारी बताया है।

बुंदेलखंड के पर्यावरण कार्यकर्ता आशीष सागर दीक्षित का कहना है कि इलाके से इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों के काटे जाने के बाद यहां की जैव विविधता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, यही नहीं हीरे की परियोजना पर प्रतिवर्ष 53 लाख क्यूबिक पानी भी खर्च होगा। पहले से ही सूखे की मार झेल रहे इलाके के लिए यह और भी गंभीर खतरा है। ध्यान रहे कि बक्सवाहा के जंगलों में 3.42 करोड़ कैरेट के हीरों का यहां दबे होने का अनुमान है। भारत में अभी तक हीरे का सबसे बड़ा भंडार मप्र के पन्ना जिले में है लेकिन बक्सवाहा में तो पन्ना से 15 गुना अधिक हीरे निकलने का अनुमान लगाया गया है। मप्र सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में हीरे की खोज के लिए 2010 में ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रियो टेंटो की मदद से सर्वे कराया था। सर्वे के दौरान ही बक्सवाहा के आसपास किंबरलाइट पत्थर की चट्टानें दिखाई दीं। हीरा इन्हीं किंब्रलाइट की चट्टानों में मिलता है। 2002 में कंपनी को औपचारिक रूप से क्षेत्र में हीरा तलाशने का काम सौंप दिया गया। लंबे शोध के बाद कंपनी ने खनन की तैयारियां शुरू कीं लेकिन स्थानीय समुदाय के विरोध के कारण कंपनी ने 2016 में इस परियोजना से अपने को अलग कर लिया। इसके बाद 2019 में हीरे की खदान का नया लाइसेंस आदित्य बिड़ला ग्रुप की एक्सेल माइनिंग कंपनी को मिला।

सरकार का दावा है कि इसके जरिए 9.04 लाख हेक्टेयर की भूमि सिंचित होगी, जिसमें से मप्र में 6.53 लाख हेक्टेयर और उप्र में 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। साथ ही 62 लाख लोगों को पेयजल भी मिलेगा। हालांकि बुंदेलखंड के विकास के नाम पर प्रचारित की जा रही इस परियोजना के तहत जहां एक तरफ क्षेत्र के 13 जिलों में से 8 जिले (पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर) को ही लाभ मिलने की संभावना है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

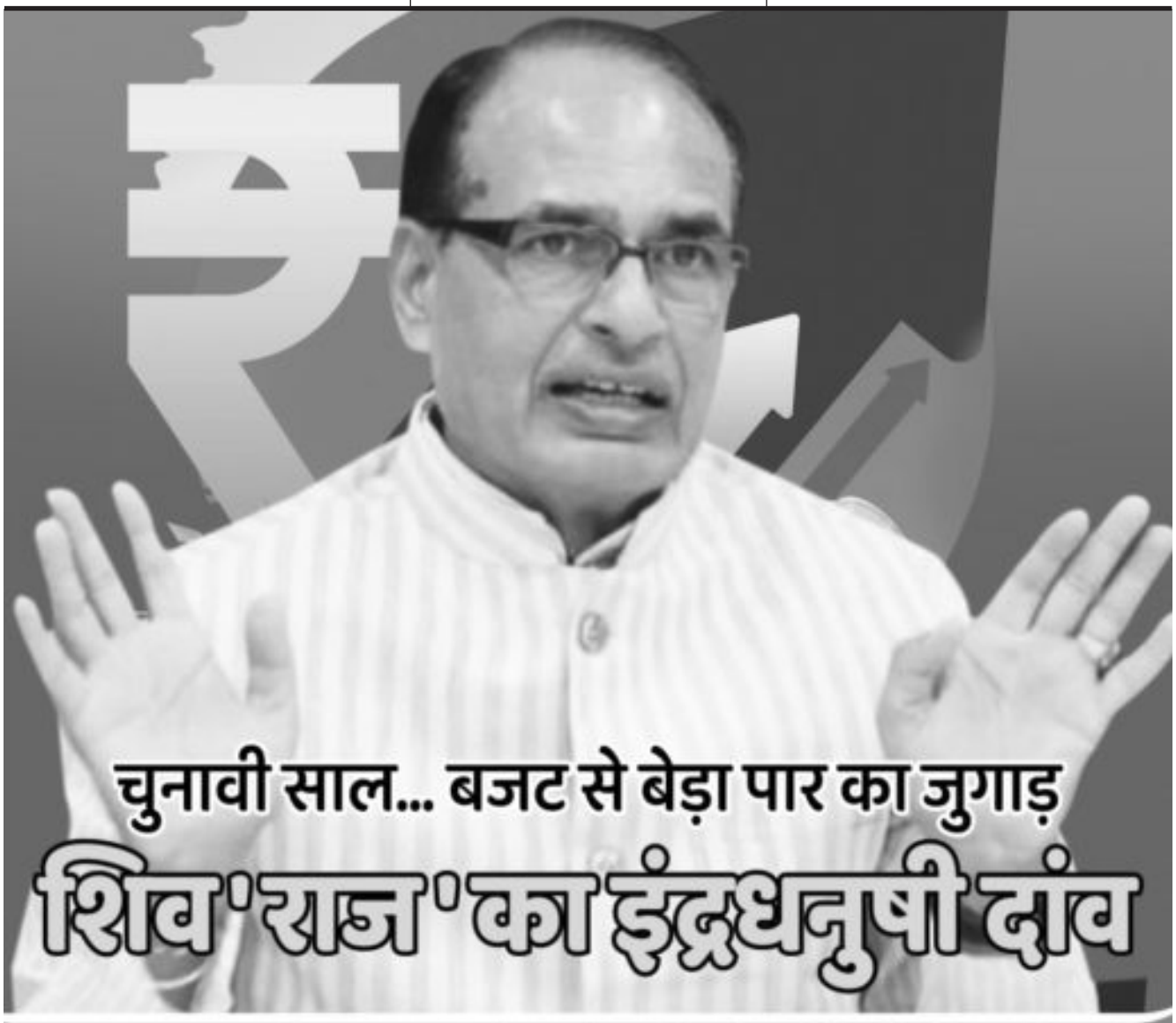

चुनावी साल... बजट से बेड़ा पार का जुगाड़

शिव'राज'का इंद्रधनुषी दांव

3.14 लाख करोड़ का बजट पेश, 55 हजार करोड़ का घाटा

बहनों और भांजियों की बल्ले बल्ले! युवाओं पर भी फोकस

यह साल विधानसभा चुनाव का है। चुनावी साल में मप्र की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बजट से चुनावी बेड़ा पार करने की भरपूर जुगाड़ की है। इसके लिए शिव'राज' ने इंद्रधनुषी दांव चला है। शिवराज सरकार ने 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ का बजट पेश किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश का राजकोषीय घाटा 55,709 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4.2 प्रतिशत रहेगा। इन सबके बावजूद बजट को आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए तैयार किया गया है।

● राजेंद्र आगाल

चुनावी साल में सरकार का रंग और ढंग पूरी तरह बदल जाता है। इसका नजारा मप्र की शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल के आखिरी बजट में देखने को मिला है। 55,709 करोड़ रुपए के अनुमानित घाटे के बावजूद सरकार ने इंद्रधनुषी दांव खेला है। यानी बजट को आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए तैयार किया गया है। सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की गई है। राज्य सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। वहीं बहनों और भांजियों को खुले हाथों से सौगातें दी गई हैं। जबकि युवाओं को साधने की भी भरपूर कोशिश की गई है। दरअसल, नेता वित्तीय मामले में चाहे कितना समझदार क्यों न हो, चुनावों का मौसम उसके सुर बदल ही देता है। मप्र की सरकार के हालिया बजट में गिफ्ट वाउचर जनता में बांटने और लोकलुभावन जन कल्याण योजनाओं का चारा डालने के मामले में फिजूलखर्ची की हद ही पार कर दी है। इसकी भरपाई कैसे होगी, यह बड़ा प्रश्न है।

पहली बार ग्रीन बजट

मप्र के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने 2023-24 का बजट पेश करते हुए ग्रीन बजट भी घोषित किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों को हटाने और उन्हें स्क्रैप करने की नीति जारी की है। राज्य सरकार अप्रैल 2023 से इसे लागू करेगी। लगभग एक हजार सरकारी वाहनों का संचालन बंद किया जाएगा। इनके स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जाएंगे। देवड़ा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने का संकल्प लिया है। प्रकृति के साथ प्रगति ही हमारा भी मूल-मंत्र है। प्रदेश में अंकुर अभियान के तहत अब तक 38 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। वहीं, इंदौर नगर निगम ने इंदौर ग्रीन बॉन्ड जारी कर 244 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसका इस्तेमाल सोलर पॉवर प्रोजेक्ट लगाने में किया जाएगा। इससे जो सोलर प्लांट बनेगा, उससे हर महीने 5 करोड़ रुपए की बचत होगी। देवड़ा ने बताया कि अगले वित्त वर्ष में 2.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जंगलों के बेहतरीकरण पर कार्य किया जाएगा। प्रदेश में 10 साल पहले सिर्फ 491 मेगावॉट बिजली नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बनती थी। आज यह 12 गुना बढ़कर 5,875 मेगावॉट हो चुकी है। 4 हजार करोड़ रुपए की 750 मेगावॉट क्षमता की सोलर एवं विंड एनर्जी हाइब्रिड प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। नीमच, आगर और शाजापुर जिलों में 1,500 मेगावॉट की सौर परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर स्थित बांध के बैकवॉटर पर 3,600 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया के सबसे बड़े 600 मेगावॉट के फ्लोटिंग सोलर पार्क की स्थापना की जा रही है।

मप्र में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के साथ सभी पार्टियां मुस्तैद हैं और अभी से तैयारी में जुटी हुई हैं। सत्ता में होने के कारण भाजपा सरकारी योजनाओं के माध्यम से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में शिवराज सरकार ने 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ का बजट पेश किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश का राजकोषीय घाटा 55,709 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4.2 प्रतिशत रहेगा। बजट को आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए तैयार किया गया है। सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की गई है। राज्य सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। शिवराज सरकार के बजट में तीन वर्ग महिला, किसान और युवा बेरोजगार पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। धर्म का तड़का भी है। बजट का करीब एक तिहाई हिस्सा महिला कल्याण के लिए रखा गया है। एक लाख नौकरी से युवाओं और ब्याज माफी से किसानों को जोड़ने की कोशिश की गई है। मप्र में पिछले दो दशक से महिला वोट भाजपा की प्राथमिकता है। महिला वोटरों को लुभाने के लिए 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना आई थी। उसकी कामयाबी से उत्साहित होकर अब लाडली बहना योजना आई है। प्रदेश में 2.60 करोड़ महिला मतदाता हैं। साल में 12,000 रुपए मुफ्त में पाने वाली एक करोड़ महिलाओं के अलावा 47 लाख औरतें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। सरकार ने उन्हें ब्याज अनुदान के रूप में 600 करोड़ देने का ऐलान भी किया है। लाडली बहना योजना का प्रावधान भाजपा सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।

सरकारी तोहफों की बरसात

मप्र में सरकारी तोहफे बरस रहे हैं और इसमें कोई अचरज भी नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां विधानसभा चुनाव बमुश्किल नौ महीने दूर है। जमीन, मकान, नगदी... सबकुछ मिल रहा है। घोषणाएं पूरी करने में आने वाली वित्तीय लागतों की चिंता किए बगैर राजनीतिक दल मुफ्त लाभों की घोषणाएं करने की होड़ में हैं क्योंकि अधिकांश आबादी लाभार्थी है, उसे इन स्थितियों से शिकायत नहीं। लेकिन ईमानदार करदाता, जो लाभार्थी नहीं हैं, इससे चिंतित हैं। उन्हें पता है कि सत्ता में रहने की होड़ में हो रही इन घोषणाओं का बोझ अंतत: उन पर ही पड़ेगा।

बीती 28 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि राज्य में बहुत जल्द लाडली बहना योजना शुरू की जाएगी। वयस्क होने पर लड़कियों को वित्तीय सहायता देने का वादा करने वाली लाडली लक्ष्मी योजना के शिल्पी (शिवराज सिंह चौहान) का कहना है कि मैं बहनों को और ज्यादा लाभ पहुंचाने के बारे लगातार सोच रहा था। लाडली बहना योजना के अंतर्गत आयकर भुगतान सीमा से नीचे के परिवारों की 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों को प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। वित्त विभाग के आला अधिकारियों का दावा है कि उन्हें योजना से पैदा होने वाले वित्तीय बोझ के आंकलन के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन प्रारंभिक गणनाओं के अनुसार इस पर अनुमानत 12,000 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय होगा। योजना में लगभग 1.2 करोड़ युवातियों के शामिल होने की उम्मीद है।

लाडली बहना की पूर्ववर्ती योजना, लाडली लक्ष्मी योजना का शिवराज सिंह चौहान को राजनीतिक लाभ मिला था और वे खुद को राष्ट्रीय स्तर पर सफल मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर सके थे। अब वे इस जनसमुदाय के बीच अपने समर्थन के आधार को और मजबूत करने की योजना बना रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मप्र के कुल 5.40 करोड़ मतदाताओं में 48 प्रतिशत महिलाएं हैं। कुछ हफ्ते पहले, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों को मुफ्त आवासीय भूखंड देने की घोषणा भी की थी। इस घोषणा पर काम आगे बढ़ाते हुए पहले टीकमगढ़ (10,500 लोगों को) और बाद में सिंगरौली जिले (25,000 लोगों को) में जमीन बांटी गई। इस योजना में भुगतान शामिल नहीं है, लेकिन अधिकारियों ने स्वीकार किया कि मुफ्त भूमि की लागत टीकमगढ़ में 120 करोड़ रुपए और सिंगरौली में 250 करोड़ रुपए आंकी गई है।

सरकार के शीर्षस्थ सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के हिस्से के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि भी बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किए गए 6,000 रुपए के अलावा 80 लाख से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 4,000 रुपए मिलते हैं। राज्य की राशि दो किस्तों में जारी की जाती है। इसमें कितनी वृद्धि होगी यह अभी पता नहीं है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि चूंकि बोनस भुगतान में समस्या है, इसलिए चुनाव से पहले ही मध्यम और बड़े किसानों की

तुलना में अधिक संख्या में मौजूद छोटे और सीमांत किसानों को किसान कल्याण योजना के तहत किए जाने वाले भुगतान में बढ़ोतरी की जाएगी।

मप्र की वित्तीय स्थिति

मप्र की वित्तीय स्थिति पर एक दृष्टि डालना यहां अप्रासंगिक नहीं होगा। वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के बजट में व्यय का अनुमान 2,47,715 करोड़ रुपए था। इसमें हर साल बढ़ती जा रही भारी ऋण चुनौतियां शामिल नहीं थीं। राजकोषीय घाटे का अनुमान जीएसडीपी का 4.56 प्रतिशत का था, जबकि 4 प्रतिशत की अनुमति थी। यह अनुमति इस विचार के साथ दी गई थी कि विद्युत क्षेत्र में सुधार किए जाएंगे। वर्तमान में राज्य सरकार की कुल देनदारियां 3,45,543 करोड़ रुपए की हैं और इस बात के कोई संकेत नहीं हैं कि नई उधारियों में कोई कमी आएगी। इस बात का किसी के पास जवाब नहीं है कि नए सरकारी तोहफों के लिए धन की व्यवस्था कैसे की जाएगी। राज्य का कर राजस्व (उत्पाद शुल्क, जीवाश्म ईंधन पर कर, टिकट और पंजीकरण, खनन आदि) 2021-22 में 81,613 करोड़ रुपए था और इसके बढ़कर 87,945 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। इनमें से 2022-23 के लिए आबकारी से लक्षित संग्रह 13,613 करोड़ रुपए था। लोकलुभावन घोषणाओं की पूर्ति की खातिर अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए राज्य सरकार को या तो जीवाश्म ईंधन पर करों में वृद्धि करनी होगी या उधारी को बढ़ाना होगा जिसकी अपनी जटिलताएं भी हैं। लेकिन इसकी परवाह किसे है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए हाल ही में घोषित मप्र के बजट को एक संतुलित बजट के रूप में सराहा जा रहा है। हर क्षेत्र और वर्ग पर केंद्रित इस बजट में बुनियादी ढांचा, मूल्यवर्धन उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश के अलावा सबसे अधिक महत्व महिला सशक्तिकरण को दिया है, जो अत्यंत सराहनीय है। एक ओर स्वसहायता समूहों के लिए 3 लाख रुपए तक के ऋण पर अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के साथ एसएचजी क्रेडिट लिंकेज के लिए 5084 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने पर भी यह बजट केंद्रित है। मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना बच्चियों को नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। निश्चित ही यह उनके व्यक्तिगत विकास के साथ-साथ राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। लाडली बहना योजना के लिए 8000 करोड़ और लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। यह गरीब महिलाओं को समग्र सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। ये आवंटन महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने में लाभकारी सिद्ध होगी। मप्र ऐतिहासिक स्मारकों, राष्ट्रीय उद्यानों और धार्मिक स्थलों सहित कई पर्यटन स्थलों से भरपूर है। इस क्षमता का दोहन करने के लिए राज्य सरकार ने महाकाल जैसे प्रमुख मंदिरों के आसपास बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान देते हुए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धन आवंटित किया है। इस निवेश से पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। प्रसन्नता का विषय है कि राज्य शिक्षा का केंद्र भी बन गया है और इस प्रकार के प्रावधान युवाओं को रोजगार दिलाने में भी सहायक होंगे।

बजट के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2022-23 में 1,151,049 करोड़ ट्रिलियन रुपए (यूएस डॉलर 150,74 बिलियन) तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह सकारात्मक पहल है। राज्य की जीडीपी 71,594 करोड़ से बढ़कर 13,22,000 करोड़ रुपए हो गई है और प्रति व्यक्ति आय जो 2002 में 11,718 रुपए थी, वह 2022-23 में 1,40,500 रुपए हो गई है। यह निरंतर विकास की ओर अग्रसर होते राज्य की परिभाषा है। हालांकि बजट में आम आदमी की चिंताओं को दूर करने के लिए और उपाय शामिल किए जा सकते थे। जैसे करों का बोझ कम करना, स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं का विस्तार और आमजन के जीवन स्तर के समग्र सुधार पर अधिक ध्यान दिया जा सकता था।

खेल बजट दोगुने से ज्यादा

खेलो इंडिया यूथ के पांचवें संस्करण के सफल आयोजन का लाभ खेल विभाग को मिलने जा रहा है। वर्ष 2023-24 के लिए मप्र के खेल बजट को 738 करोड़ कर दिया गया है। जो पिछले साल 347 करोड़ रुपए था। इस तरह मप्र के खेल बजट में दोगुने से ज्यादा वृद्धि की गई है। इससे भोपाल के नाथू बरखेड़ा में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स के निमार्ण में तेजी आएगी। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाया जाएगा। मप्र में पिछले माह खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था, इसमें लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, सफल आयोजन के साथ ही प्रदेश के खिलाडियों ने जोरदार प्रदर्शन कर 39 स्वर्ण, 30 रजत व 27 कांस्य पदक के साथ कुल 96 पदक जीते थे। इसके साथ ही मप्र पदक तालिका में पिछली बार के मुकाबले आठवें से सीधे तीसरे स्थान पर पहुंच गया था। नाथू बरखेड़ा में तैयार हो रहा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेल विभाग का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तीन चरणों में इसे तैयार होना था। पिछले साल खेलो इंडिया के दौरान ही इसमें काम शुरू हो जाना था, लेकिन कम समय के कारण नहीं हो सका। अब पहले चरण में यहां पर एथलेटिक ट्रैक व दो हॉकी मैदान तथा स्पोर्ट्स साइंस सेंटर तैयार किया जाएगा। पूर्व में इसकी अनुमानित लागत लगभग 137 करोड़ रुपए थी। इसी कॉम्प्लेक्स में फुटबाल स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी तीसरे चरण में तैयार किया जाना प्रस्तावित है। मप्र को खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत महत्व मिला है। मप्र के भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग अकादमी, घुड़सवारी अकादमी व वाटर स्पोर्ट्स अकादमी है। इसके अलावा तात्या टोपे स्टेडियम में मार्शल आर्ट गेम्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंडोर हाल तथा एथलेटिक्स, टेनिस व बैडमिंटन की सुविधाएं हैं। अभी इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में भी खेल सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन नाथू बरखेड़ा में जब अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स पूरी तरह विकसित हो जाएगा तब मप्र सही मायने में स्पोर्टस हब बन जाएगा।

धार्मिक स्थलों के विकास पर करोड़ों खर्च करेगी सरकार

मप्र के बजट में इस बार धर्म की गंगा बहाने में भी शिवराज सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। योगी सरकार ने अपने बजट में महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की थी। इसके अलावा, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ आदि में बड़े धार्मिक स्थलों पर भी सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इसी तर्ज पर शिवराज सरकार ने भी मप्र के धार्मिक शहरों की तस्वीर बदलने के लिए काफी राशि खर्च करने का ऐलान किया है। विधानसभा चुनाव के पहले पेश हुए बजट में धार्मिक स्थलों को शामिल कर सरकार यह दावा कर रही है कि धार्मिक पर्यटन बढ़ने से लोगों को रोजगार के साधन भी मिलेंगे। इसके लिए महाकाल लोक का बड़ा उदाहरण पेश किया जा रहा है। महाकाल लोक के निर्माण में भी सरकार ने 400 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की है। अभी महाकाल लोक के दूसरे चरण का कार्य चल रहा है। शिवराज सरकार ने बजट में ओरछा के रामराजा के विकास को भी शामिल किया है। इसे रामराजा लोक के नाम से विकसित किया जाएगा। सरकार ने नर्मदा परिक्रमा के लिए नर्मदा पथ का निर्माण करने की योजना भी बजट में पारित की है। हर साल नर्मदा परिक्रमा के लिए मप्र के लाखों लोग पहुंचते हैं। अभी दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के विकास का दूसरा चरण चल रहा है जबकि सरकार ने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए भी बजट में करोड़ों की राशि स्वीकृत की है।

3 करोड़ से ज्यादा वोटरों पर निशाना

चुनावी साल में आए मप्र के इस बजट में शिवराज सरकार ने तीन करोड़ से ज्यादा वोटरों पर सीधा निशाना लगाया है। पूरे बजट का एक तिहाई हिस्सा यानी 1.02 लाख करोड़ रुपए (32.79 प्रतिशत) सिर्फ महिलाओं के लिए रखा है, जो पिछली बार से 22 प्रतिशत ज्यादा है। खासतौर पर एक करोड़ महिलाओं के खाते में एक हजार रुपए हर महीने देने के लिए लाई गई लाडली बहना योजना के फंड में पहले साल ही 8000 करोड़ रखे गए हैं, क्योंकि दिसंबर तक चुनाव हो जाएंगे। महिलाओं पर फोकस की बड़ी वजह है- प्रदेश के 5.39 करोड़ वोटरों में 2.60 करोड़ महिलाओं का होना। 18 विधानसभा सीटों पर इनकी संख्या पुरुषों से ज्यादा हो गई है। इस साल जुड़े 13.39 लाख नए वोटरों में भी महिलाएं 7.07 लाख हैं। पांच आदिवासी बहुल जिला मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, आलीराजपुर और झाबुआ में महिला वोटर पुरुषों से ज्यादा हैं। इसलिए महिला वोटर इस बार सबसे अहम है। इस वोटर की अहमियत आप इससे समझ सकते हैं कि बजट के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तुरंत बयान जारी कर कहा कि उनकी सरकार आई तो महिलाओं के खाते में डेढ़ हजार रुपए महीना देंगे।

पिछले तीन विधानसभा चुनाव देखें तो महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम देखने को मिली है। 2018 के विधानसभा चुनाव में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वोट 2 प्रतिशत, 2013 में यह करीब चार और 2008 में यह 7 प्रतिशत कर्म दर्ज की गई थी। क्या महिलाओं का वोट किसी एक पार्टी की ओर झुका हुआ दिखता है तो इसका जवाब है कि ऐसा निर्णायक तौर पर दिखाई नहीं देता है। हां, जिस पार्टी की सरकार होती है, जो पार्टी योजना लेकर आती है उनके प्रति झुकाव अवश्य देखने को मिलता है। अगर हम वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणाम देखें तो करीब दो फीसदी तक महिलाओं का झुकाव भाजपा की ओर दिखाई दिया था। जहां तक हिंदुत्व का सवाल है तो भाजपा की हर राज्य सरकार ऐसा करती है और उसकी कोशिश होती है कि मतदाताओं को यह संदेश दिया जा सके कि हिंदुआं की सबसे हितैषी पार्टी वही है। हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराने की घोषणा भी इसका ही तरीका है। बजट में अनुसूचित जनजाति योजना का बजट 37 प्रतिशत बढ़ाकर (36,950 करोड़ रुपए) इस वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। इन खर्चों की पूर्ति सरकार को जीएसटी और अन्य करों से मप्र को मिलने वाला 80 हजार करोड़ से अधिक के हिस्से और पेट्रोल-

सरकार की दरियादिली

- प्रदेश में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएंगी। रोजगार के लिए 200 युवाओं को जापान भी भेजा जाएगा
- 900 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। सीएम सनराइज स्कूलों के लिए 3 हजार 230 करोड़ रुपए का बजट
- सीएम लाडली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़, पात्र महिलाओं को मिलेंगे 1000 प्रतिमाह
- नारी कल्याण के लिए 1.2 लाख 976 करोड़
- बजट में लाडली लक्ष्मी योजना उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन
- लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़
- महिला स्वसहायता समूह के लिए 660 करोड़
- आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़
- एक लाख नई नौकरियां देने का ऐलान
- लाडली बहना योजना के लिए 60 हजार करोड़ का प्रावधान
- मप्र का कृषि का योगदान पहले 3.6 था अब 4.8 परसेंट पहुंचा
- घुमंतू जाति के लिए मुख्यमंत्री कौशल योजना होगी शुरू
- संपत्ति की रजिस्ट्री में दी जा रही छूट
- खेल विभाग का बजट बढ़ाया गया, खेलों के विकास के लिए 738 करोड़
- नवीन मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के तहत 12वीं क्लास फर्स्ट डिविजन से पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी।
- युवाओं को स्वावलंबी बनाना सरकार की योजना
- स्कूलों में खाली पदों पर होगी भर्ती
- डिफाल्टर बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी
- 300 गौशालाओं के निर्माण की स्वीकृति
- मिलेट मिशन के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान
- फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा
- 900 किलोमीटर लंबा नर्मदा प्रगति पथ बनेगा
- 105 नए ओवरब्रिज बनाए जाएंगे
- सड़क निर्माण और विकास के लिए 10,182 करोड़
- मछली उत्पादन में मप्र को विशेष पुरस्कार
- 2 साल में 17,000 शिक्षकों की भर्ती

मप्र में बढ़ी प्रति व्यक्ति आय

सिंचाई क्षमता बढ़ी तो कृषि विकास दर ने भी रिकॉर्ड तोड़ा

सिंचाई क्षमता में बढ़ोतरी से मप्र की कृषि विकास दर में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि दर्ज हुई है। 2003 में सिंचाई क्षमता सिर्फ 7 लाख 68 हजार हेक्टेयर थी, जो 2022 में बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है। गेहूं के निर्यात में मप्र देश में नंबर-1 बना हुआ है। देश में कुल गेहूं के निर्यात में मप्र की 46 प्रतिशत भागीदारी है। बीते वर्षों में गेहूं उत्पादन 169 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 600 मीट्रिक टन के पार पहुंच चुका है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मप्र लगातार समृद्ध हो रहा है। मप्र का हेल्थ बजट 662 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,400 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। पैरा मेडिकल स्टाफ की संख्या में 2003 के मुकाबले अब तक 43,500 से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मप्र पॉवर में सरप्लस स्टेट बन चुका है। मप्र में जहां साल 2003 तक ऊर्जा क्षमता सिर्फ 5,173 मेगावॉट थी जो वर्ष 2022 में बढ़कर 28,000 मेगावॉट हो चुकी है।

मप्र विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शिवराज सरकार ने वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में 1,40,583 रुपए हो गई, जो 15.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। वहीं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 16.48 प्रतिशत की रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर है। हमारे ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि सरकार काफी ऋण ले रही है लेकिन यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 29 प्रतिशत है जो 2005 में 39 प्रतिशत था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 में 1,87,000 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना हुई तथा 15 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध हुए। वर्ष 2022-23 में नवंबर माह तक 2,13,000 पूछो लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई, जिसमें 11.30 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

गौरतलब है कि आर्थिक सर्वेक्षण में प्रदेश की आर्थिक स्थिति, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, प्रदेश के ऊपर ऋण, कृषि व औद्योगिक विकास, रोजगार के साथ सरकार की प्रमुख योजनाओं की स्थिति की जानकारी दी जाती है। प्रचलित भावों के आधार पर प्रदेश में वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 24 हजार 685 थी। इसमें वृद्धि संभावित है। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसमें मप्र की उजली तस्वीर पेश की गई है। यह दावा किया गया है कि पिछले वर्ष आर्थिक समृद्धि में मप्र देश के अग्रणी राज्यों में शामिल रहा और इसने जीएसडीपी में 16.43 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की। वहीं, 10 वर्षों में यह बढ़ोतरी 319 प्रतिशत हुई है। राज्य सांख्यिकी आयोग भी देश में सबसे मप्र में ही गठित हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर कीमतों पर मप्र में 2022-23 के अग्रिम अनुमान के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 5.67 प्रतिशत बढ़कर 65,023 रुपए हो गई है।

हालांकि, यह राष्ट्रीय आय 96,522 रुपए प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति से अब भी 32 प्रतिशत या 31,499 रुपए कम है। राज्य सरकार का कहना है कि मप्र में प्रति व्यक्ति आय 2011-12 में 38,497 रुपए थी, जो इन वर्षों में 70 प्रतिशत बढ़ी है। देश की अर्थव्यवस्था पांच बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें मप्र ने अपना योगदान 550 बिलियन डॉलर रखने का लक्ष्य तय किया है। प्रदेश इस ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश का जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर 7.06 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ा है।

मप्र सरकार के बजट का आकार भी तेजी से बढ़ रहा है। 2001 में मप्र का बजट महज 16,393 करोड़ रुपए का था, जो 2023 में बढ़कर 2,47,715 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यह वृद्धि 15 गुना है। प्रदेश का व्यय बजट पिछले वित्त वर्ष में 2,17,313 करोड़ रुपए था, जो बजट अनुमानों में 14 प्रतिशत बढ़कर 2,47,715 करोड़ रुपए किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2018-19 से 2021-22 के बीच राज्य का राजस्व 7.94 प्रतिवर्ष सीएजीआर से बढ़ा है। यानी हर साल औसतन उसमें करीब 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 2022-23 के बजट अनुमानों में राज्य की अपनी राजस्व वृद्धि दर 13.32 प्रतिशत रही, जबकि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी पिछले साल की तुलना में 9.81 प्रतिशत तक बढ़ी है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि सर्वेक्षण के तथ्य सिद्ध करते हैं कि मप्र की आर्थिक स्थिति मजबूत है। एक तरफ हमने वित्तीय अनुशासन और सुशासन के साथ सर्वसमावेशी विकास किया है, वहीं दूसरी तरफ राज्य के बजट का आकार तथा कर संग्रहण भी लगातार बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 में मप्र की आर्थिक विकास दर में 16.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2001-02 में सकल घरेलू उत्पाद 71,594 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 13 लाख 22 हजार करोड़ रुपए हो गया है। वर्ष 2001-02 में प्रति व्यक्ति आय 11,718 रुपए थी, आज बढ़कर 1,40,500 रुपए हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम पर अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि हम कर्जा ले रहे हैं लेकिन यदि आप आंकड़े देखेंगे 2005 में ऋण जीएसडीपी अनुपात मतलब जीएसडीपी के अनुपात में जो कर्जा लेते थे, वह 39.5 प्रतिशत था। लेकिन, कोविड की कठिनाइयों के बावजूद 2020-21 में घटकर 22.6 प्रतिशत हो गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अपने आप में सिद्ध करता है कि जीएसडीपी के अनुपात में ऋण का प्रतिशत लगातार घटा है। पिछले साल हमारा पूंजीगत व्यय 37 हजार 89 करोड़ रुपए था। हमने एक साल में उसको 23.18 प्रतिशत बढ़ाया। अब बढ़कर 45 हजार 685 करोड़ रुपए हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि औद्योगिक विकास दर जो 2012 में -0.61 प्रतिशत थी, वह 2022 में बढ़कर 24 प्रतिशत हुई है। यदि आप राजस्व संग्रहण की बढ़ती हुई गति को देखेंगे, तो हमने लगातार राज्य के करों के संग्रहण को भी बढ़ाया है और यह विगत तीन वर्षों का औसत 7.94 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों को 13.41 प्रतिशत तथा एमएसएमई क्षेत्र को ऋण में 30.22 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। स्ट्रीट वेंडरों को ऋण देने में मप्र सबसे आगे है। हमने 5 लाख 25 स्ट्रीट वेंडरों को 521 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया है। सारे आंकड़े बताते हैं कि मप्र की आर्थिक स्थिति मजबूत है।

सदेह से परे हों न्यायिक नियुक्तियां

न्यायिक नियुक्तियों पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कलेजियम व्यवस्था बनाने और संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी के गठन को गैर-संवैधानिक घोषित करने के मुद्दे पर विवाद और विमर्श दोनों जारी हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने न्यायपालिका को न्यायिक लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन न करने की सलाह दी है तो कानून मंत्री ने न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कलेजियम में केंद्र सरकार और उच्च न्यायालय कलेजियमों में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए पत्र भेजा। इससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य विवाद का संकेत गया, लेकिन इसे इन संस्थाओं के बीच संवाद के रूप में भी देखा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति एमसी छागला जब मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे तो उस दौरान वह तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई के साथ न्यायिक नियुक्तियों पर सैद्धांतिक असहमति के बावजूद प्रतिमाह चाय या रात्रिभोज पर संवाद करते थे। आज उस परंपरा को पुनर्जीवित क्यों नहीं किया जा सकता?

स्वतंत्रता तथा योग्यता के आधार पर निष्पक्ष न्यायिक नियुक्तियों को लेकर देश में सर्वसम्मति है। संविधान निर्माताओं की ऐसी कोई मंशा नहीं थी न्यायिक नियुक्तियों में किसी एक संवैधानिक संस्था का एकाधिकार हो। डॉ. अंबेडकर कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि न्यायपालिका ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी और जनता को बताएगी भी नहीं कि किस आधार पर उनका चयन हुआ और क्यों कुछ को अस्वीकृत किया गया? कलेजियम प्रणाली से जिस तरह नियुक्तियां हो रही हैं, उससे जनता के मन में शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। संभव है कि वे शंकाएं निर्मूल हों, किंतु पारदर्शिता के अभाव में उन्हें बल मिलता है। कई उदाहरण भी हैं। जैसे त्रिपुरा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी का प्रतिवेदन न करना और कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सौमित्र सेन की नियुक्ति करना। सेन पर वित्तीय अनियमितताओं के कारण राज्यसभा ने महाभियोग प्रस्ताव पारित किया था। ऐसे निर्णय कलेजियम पर प्रश्नचिन्ह खड़े करते हैं।

एनजेएसी संविधान संशोधन के उपरांत अस्तित्व में आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया। जबकि एनजेएसी में अध्यक्ष का दायित्व स्वयं मुख्य न्यायाधीश को दिया गया था, जिसमें दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानून मंत्री और दो अन्य ख्यातिप्राप्त जनों का प्रविधान था, जिनका चयन एक समिति करती जिसमें प्रधानमंत्री, नेता-प्रतिपक्ष और स्वयं मुख्य न्यायाधीश होते। एनजेएसी को निरस्त करने के न्यायपालिका के जो भी तर्क हों, लेकिन जनता को आज तक यह समझ नहीं आया कि किस लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्तियां करते हैं।

विश्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं। अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन उसके पहले सीनेट की समिति संभावितों के गंभीर साक्षात्कार लेती है। पूरी पड़ताल के आधार पर ही सीनेट नियुक्ति को स्वीकृत या अस्वीकृत करती है। इंग्लैंड में आयोग द्वारा परीक्षा और साक्षात्कार की प्रक्रिया के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्तियों का प्रतिवेदन होता है और प्रधानमंत्री के परामर्श पर महारानी-महाराज नियुक्ति करते हैं। लोकतंत्र में जनता और संविधान सर्वोच्च है, न कि न्यायपालिका। हमारे संविधान निर्माताओं ने यद्यपि न्यायपालिका को संसद के कानूनों पर न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार दिया, मगर न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अस्वीकार कर व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका में संतुलन स्थापित किया था। अत: उन्होंने वधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, न कि विधि की सम्यक प्रक्रिया के आधार पर न्यायपालिका को न्यायिक-पुनर्निरीक्षण का अधिकार दिया। हालांकि, 1973 में केशवानंद भारती मामले ने पूरा परिदृश्य बदल दिया।

संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन कर सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक-सर्वोच्चता की ओर कदम बढ़ाए। अब सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए किसी भी कानून को इस आधार पर निरस्त कर सकता है कि वह संविधान के मूल ढांचे के विरूद्ध है। एनजेएसी के साथ भी उसने यही किया। उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक सर्वोच्चता की दिशा में दूसरा कदम 1993 में तब बढ़ाया जब न्यायिक नियुक्तियों में वर्षों की स्थापित प्रक्रिया, जिसमें राष्ट्रपति देश के मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर न्यायाधीशों की नियुक्ति करते थे, को पलट दिया। उस पारंपरिक व्यवस्था में राष्ट्रपति परामर्श को मानने को बाध्य नहीं थे, लेकिन नई व्यवस्था में मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया गया। इसी से कलेजियम व्यवस्था का जन्म हुआ।

● **राजेश बोरकर**

न्यायपालिका की विश्वसनीयता न टूटे

अक्सर जनता के मन में न्यायिक नियुक्तियों को लेकर संशय होता है, किंतु न्यायपालिका के प्रति आदर भाव के चलते वह कोई प्रश्न नहीं उठाती। ऐसे में न्यायपालिका को विचार करना चाहिए कि कहीं जनता का यह विश्वास टूट न जाए। संसद और कार्यपालिका तो जनता के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन न्यायपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? जनता किससे पूछे कि लंबित मुकदमों की संख्या घटाने के लिए न्यायपालिका ने क्या किया? विलंबित न्याय वस्तुत: न्याय से वंचित करना है- इस सिद्धांत की उपेक्षा क्यों की जा रही है? क्यों नियुक्तियों में पारदर्शिता का अभाव है? प्रश्न यह भी है कि लोकतंत्र में न्यायिक नियुक्तियों में जनता द्वारा निर्वाचित सरकार की भूमिका क्यों न हो? स्मरण रहे कि केवल न्यायपालिका ही ऐसी संस्था है जिसके चयन में जनता की प्रत्यक्ष भूमिका न होने के बावजूद उसकी आस्था बनी हुई है, लेकिन यदि उसके गठन में जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी समाप्त हो जाएगी तो जनता न्यायपालिका से पूर्णत: कट जाएगी। यह लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं होगा। एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, उत्तरदायी, पारदर्शी एवं जनोन्मुखी न्यायपालिका लोकतंत्र में अपरिहार्य है।

राजनीतिक पार्टियों को हर साल करोड़ों रुपए गुप्त चंदे के रूप में मिलता है, लेकिन पार्टियों को यह चंदा कौन दे रहा है, इसको लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सत्ता में जो पार्टी रहती है, वह औद्योगिक घरानों से मनमाना चंदा लेती है और उसका हिसाब भी नहीं देती है।

गुप्त चुनावी चंदे का दुरुपयोग...

सन् 2017 के बजट सत्र में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने जिस गुप्त चंदा (इलेक्टोरल बॉन्ड) को आधिकारिक सहमति दी थी, उसके नुकसान और दुरुपयोग को लेकर कयास लगते रहे हैं। ऐसे आरोप लग चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास 70 से 80 फीसदी तक गुप्त चंदा आ रहा है और वह इस चंदे का दुरुपयोग कर रही है। नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार पर पहले भी आरोप लगता रहा है कि उसने जल्दबाजी में विवादास्पद गुप्त चंदा अधिनियम को अन्य कानूनों की संसदीय प्रक्रिया के तहत मनमानी करके निर्णय लेते हुए इसे वैध बना दिया, जबकि चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके पक्ष में नहीं थे। जानबूझकर केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय की तरफ से कई गड़बड़ियों को नजरअंदाज करते हुए लोकसभा में यह बिल पास करके राज्यसभा को बाइपास करके इस बिल को पास किया गया, जो कि असंवैधानिक और गैर-कानूनी था। इस बिल को पास करने की चर्चा को अनौपचारिक चर्चा का नाम देकर जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने इसे पास किया, उसमें अज्ञात लोगों को शामिल किया गया।

केंद्र सरकार का यह कदम न केवल सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना था, बल्कि खुद केंद्र सरकार के कामकाज की नियमावली का उल्लंघन भी था। इस बिल को लेकर कानून मंत्रालय ने जो दो पन्नों का दस्तावेज तैयार किया, उससे पता चलता है कि सरकार ने दबे स्वर में इसे न्यायसंगत ठहराने की कोशिश की। हालांकि एक नियम यह भी है कि राजनीतिक दलों को सन् 1976 के बाद मिले विदेशी चंदे की अब जांच नहीं हो सकेगी। इस संबंध में भी सन् 2018 को वित्त विधेयक में 21 संशोधनों के बाद लोकसभा में संशोधित कानून बिना किसी चर्चा के ही पारित हो चुका है, जिसमें से एक संशोधित कानून विदेशी चंदा नियमन कानून 2010 है। जबकि पहले कानून के मुताबिक, राजनीतिक दलों पर विदेशी चंदा लेने से रोक थी। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने पहले वित्त विधेयक-2016 के जरिए विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) में संशोधन करके विदेशी चंदा लेने को भी आसान कर दिया था, जिसमें कहा गया कि सन् 1976 के बाद से मिले विदेशी चंदे की जांच नहीं होगी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल को मिला हो। इस संशोधन के बाद सभी राजनीतिक दल, खासकर भाजपा और कांग्रेस दोनों बच गए। क्योंकि सन् 2014 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन दोनों बड़े दलों को एफसीआरए कानून के उल्लंघन का दोषी ठहराया था। इसके लिए तत्कालीन वित्तमंत्री (अब स्व.) अरुण जेटली सबसे बड़े जिम्मेदार हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता व एनसीपीआरआई के सदस्य सौरव दास ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत इसकी जानकारी सरकार से हासिल की, जिससे पता चलता है कि किस तरह तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली ने संवैधानिक प्रावधानों की धज्जियां उड़ाते हुए इस विवादास्पद धन शोधन की प्रक्रिया को धन विधेयक की श्रेणी में डालकर संविधान के आर्टिकल 110 की धज्जियां उड़ाईं, जिसे पास कराने की कोई मजबूरी सरकार को नहीं थी। क्योंकि चंदा गुप्त रखने का कोई कारण नहीं था, लेकिन गुप्त चंदा योजना को फिर भी गुप्त रखा गया, ताकि लोगों को इसका अंदाजा न हो सके कि पार्टियों के पास इतना पैसा कहां से, क्यों और किस काम के लिए आता है। इसी के चलते चंदा लेने की इस प्रक्रिया को इतना गुप्त रखा गया कि केवल सरकार और बैंक को ही चंदा देने और लेने वाले के बारे में पता रहेगा, बाकी किसी को नहीं। इससे हुआ यह कि सरकार हर पार्टी को मिल रहे चंदे पर नजर तो रख सकती है, लेकिन अपनी पार्टी को मिल रहे गुप्त चंदे के बारे में किसी को कानोंकान हवा तक नहीं लगने दे सकती है। इससे जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है, वह तो अपना चंदा आसानी से पचा सकती है और चंदा देने वालों को लाभ भी पहुंचा सकती है, लेकिन अगर विपक्षी को चंदा किसी ने दिया, तो न तो विपक्ष उसका दुरुपयोग कर

राजनीतिक चंदे का दौर कैसे शुरू हुआ?

आज से करीब 40 साल पहले सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को रसीद बुक दी जाती थी जिसे लेकर वे घर-घर जाकर चंदा वसूल करते थे। उस समय छोटी-छोटी राशि में मिलने वाले चंदे की अहमियत थी। बाद में ऐसे दौर भी आए कि जो लोग फंडिंग करते थे उन्होंने सोचा कि अगर हमारे बलबूते पर इन पार्टियों के उम्मीदवार जीतते हैं तो हम खुद ही चुनाव लड़कर क्यों न जीतें। और वहीं से राजनीति में पैसे वाले लोगों का आगमन शुरू हुआ। अब बड़े-बड़े कॉर्पोरेट राजनीतिक दलों को करोड़ों रुपए का चंदा देते हैं और फिर सरकार को रिमोट से चलाने की कोशिश करते हैं जो कि आज के दौर में काफी आम हो गया है। उस समय चंदे को लेकर उतनी जागरूकता भी नहीं थी और न ही उतने प्रश्न होते थे। लेकिन चुनाव की फंडिंग और राजनीतिक दलों की आतंरिक संरचना हमेशा मुद्दा रहा है। इन पर बौद्धिक और अकादमिक बहस तो होती रहती थी लेकिन सतही चिंताओं को प्रकट करने के अलावा पार्टियों ने इस पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आज भी वह जनमत के दबाव में ही ध्यान देती है। धीरे-धीरे बदलाव आता गया और दबाव पार्टियों पर बनता गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट तथा चुनाव आयोग ने भी भूमिका निभाई कि वे लगातार अपने को पारदर्शी, लोकतांत्रिक और फंडिंग को लेकर भी लोगों के प्रति जवाबदेही दिखाएं।

सकेगा और न ही चंदा देने वालों की खैर होगी। और अब हो भी यही रहा है। जो कंपनियां, फर्में और व्यक्ति सत्तासीन पार्टी को चंदा दे रहे हैं, उनको मुनाफा ही मुनाफा हो रहा है और जो विपक्षी दलों को चंदा दे रहे हैं, उनके यहां छापा ही छापा हो रहा है।

अगर वित्त वर्ष 2018-19 की चुनाव आयोग के सामने भारतीय जनता पार्टी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट देखें, तो पता चलता है कि उसने इस वित्तीय वर्ष में करीब 1,450 करोड़ रुपए इस गुप्त चंदे से प्राप्त किए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ही वित्त वर्ष 2019-20 में चुनाव आयोग को बताया कि इस बड़ी पार्टी ने इस वित्तीय वर्ष में गुप्त चंदे के जरिए तकरीबन 2,555 करोड़ रुपए प्राप्त किए। जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 18 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने गुप्त चंदे के जरिए कुल 3,441 करोड़ रुपए ही प्राप्त किए। इसमें कांग्रेस ने केवल 318 करोड़ रुपए प्राप्त किए। जबकि तृणमूल कांग्रेस को 100 करोड़ रुपए, डीएमके को 45 करोड़ रुपए, शिवसेना को 41 करोड़ रुपए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 20 करोड़ रुपए, आम आदमी पार्टी को 17 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय जनता दल को केवल 2.5 करोड़ रुपए ही गुप्त चंदे के जरिए मिले। वहीं अकेले भारतीय जनता पार्टी वित्त वर्ष 2017-18 में 68 फीसदी और 2018-19 में 75 फीसदी गुप्त चंदा प्राप्त हुआ। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने वित्त वर्ष 2021-22 में 1,917 करोड़ रुपए से ज्यादा गुप्त चंदे के रूप में प्राप्त किए। जबकि शुरू में भारतीय जनता पार्टी को केवल 200 करोड़ रुपए ही गुप्त चंदे के जरिए मिले थे। लेकिन यह गुप्त चंदा भारतीय जनता पार्टी के खाते में धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते 2,500 करोड़ से ज्यादा हो गया।

ऐसा नहीं है कि गुप्त रूप से केवल राजनीतिक दलों को ही चंदा मिलता है। नेताओं को भी गुप्त चंदे के रूप में बहुत पैसा मिलता है। लेकिन चुनाव आयोग से लेकर केंद्र सरकार तक किसी ने अभी तक ऐसा नियम नहीं बनाया है कि नेताओं को मिले गुप्त चंदे की जांच की जाए या उसका हिसाब उनसे लिया जाए। चुने हुए नेता गुप्त चंदे और गैर-कानूनी तरीके से चंद दिनों में करोड़पति और अरबपति हो जाते हैं। बता दें कि जब गुप्त चंदे की प्रक्रिया को गोपनीय और आसान बनाया गया, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका विरोध कई आशंकाएं जताते हुए किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि गुप्त चंदे से भ्रष्टाचार बढ़ेगा, सरकार को सबसे ज्यादा चंदा मिलेगा, मोटा चंदा देने वालों को ज्यादा लाभ पहुंचाया जाएगा और लोग बढ़चढ़कर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे, ताकि उन्हें सरकार से लाभ मिल सके। गुप्त चंदे को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही नहीं, बल्कि चुनाव आयोग से लेकर कई नेताओं और समाज सुधारकों ने भी आपत्ति जताई है; लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी, जिसके फलस्वरूप राजनीतिक दलों को गुप्त रूप से जमकर चंदा मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर तो यहां तक आरोप हैं कि वह इस गुप्त चंदे के पैसों से विधायक खरीदने का काम भी करती है। आज व्यापारियों से लेकर, तमाम बड़े उद्योगपति गुप्त रूप से राजनीतिक दलों को गुप्त चंदा देकर मोटा लाभ कमाने में लगे हैं। जबकि चुनावी फंडिंग के नाम पर बना गुप्त चंदा कानून लोकतंत्र और देश के आम लोगों के लिए बिलकुल अच्छा नहीं है।

काले धन पर टिकी सफेदपोश राजनीति

राजनीतिक दलों के आर्थिक प्रबंधन का मुद्दा एक बेहद अहम मुद्दा है। दुनियाभर के परिपक्व और उभरते प्रजातांत्रिक देश राजनीति में धन के दुरुपयोग की समस्या से जूझ रहे हैं। एक राजनीतिक दल के संचालन के लिए धन बेहद जरूरी है, लेकिन चंदा प्राप्त करने का अनियंत्रित, अज्ञात और अपारदर्शी तरीका प्रजातंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। जहां एक ओर धन की कमी से जूझ रही साधनविहीन पार्टी लोगों तक अपनी पहुंच और अपनी बात पहुंचाने के लिए कई मुश्किलों का सामना कर रही होती है, वहीं दूसरी ओर अवैध तरीके से चंदा हासिल कर संपन्न दल फिजूलखर्ची और दिखावा कर लोगों को लुभाते हैं। फिर सत्ता में आने के बाद वे आम लोगों की दिक्कतों पर ध्यान देने के बजाय पार्टी के पोषकों के हितों का अधिक ख्याल रखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश भारत की अपनी समस्याएं हैं। यह बात समझने के लिए आपको कोई राजनीतिक पंडित होना आवश्यक नहीं है कि भारत की राजनीति भ्रष्टाचार, संरक्षणवादिता और वंशवाद से ग्रस्त है। अपने देश में भ्रष्टाचार की गाथा पर तो ग्रंथ लिखे जा सकते हैं।

विरोध की अनदेखी करके अपने हित में कानून पारित करने में पारंगत भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना हित इस कदर साधने में लगी है कि कोई भी कानून अपनी मर्जी से पास कर देती है। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले 20,000 से ज्यादा चंदा मिलने पर पार्टी द्वारा उसकी जानकारी देने की बाध्यता को खत्म करके अब 2,000 से ज्यादा का गुप्त चंदा लेने पर जानकारी देने की बाध्यता तय कर दी है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने चुनावी गुप्त चंदे अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक लेने की सीमा तय करने का प्रस्ताव भी रखा है।

इसके अलावा चुनाव आचरण नियम-1961 के नियम संख्या-89 में संशोधन लागू किया गया है, जिसके तहत एक उम्मीदवार को चुनाव से संबंधित रसीद और भुगतान के लिए एक खाता अलग खोलकर रखना होगा, जिसमें प्राप्त चंदे के बारे में पार्टी या नेता को चुनाव खर्च के लिए उस खाते में प्राप्त रकम के बारे में चुनाव आयोग को बताना ही होगा। इतने सख्त नियम होने के बाद भी राजनीतिक दल पारदर्शिता रखते होंगे, इसकी कम ही उम्मीद है। क्योंकि इस तरह से गुप्त चंदा मिलने और उसकी गोपनीयता बनाए रखने के चलते राजनीतिक दल इस चंदे का दुरुपयोग करते ही होंगे। क्योंकि अब इस गुप्त चंदे का हिसाब देना जरूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की यह खासियत है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने पूरे पत्ते कभी नहीं खोलती है। केंद्र में सरकार भाजपा की ही है और पीएम केयर फंड का हिसाब न देने से ही केंद्र सरकार की नीयत का पता चलता है, जो कि कायदे से सरकारी खाता है और उसमें पारदर्शिता बहुत ही आवश्यक है। राजनीति में ईमानदारी अब दूर की कौड़ी हो चुकी है। राजनीतिक भ्रष्टाचार के चलते ही हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरे तक फैल चुकी हैं। अगर देश में भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो सबसे पहले राजनीति के क्षेत्र से भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा।

● **विपिन कंधारी**

2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से बिसात बिछने लगी है। विपक्ष खंड-खंड नजर आ रहा है। उसके बावजूद दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को मात देकर सत्ता से बाहर किया जाएगा। अभी तक यह महज कपोल कल्पना लग रही है, क्योंकि बिना एक हुए विपक्ष भाजपा का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। हालांकि इन सबके बावजूद 2024 के चुनावी महाभारत में मंडल, कमंडल और आरोपों के बंडल की राजनीति गर्माने लगी है।

आरोपों के बंडल पर 2024 का चुनावी संग्राम

पिछले लोकसभा चुनावों के बाद यूं तो हर साल देश में कहीं न कहीं चुनावी महाभारत होती रही है, लेकिन अगले आम चुनाव से ठीक पहले का यह साल सियासी नजरिए से सबसे ज्यादा गरम साल साबित होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की लोकप्रियता और राजनीतिक परिपक्वता के बल पर लोकसभा चुनावों में हैट्रिक की तैयारी कर रही है, तो वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा की सफलता से उत्साहित होकर भाजपा की हैट्रिक न बनने देने की तैयारियों में जुट गई है। जबकि भाजपा विरोधी क्षेत्रीय दल अपने-अपने इलाकों में अपनी ताकत बढ़ाकर अगले लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा को रोकने और कांग्रेस को दबाव में लेने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।

इस चुनावी महाभारत में जहां भाजपा मोदी सरकार के 10 सालों के कामकाज और भविष्य का भारत कैसा होगा अपने इस एजेंडे की पैकिंग में अपने सबसे बड़े और धारदार सियासी हथियार हिंदुत्व को फिर से आजमा कर कमंडल राजनीति को गरम करेगी, तो उसकी काट के लिए सामाजिक न्याय के योद्धा राजद, जद(यू) और समाजवादी पार्टी ने हिंदू ध्रुवीकरण की काट के लिए जातीय जनगणना और रामचरित मानस विवाद के जरिए पिछड़ों के ध्रुवीकरण की मंडल राजनीति का दांव खेलने में जुट गए हैं। उधर कमंडल और मंडल से इतर कांग्रेस ने भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ मुद्दों का एक बंडल तैयार किया है, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, छोटे उद्योगों मझोले व्यापार और दुकानदारों की तकलीफ, मजदूरों की रोजमर्रा की दिक्कतों और सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना और कॉरपोरेट भ्रष्टाचार के जरिए अमीर-गरीब की गहराती खाई जैसे मुद्दे शामिल हैं।

लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दिए गए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस अंदाज में एक तरफ अडाणी समूह को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब देने की बजाय उनका संज्ञान ही नहीं लिया और अपने भाषण में उन्होंने बेहद आक्रामक और व्यंग्यात्मक अंदाज में कांग्रेस सरकारों के जमाने में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र करते हुए अपनी सरकार के कामकाज और उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए इस साल होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अगले साल के लोकसभा चुनावों की राजनीतिक पिच तैयार कर दी। अपने भाषण में उन्होंने न सिर्फ विपक्ष को आईना दिखाया, बल्कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को सियासी लाइन भी दे दी कि अब उन्हें राजनीतिक विमर्श में क्या करना है और क्या बोलना है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की लाइन ऐसी सियासी पैकेजिंग हैं,

विपक्ष लगातार भाजपा पर हमलावर

राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी इसी तरह प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार दोनों को घेरा। हालांकि दोनों ही सदनों में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के आरोपों पर जवाब देना तो दूर उनका संज्ञान ही नहीं लिया और दोनों सदनों में कांग्रेस नेताओं के भाषणों के कई अंश कार्यवाही से हटा दिए गए। इसके बावजूद कांग्रेस ने अपने आरोपों की धार कम नहीं की और सदन के बाहर लगातार कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख जयराम रमेश और अन्य प्रवक्ताओं ने प्रधानमंत्री से अडाणी प्रकरण को लेकर सवाल भी पूछे। इसी कड़ी में कांग्रेस ने 17 फरवरी को देश के 23 बड़े शहरों (राज्यों की राजधानियों) में अपने प्रमुख नेताओं को भेजकर इस मुद्दे पर संवाददाता सम्मेलन करके केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोपों की बौछार की। कांग्रेस अपने इन आरोपों को शहर-शहर, नगर-नगर और गांव-गांव ले जाने की तैयारी कर रही है।

जिसमें विकास सुशासन और उपलब्धियों के चमकदार खोल के भीतर ठोस हिंदुत्व है जो आगे आने वाले सभी चुनावों में भाजपा का सबसे धारदार हथियार होगा।

दरअसल भारतीय जनता पार्टी और पूरा संघ परिवार दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। एक सरकार और पार्टी की खुली और अधिकारिक रणनीति और दूसरी गैर पार्टी संगठनों यानी संघ परिवार के अनुषांगिक संगठनों जिन्हें राजनीति की भाषा में नॉन स्टेट एक्टर्स भी कहा जा सकता है, के जरिए छुपी हुई समानांतर रणनीति। इसके तहत विभिन्न संघ परिवार से जुड़े विभिन्न गैर भाजपा संगठनों द्वारा लगातार हिंदुत्व और हिंदू ध्रुवीकरण को गरम करते हुए संघ परिवार की कमंडल राजनीति को आगे बढ़ाते रहना। इसीलिए एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी उनके मंत्री और भाजपा केंद्र सरकार के पिछले करीब 10 साल की उपलब्धियों, कामकाज का जोरशोर से प्रचार-प्रसार करके जनता को बताएंगे कि किस तरह भारत की असली विकास यात्रा 2014 से शुरू हुई है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए संसद के दोनों सदनों में अपनी सरकार की उपलब्धियों, कामकाज और नीतियों का विस्तार से जिक्र करते हुए 2004 से 2014 के कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए सरकार के कार्यकाल को लॉस्ट डिकेड यानी खोया हुआ दशक कहा और 2014 से 2024 के समय को इंडिया डिकेड यानी भारत दशक की संज्ञा दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस शासन के दौरान की विफलताओं को जमकर गिनाया और अपनी सरकार के खिलाफ उठने वाले सवालों को उन्होंने भारत की विकास यात्रा को बाधित करने की साजिश बताया तो भाजपा ने इसके तार विदेशों से जुड़े होने की बात कही। अपने भाषण से प्रधानमंत्री ने भाजपा और उसके कार्यकर्ताओं को 2024 के चुनावों का एजेंडा दे दिया है। प्रधानमंत्री की इसी लाइन पर भाजपा 2023 के सभी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों की माहौलबंदी (नेरेटिव) बनाएगी।

दूसरी रणनीति के तहत जनवरी 2024 तक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पूरा होने का अतिशय प्रचार, गौवध और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर लगातार माहौल गरम रखना, कुछ साधू संतों के द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान और विहिप बजरंग दल जैसे संगठनों और भाजपा के भी हिंदुत्ववादी सांसदों नेताओं द्वारा इसका समर्थन करते हुए हिंदुओं में यह संदेश देना कि जिस तरह 2014 के बाद से लगातार केंद्र और राज्यों की भाजपा सरकारों ने लगातार हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया है, तीन तलाक, अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों को हल किया है। उसी तरह अगर भारत को हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ आगे ले जाना है, तो 2024 में भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार को और भी ज्यादा बड़े बहुमत से जिताने की जरूरत है। पिछले साल हुए उत्तराखंड और गुजरात विधानसभा के चुनावों में जिस तरह समान नागरिक कानून बनाए जाने का वादा भाजपा ने किया वह इसका ही संकेत है।

ऐसा भी नहीं है कि यह दोनों रणनीतियां एक दम अलग-अलग चलेंगी। बल्कि जरूरत पड़ने पर इनको एक-दूसरे से मिलाया भी जा सकता है। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे और संघ परिवार हिंदुत्व के एजेंडे को गरम करेगा, भाजपा और सरकार भी अपने कामकाज के साथ-साथ उसके स्वर में स्वर मिलाएंगे। केंद्रीय गृहमत्री अमित शाह ने जिस तरह त्रिपुरा के चुनावों में प्रचार के दौरान पहले जनवरी 2024 तक राम मंदिर का निर्माण पूरा होने जाने की घोषणा की और फिर यह ऐलान भी किया कि 2024 के चुनावों में भाजपा के सामने विपक्ष की तरफ से कोई चुनौती नहीं है और भाजपा पहले से भी ज्यादा बड़े बहुमत से केंद्र में तीसरी बार लगातार सरकार बनाएगी, यही बताता है कि भाजपा अगला चुनाव विकास और हिंदुत्व की दुधारी तलवार से विपक्ष का मुकाबला करेगी।

अब सवाल है कि क्या विपक्ष हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। भाजपा की ही तरह विपक्ष में भी दोहरी रणनीति पर काम हो रहा है। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा से उत्साहित कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ आरोपों का बंडल लेकर मैदान में उतर आई, तो दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की विचारधारा से निकली मंडलवादी पार्टियां समाजवादी पार्टी, जनता दल(यू) और राष्ट्रीय जनता दल पिछड़ों के ध्रुवीकरण की मंडल राजनीति के जरिए भाजपा के हिंदुत्व की काट की तैयारी में जुट गई हैं। जहां अपनी भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान लगातार हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ राहुल गांधी नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा देते हुए बेरोजगारी, महंगाई, छोटे उद्योगों और व्यापारियों, किसानों, मछुआरों, मजदूरों के मुद्दे उठाते रहे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद संसद में उन्होंने अदाणी प्रकरण पर सीधे केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया और यह साबित करने की कोशिश की कि मोदी सरकार अपने चहेते उद्योगपतियों के हितों के लिए देश के हितों को दांव पर लगा रही है।

● **इन्द्र कुमार**

मंडल राजनीति के दूसरे चरण की शुरुआत

विपक्ष का दूसरा धड़ा जातीय ध्रुवीकरण की मंडल राजनीति के दूसरे चरण की शुरुआत कर चुका है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने सबसे पहले रामचरित मानस की एक चौपाई को लेकर शूद्रों (पिछड़ों और दलितों) और महिलाओं के अपमान का मुद्दा उठाया। बिहार से शुरू हुए इस विवाद को और ज्यादा हवा दी उप्र के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने न सिर्फ रामचरित मानस की कुछ चौपाइयों पर एतराज जताते हुए उन्हें पिछड़ा, दलित और महिला विरोधी बताया, बल्कि मौर्य के कुछ समर्थकों ने मानस के पन्ने फाड़कर उन्हें जलाया भी। हालांकि इसे लेकर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया और गिरफ्तारियां भी कीं। लेकिन स्वामी प्रसाद हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिस तरह इस मुद्दे पर बिना कुछ बोले स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ दिया है, उससे साफ संकेत है कि समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह पिछड़ों के ध्रुवीकरण की राजनीति पर उतर चुकी है। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को बहुत उम्मीद थी कि योगी सरकार से नाराज सवर्णों खास कर ब्राह्मणों के एक हिस्से का वोट सपा को मिलेगा।

ईडी बिगाड़ेगी चुनावी खेल

एक काफी लोकप्रिय मुहावरा है- लोहा गर्म है, हथौड़ा मारा जाए। इसका मतलब सही मौके का इंतजार कर वार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की राजनीति में माहौल भी ऐसा बना है कि आंदोलनकर्मी सरकार पर लगातार बरस रहे हैं। उधर, भाजपा भी हमलावार हो गई है। इसके साथ ही ईडी के लगातार छापे पड़ रहे हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है की ईडी प्रदेश में कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है।

छत्तीसगढ़ में ईडी ने विधानसभा चुनाव के ठीक एक साल पहले दस्तक दी थी। इसके बाद से लगातार 5 महीने से ईडी की कार्रवाई जारी है। पहले कोयला कारोबारियों और प्रशासन के बड़े अफसरों को ईडी ने गिरफ्तार किया। अब ईडी कांग्रेस के नेताओं से पूछताछ कर रही है। ये सिलसिला पिछले 20 दिन से चल रहा है। इससे छत्तीसगढ़ की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईडी के एक्शन से कांग्रेस पार्टी बड़ी मुसीबत में फंस गई है और क्या इससे विधानसभा चुनाव में असर पड़ेगा। दरअसल 11 अक्टूबर 2022 को ईडी ने छत्तीसगढ़ में एक साथ कई जगहों पर रेड डाली थी। इसके बाद से लगातार 5 महीने तक यानी 2023 में अब तक ईडी की रेड जारी है। पिछले महीने 20 फरवरी को ईडी ने एक साथ 6 से अधिक कांग्रेस पार्टी के पॉवरफुल नेताओं के घर रेड डाली थी। इसके बाद अब नेताओं को ईडी लगातार समन भेजकर पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुला रही है। इस दौरान ईडी के अफसर 8-8, 10-10 घंटे पूछताछ कर रहे हैं।

गत दिनों कांग्रेस के नेता विनोद तिवारी को ईडी ने पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया था। इससे पहले एजेंसी देवेंद्र यादव, गिरीश देवांगन, कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल को पूछताछ के लिए बुला चुकी है। दूसरी तरफ पिछले 10 दिनों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। रायपुर में ईडी 5 दफ्तर के ठीक सामने कांग्रेस ने पंडाल लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस केंद्र की भाजपा सरकार लगातार ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं को परेशान करने आरोप लगा रही है। ईडी की पूछताछ से बाहर निकले विनोद तिवारी ने कहा कि ईडी ने मुझसे 10 घंटे पूछताछ की। उनके खिलाफ हुए कार्रवाई को विनोद तिवारी ने राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की आय से अधिक संपत्ति की शिकायत करना गुनाह बन गया है। अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह में बार-बार करूंगा। जब तक रमन सिंह अपनी आय से अधिक संपत्ति का स्रोत छत्तीसगढ़ की ढाई करोड़ जनता को नहीं बता देते तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी पहले भी लड़े हैं आगे भी लड़ेंगे।

इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब से केवल 8 महीने बाद राज्य में चुनाव हो सकते हैं। चुनावी माहौल में कांग्रेस के नेताओं के घर ईडी की रेड से जनता के बीच कांग्रेस पार्टी की छवि को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। इस मामले में राजनीतिक विशेषज्ञ बाबूलाल शर्मा ने कहा कि रेड का जो मैसेज जनता के बीच जाएगा और जनता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को किसान मुख्यमंत्री मानती है और केंद्र सरकार का तरीका गलत लगता है और जनता मान लेती है कि सताया जा रहा है तो इस आधार पर कांग्रेस को फायदा हो सकता है। वहीं कुछ राजनीतिक पंडितों का मानना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी किसान पुत्र और छत्तीसगढ़िया वाद के छवि के साथ घर-घर तक पहुंचने में कितना सफल होते हैं इस पर निर्भर करता है।

आपको बता दें कि ईडी ये कार्रवाई कोयला ट्रांसपोर्टिंग में गड़बड़ी के आरोप पर कर रही है। इसमें कोयला कारोबारियों की शासन के बड़े अफसरों की तरफ से मदद करने का आरोप है। अवैध लेवी के जरिए मिले पैसे का राजनीतिक इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है। इसलिए ये मामला छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं के लिए गले की फांस बन गया है। ईडी कोयला ट्रांसपोर्टिंग में गड़बड़ी के आरोप के पीछे सरकार के बड़े अफसर और कांग्रेस नेताओं के संबंध तलाश रही है। इसलिए ये मामला बड़ा हो गया है।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

घोटाले में अब तक 9 लोगों की हो चुकी गिरफ्तारी

11 अक्टूबर 2022 में राज्य में कोयला कारोबार से जुड़े कारोबारियों और रायपुर में सस्पेंड आईएएस समीर विश्नोई के यहां भी रेड की कार्रवाई की गई थी। इसके बाद ईडी ने समीर विश्नोई और 3 कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद दिसंबर 2022 में मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ अफसर सौम्या चौरसिया को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है। इसके बाद 15 दिसंबर को उन्हें सचिवालय से निलंबित कर दिया गया था। 11 दिसंबर को इसी मामले में ईडी ने आईएएस अधिकारियों समेत कुछ अन्य की 152.31 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति कुर्क की थी। इससे पहले इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, उनके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी, छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई और एक अन्य कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल शामिल हैं। ये सभी रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद हैं और रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेशी चल रही है।

पवार की चाल से फंसी शिवसेना

महाराष्ट्र में ऑपरेशन शरद पवार शुरू हो चुका है। कांग्रेस और शिवसेना को पीछे छोड़कर शरद पवार आगे निकल गए हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद एनसीपी प्रमुख विपक्षी पार्टी बन गई है। जबकि 2019 के चुनाव नतीजों में एनसीपी तीसरे नंबर की पार्टी थी। अगले विधानसभा चुनाव में शरद पवार का लक्ष्य इन दोनों पार्टियों को पीछे छोड़कर भाजपा के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बनना है। ताकि अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बने तो मुख्यमंत्री पद पर एनसीपी का दावा हो, और अगर सरकार न बने, तो शिवसेना टूटने के बाद मिला प्रमुख विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल रहे।

महाराष्ट्र में मराठी वोटरों को लेकर शिवसेना और एनसीपी दोनों की दावेदारी रही है, लेकिन 1999 को छोड़कर दोनों पार्टियों का वोट प्रतिशत भी लगभग बराबरी का रहा। 1999 में जब एनसीपी पहली बार चुनाव लड़ी थी, तो उसे 22.6 प्रतिशत वोट और 58 सीटें मिलीं थीं। पिछले विधानसभा चुनाव में शिवसेना को 16.41 प्रतिशत वोट और 56 सीटें मिली थीं, तो एनसीपी को 16.71 प्रतिशत वोटों के साथ 54 सीटें मिली थीं। यानी एनसीपी और शिवसेना में बराबर की टक्कर थी और मराठा वोटों के लिए दोनों पार्टियां प्रतिस्पर्धा में रहती हैं। तो सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या शरद पवार ने शिवसेना को कमजोर करने के लिए उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवाने का दांव खेला था। शरद पवार भले ही प्रधानमंत्री पद के सिर्फ उम्मीदवार ही बने रह गए, कभी वह लक्ष्य हासिल नहीं कर सके, लेकिन वे राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। कांग्रेस छोड़ने के तीन साल बाद 2002 में उपराष्ट्रपति पद पर भाजपा के उम्मीदवार भैरोसिंह शेखावत को जितवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। भैरोशिंह शेखावत के सामने महाराष्ट्र के सुशील कुमार शिंदे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। पवार ने नजमा हेपतुल्ला के घर पर बैठकर कई कांग्रेसी सांसदों को शेखावत को वोट देने के लिए राजी किया था।

1999 में एक वोट से वाजपेयी सरकार गिरने के बाद जब उन्होंने विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस छोड़कर एनसीपी बनाई थी, तो किसने सोचा था कि एक दिन देश में कांग्रेस इतनी कमजोर हो जाएगी कि विपक्षी एकता के लिए लोग शरद पवार की तरफ देखेंगे। अगर शरद पवार ने एनसीपी नहीं बनाई होती, तो उन्हें अपनी या अपनी बेटी की लोकसभा सीट बचाना ही मुश्किल हो जाता। आज वह अपने गृह राज्य महाराष्ट्र में कांग्रेस को पीछे छोड़कर आगे निकल चुके हैं। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में उसी कांग्रेस से बराबरी के स्तर पर गठबंधन किया, जिसे उन्होंने विदेशी मूल के मुद्दे पर ठुकराया था। दोनों पार्टियों ने 125-125 सीटों पर चुनाव लड़ा था। गठबंधन से एनसीपी को ज्यादा फायदा हुआ। कांग्रेस 42 सीटों से बढ़कर 44 पर आ गई थी, लेकिन एनसीपी 41 से बढ़कर 54 पर पहुंच गई थी। इसी कारण आज महाराष्ट्र में कांग्रेस नहीं, बल्कि एनसीपी प्रमुख विपक्षी दल है। यानी महाविकास आघाड़ी को शरद पवार ही लीड करेंगे। शरद पवार ने नेतृत्व संभालने का यह लक्ष्य उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवाकर और शिवसेना का विभाजन करवाकर हासिल किया है।

1999 में जब एनसीपी ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था, तो वह भाजपा से आगे निकल गई थी। तब भाजपा 56 सीटों के साथ चौथे नंबर की पार्टी थी, और एनसीपी 58 सीटों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी थी। कांग्रेस 75 सीटों के साथ पहले नंबर की पार्टी बनी हुई थी और 69 सीटों के साथ शिवसेना दूसरे नंबर पर थी। 20 साल बाद 2019 के चुनाव के बाद बनी विधानसभा में स्थिति एक दम बदल चुकी है। 1999 में पहले नंबर की कांग्रेस 44 विधायकों के साथ अब चौथे नंबर पर है, और चौथे नंबर की भाजपा 105 विधायकों के साथ अब पहले नंबर पर है। चुनावों में तीसरे नंबर पर आई एनसीपी शिवसेना टूटने के बाद अब विधानसभा में दूसरे नंबर की पार्टी है। उद्धव सरकार बनने से सबसे ज्यादा फायदा एनसीपी और शरद पवार को हुआ और सबसे ज्यादा नुकसान शिवसेना और उद्धव ठाकरे को हुआ। इसलिए जब चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे से उनकी पार्टी का नाम शिवसेना और चुनाव निशान धनुष बाण छीन कर एकनाथ शिंदे को दे दिया, तो शरद पवार ने उद्धव ठाकरे की तरह चुनाव आयोग की आलोचना नहीं की। बल्कि कहा कि उद्धव ठाकरे को नए नाम और नए निशान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब आने वाले किसी भी चुनाव में शिवसेना के मराठी वोटों का विभाजन शरद पवार को पुन: बड़े मराठी लीडर के तौर पर स्थापित करेगा।

महाराष्ट्र की ऐसी 55-60 सीटें हैं, जहां पर 1999 से ही एनसीपी और शिवसेना की आमने-सामने टक्कर हुआ करती थी। पहली बार दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो उन 55-60 सीटों पर दोनों दलों की दावेदारी होगी। लेकिन फिलहाल शरद पवार ने इस साल होने वाले 10 महानगर पालिकाओं के चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से आगे निकलने की मुहिम शुरू कर दी है। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना कमजोर पड़ गई है और कांग्रेस आपसी फूट का शिकार है, तो महाविकास आघाड़ी में इन दोनों दलों से आगे निकलने का यह स्वर्णिम मौका है।

● **बिन्दु माथुर**

सधी पारी खेल रहे शरद पवार

बाल ठाकरे की गलती से सबक सीखकर वह अपने पारिवारिक वारिसों में संतुलन बनाकर चल रहे हैं। बाल ठाकरे के जीवित रहते ही शिवसेना विभाजित हो गई थी, क्योंकि उन्होंने पुत्र मोह में राजनीति में ज्यादा सक्रिय अपने भतीजे राज ठाकरे का दावा खारिज करके उद्धव ठाकरे को पार्टी प्रमुख बना दिया था। अगर लोकसभा चुनावों और अगले विधानसभा चुनाव तक मौजूदा राजनीतिक समीकरण बने रहते हैं, तो इसका फायदा भाजपा और एनसीपी को होगा, जबकि कांग्रेस और शिवसेना के दोनों गुट कमजोर होंगे। वैसे यह ट्रेंड 2019 में ही शुरू हो चुका था। मौका देख इस उम्र में भी उन्होंने महाराष्ट्र के दौरे तेज कर दिए हैं। युवा मराठाओं में पार्टी की पैठ बनाने के लिए वह अपने पोते रोहित पवार को आगे ला चुके हैं, और उनके दौरे भी तेज हो गए हैं। पवार का लक्ष्य महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करने की बजाय एनसीपी की ताकत बढ़ाने का है, ताकि उनके बाद उनका कुनबा राजनीति में वर्चस्व बनाए रख सके। वह इस दिशा में रणनीति के तहत गोटियां फिट कर रहे हैं।

कांटों भरी राह पर भाजपा

राजस्थान में नेता विपक्ष गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान भाजपा नेताओं को चौंका दिया है। जिस राज्य में कुछ महीनों बाद ही चुनाव होने वाले हों उसी राज्य के 79 साल के नेता विपक्ष को राज्यपाल बनाकर भाजपा नेतृत्व ने राज्य में होने वाले भावी बदलावों के संकेत दे दिए हैं। अगर ऐसा है तो राजस्थान की दिग्गज नेता वंसुधरा राजे के लिए आगे की राह आसान नहीं रहने वाली है। इस बात की संभावना है कि अगले कुछ दिनों में राजस्थान में नेता विपक्ष की नियुक्ति भाजपा हाईकमान कर देगा। भाजपा की ओर से नेता विपक्ष कौन होगा अभी यह तय नहीं है, लेकिन दावेदार कई हैं और कई खेमे भी हैं। भाजपा के लिए नेता विपक्ष की नियुक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से मुख्यमंत्री के चेहरे का संकेत मिलेगा। नेता विपक्ष के चेहरे से पार्टी की खेमेबंदी के समीकरण भी बदलेंगे। पार्टी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पहले से ही खेमेबंदी जारी है। भाजपा में अभी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, वरिष्ठ नेता ओम माथुर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सांसद किरोड़ीलाल मीणा, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के अपने खेमे हैं। इन खेमों के अलावा भी कई नेताओं के अपने खेमे हैं। कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद इन खेमों के नेताओं में उम्मीद जगी है। हालांकि इन सभी खेमों में वंसुधरा का खेमा सबसे भारी है, भले ही मोदी और शाह ने उन्हें किनारे लगाने की पूरी कोशिश क्यों न की हो।

राजस्थान की सबसे दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वंसुधरा राजे सिंधिया की कोशिश होगी कि वह अपने गुट के किसी नेता को विपक्ष के नेता पद पर बिठाएं। वंसुधरा को नेता विपक्ष बनाने की मांग वंसुधरा के समर्थकों की ओर से शुरू हो गई है लेकिन वंसुधरा खुद विपक्ष का नेता बनने को तैयार होगी, इसकी संभावना कम है। कुछ भाजपा नेताओं का मानना है कि वंसुधरा की नजर नेता विपक्ष की बजाय चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष पर है। वे चाहती हैं कि अगले चुनाव में टिकटों के चयन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहे इसके लिए वंसुधरा के लिए चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष का पद नेता प्रतिपक्ष से ज्यादा महत्व रखता है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री रहते वंसुधरा की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से अनबन की खबरें लगातार सुर्खियों में रहती थीं। अमित शाह ने बतौर अध्यक्ष वंसुधरा पर पूरी लगाम लगा दी थी और 2018 के विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में वंसुधरा को नजरअंदाज किया गया। अपनी पसंद के उम्मीदवारों को टिकट देने के बाद भी केंद्रीय नेतृत्व ने 2018 में राजस्थान में भाजपा की हार का ठीकरा वंसुधरा के सिर पर फोड़ दिया और उनके तमाम समर्थकों की मांग के बाद भी वंसुधरा को नेता विपक्ष नहीं बनाया गया। उसके बाद पहली बार विधायक बने सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया जो लगातार वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों को किनारे करने में लगे रहे। इस कारण पिछले चार साल विपक्ष में रही भाजपा कांग्रेस सरकार को घेरने की बजाय आपसी गुटबाजी में बंटी रही। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच खिंची तलवारों के बाद भी भाजपा अपने लिए कोई अवसर नहीं बना सकी। गहलोत सरकार के विरोध में निकली जन आक्रोश यात्रा तो बुरी तरह विफल रही। लेकिन मोदी और शाह अब राजस्थान को लेकर गंभीर है और भाजपा की कमजोर स्थिति से चिंतित भी हैं। इसलिए राजस्थान को लेकर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व फूंक-फूंक कर कदम उठा रहा है।

भाजपा का केंद्रीय संगठन मोदी और शाह की मजबूत पकड़ में है, ऐसे में नए नेता विपक्ष से लेकर अगले विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला मोदी और शाह ही लेंगे। लेकिन नेता विपक्ष की रेस हो, चुनाव प्रचार अभियान की प्रमुख बनने की रेस हो या मुख्यमंत्री की दौड़ हो, वसुंधरा राजे सबसे आगे हैं। लेकिन वंसुधरा को लेकर भाजपा हाईकमान ने कौनसी जिम्मेदारी तय की है यह कहना अभी मुश्किल है। फिर भी, एक बात तय है कि भाजपा राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से बचेगी और मोदी के चेहरे और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। वसुंधरा के विरोधी नेता यही चाहते हैं। क्योंकि वसुंधरा के अलावा किसी अन्य प्रदेश नेता की इतनी लोकप्रियता नहीं है कि अपने चेहरे पर राजस्थान का चुनाव जीत सके। इसलिए वे सभी नेता बार-बार मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव से कुछ माह पहले राजस्थान की विकट परिस्थितियों में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना कितना उचित होगा, यह कहना कठिन है। पिछले दिनों जिस तरह से प्रधानमंत्री ने राजस्थान में रैलियां और कार्यक्रमों की शुरुआत की है, उससे तो यही लग रहा है कि मोदी को केंद्र में रखकर ही चुनाव लड़ने की तैयारी है। जिन बड़े पदों पर फैसले होने हैं, इनमें प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और चुनाव अभियान समिति के प्रमुख का पद शामिल हैं। इस समय विधानसभा में भाजपा की तरफ से विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ हैं, जो राजपूत हैं। अध्यक्ष सतीश पूनिया हैं, जो जाट हैं। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर हैं, जो ब्राह्मण हैं। ऐसे में जातीय संतुलन के हिसाब से भी पार्टी निर्णय करेगी।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

गहलोत की लोकप्रियता बरकरार

भाजपा का सियासी ट्रेंड रहा है कि किसी को नेता विपक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाती है तो जरूरी नहीं कि वह अगले चुनाव में पार्टी के सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री बनाया जाए। 2003 और 2013 के चुनाव के बाद भाजपा जब सत्ता में आई तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनीं। दोनों ही बार चुनाव से पहले विधानसभा में नेता विपक्ष के पद पर गुलाबचंद कटारिया थे। 2003 और 2013 से पहले वसुंधरा राजे को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और फिर सत्ता में आने के बाद उनको दोनों बार मुख्यमंत्री बनाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का प्रदेश में व्यापक जनाधार है। विपक्ष में रहकर चुनावी साल में सत्ताविरोधी लहर को भाजपा के पक्ष में करके रिजल्ट लाने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन केंद्र की शह पर प्रदेश अध्यक्ष द्वारा लगातार वंसुधरा का विरोध उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने वंसुधरा के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वहीं, पूनिया की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के कारण अन्य सभी नेता उनसे भी कट गए हैं। जहां वसुंधरा का जनाधार है, वहीं अन्य सभी प्रदेश नेता मोदी और शाह से चुनाव जिताने की उम्मीद कर रहे हैं। मोदी और शाह के सर्वे में जनता में अशोक गहलोत की लोकप्रियता बरकरार है। राजस्थान में चुनाव सिर पर हैं, ऐसे में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व प्रदेश के नेताओं की अति महत्वाकांक्षा और आपसी संघर्ष से कैसे निपटता है यह आने वाला समय ही बताएगा। समय पर निर्णय नहीं हुआ तो भाजपा के लिए सत्ता में वापसी आसान नहीं होगी। और उसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ना तय है।

भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरु कर दी है और उसकी नजर उप्र पर है। 2024 के चुनाव में भाजपा ने उप्र में सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट तय कर रखा है, जिसके लिए 2019 में हारी हुई सीटों पर जीत का परचम फहराने की रणनीति का जिम्मा सुनील बंसल को सौंपा गया है। उन्होंने गत दिनों लखनऊ में बैठक कर रणनीति भी बनाई।

सुनील बंसल की फिर उप्र वापसी

दिल्ली की सत्ता तक जाने वाला रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। लोकसभा चुनाव में उप्र देश की दिशा तय करता है, क्योंकि सूबे में 80 लोकसभा सीटें है। 2014 की अपेक्षा 2019 के चुनाव में भाजपा को कम सीटें मिलीं, पर 2024 में भाजपा ने सूबे की सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट तय किया है। पार्टी देश की सत्ता पर लगातार तीसरी बार काबिज होने और उप्र के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी तरह का कोई भी सियासी रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में भाजपा ने एक बार फिर सुनील बंसल को उप्र में मिशन-2024 की अहम जिम्मेदारी सौंपी है?

भाजपा उप्र में आगामी लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने की रणनीति पर काम कर रही है। भाजपा का मिशन-2024 के लिए सबसे ज्यादा फोकस 2019 में उप्र की हारी हुई लोकसभा सीटों पर है, जिसे अगले साल 2024 में जीतने के लिए पार्टी ने अभी से मशक्कत शुरू कर दी है। उप्र के मिशन-80 लक्ष्य के मद्देनजर हारी हुई 14 लोकसभा सीटों के लिए भाजपा पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर रही है, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी सुनील बंसल के कंधों पर डाली गई है। इसके अलावा भाजपा ने हारी हुई सीटों पर प्रभारी बनाए हैं, जो बंसल के मार्गदर्शन में काम करेंगे।

उप्र को लेकर भाजपा काफी संजीदा हो गई है। लोकसभा चुनाव के लिए मिशन-80 के लक्ष्य के मद्देनजर हारी हुई 14 सीटों के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है। भाजपा ने इन सीटों पर संयोजक और सह संयोजक नियुक्त किए हैं। पार्टी ने 3-3 लोकसभा सीटों के लिए कलस्टर बनाकर प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। भाजपा की इस रणनीति को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को कमान सौंपी गई है, जिन्होंने 2 मार्च को प्रदेश मुख्यालय पर हारी हुई 14 सीटों को जीतने के लिए पदाधिकारियों के साथ मंथन किया।

2024 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई 14 सीटों पर जीत के लिए भाजपा संगठन की ओर से अमरपाल मौर्य को संयोजक, कलावती सिंह और विजय शिवहरे को सह संयोजक नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर प्रभार राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को दिया गया है। पार्टी पदाधिकारियों को प्रभारी नियुक्त करते हुए राज्यमंत्री जसवंत सिंह और मुकुट बिहारी वर्मा को जिम्मदारी दी गई है। भाजपा ने पहले से चार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अश्वनी वैष्णव, जितेंद्र सिंह और अन्नपूर्णा देवी को अलग-अलग सीटों का प्रभार दिया है।

बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने उप्र की 80 में से 73 सीटें जीती थीं। भाजपा 71 और अनुप्रिया पटेल की अपना दल ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन 2019 के चुनाव में सपा-बसपा-आरएलडी गठबंधन के चलते भाजपा का समीकरण गड़बड़ा गया था। ऐसे में भाजपा गठबंधन 80 लोकसभा सीटों में से 64 सीटें ही जीत सका था। इस तरह से भाजपा ने 2014 की जीती अपनी 9 सीटें 2019 में गंवा दी थी।

लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा को बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना इन 16 सीटों पर हार मिली थी। इन 16 सीटों में से 10 बसपा, 5 सपा और 1 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन भाजपा ने उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर की सीट पर जीत हासिल की थी। इस तरह से अब भाजपा का फोकस 14 सीटों पर है, जिसके लिए अपने अहम नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उप्र में भाजपा को जीत दिलाने का ट्रैक रिकार्ड सुनील बंसल का काफी शानदार रहा है। उप्र के संगठन महामंत्री पद पर रहते हुए सुनील बंसल ने 2014 व 2019 के लोकसभा और 2017 व 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को शानदार जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा की थी। पिछले साल भाजपा ने सुनील बंसल को उप्र संगठन महामंत्री से प्रमोशन करके राष्ट्रीय महामंत्री का जिम्मा सौंपा था और उन्हें तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और ओडिशा का प्रभारी बनाया गया।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

बंसल का उप्र में जीत का ट्रैक रिकॉर्ड

भाजपा को उप्र में एक के बाद एक ऐतिहासिक सफलताएं दिलाने वाले सुनील बंसल को गृहमंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को उप्र से बड़ी जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने उप्र में 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह के साथ उप्र संगठन को दुरुस्त करते हुए चुनावी रणनीति तय की थी। सुनील बंसल ने 2014 लोकसभा चुनाव के बाद 2017 उप्र विधानसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव और फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दिलाने का काम किया है। उप्र में 2014 से पहले पार्टी संगठन की स्थिति बहुत दयनीय थी, लेकिन सुनील बंसल ने बूथ स्तर पर संगठन के ढांचे को मजबूत किया। सुनील बंसल की राजनीतिक कुशलता और उप्र की नब्ज को समझने की वजह से राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जातीय जनगणना पर सियासत

बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना की शुरुआत करने को बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है, जिससे अन्य राज्यों में भी आगामी लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा फिर गर्मा सकता है। जाहिर है कि नीतीश कुमार और लालू यादव हमेशा इसके पक्ष में रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है जातिगत जनगणना? और इसके सियासी मायने क्या हैं? जो बिहार की सियासत और इसके चुनावी समीकरणों को गर्म करने का माहौल बना रहे हैं। दरअसल भारत में पिछड़े वर्ग (ओबीसी) की आबादी कितनी है, इसका आज तक कोई ठोस प्रमाण फिलहाल नहीं है। भारत में जातिगत जनगणना का अपना इतिहास रहा है। जब अंग्रेज भारत आए, तो उन्होंने जाति आधारित जनगणना शुरू की थी, जो सन् 1931 तक जारी रही। हालांकि सन् 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा एकत्रित किया तो गया, लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया गया।

केंद्र में कांग्रेस की मनमोहन सरकार के दौरान सन् 2010 में मुख्य विपक्षी दल भाजपा के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे ने जाति आधारित जनगणना के पक्ष में तर्क देते हुए सदन में सवाल उठाया था कि अगर ओबीसी जातियों की गिनती नहीं हुई, तो उनको न्याय देने में दशकों लग जाएंगे? मजे की बात तो यह है कि यह तब की बात है, जब कांग्रेस सत्ता में थी और भाजपा विपक्ष में। उस समय गोपीनाथ मुंडे जैसे भाजपा के ओबीसी चेहरों ने जोरशोर से जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था। लेकिन जब भाजपा सत्ता में आई, तो पार्टी का रुख ही बदल गया। जब पिछले महीने संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार से सवाल पूछा गया कि 2021 की जनगणना जातियों के हिसाब से होगी? तो सरकार ने लिखित जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी, एसटी) को ही गिना जाएगा। यानी सरकार की ओबीसी जातियों को गिनने की कोई योजना नहीं है।

साफ है कि केंद्र की सत्ता में जो भी पार्टी आती है, वो जातीय जनगणना को लेकर आनाकानी करने लगती है और जब विपक्ष में होती है, तो जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाती है। हालांकि लालू यादव जैसे कांग्रेस के सहयोगियों के दबाव में मनमोहन सरकार को जाति जनगणना पर विचार करना पड़ा और सन् 2011 में प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी, जिसने जाति जनगणना के पक्ष में सुझाव दिया। इस जनगणना का नाम 'सोशियो-इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस' रखा गया। जिलेवार पिछड़ी जातियों को गिनने के बाद जातीय जनगणना का डेटा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को दिया गया। उसके बाद भाजपा के सत्ता मे आने के कई वर्षों तक इस डेटा की कोई बात नहीं हुई। अब इस डेटा पर फिर सुगबुगाहट शुरू हुई, तो जातीय जनगणना के डेटा वर्गीकरण के लिए एक विशेषज्ञ ग्रुप बनाया गया है। लेकिन इस ग्रुप के रिपोर्ट दिए जाने की जानकारी नहीं मिल पाई है। तो साफ है कि कुल मिलाकर भाजपा की मोदी सरकार भी जातिगत आंकड़ों को जारी करना मुनासिब नहीं समझ रही है।

सामाजिक कार्यकर्ता बिसन ढिंढार नेहवाल कहते हैं कि उसके बाद भी सन् 1951 से सन् 2011 तक की जनगणना तो हुई है, लेकिन उसमें हर बार सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ही आंकड़े दिए जाते रहे हैं, ओबीसी और दूसरी जातियों को उसमे सम्मिलित नहीं किया जाता है। हालांकि सन् 1990 में जब केंद्र की तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग) की एक सिफारिश के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27 फीसदी आरक्षण देने की सिफारिश की, तो इस फैसले ने भारत, खासकर उत्तर भारत की राजनीति को बदलकर रख दिया। गौरतलब है कि मंडल कमीशन ने अपनी सिफारिश में सन् 1931 की जनगणना को ही आधार माना था, जिसके आधार पर भारत में अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) की आबादी 52 फीसदी मानी जाती रही है। उसके उपरांत अलग-अलग राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी सर्वे और अनुमान के आधार पर इस आंकड़े को अपने चुनावी एजेंडे को पूरा करने के लिए तोड़-मरोड़कर पेश करती रहीं हैं, लेकिन अपने दावे को साबित करने के लिए आज तक कोई भी सियासी दल एक ठोस आधार नहीं बता पाया है। हालांकि कुछ विश्लेषक इसे बड़ा जोखिम भरा कदम बताते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसा करने से समाज में जातिगत भेदभाव बढ़ जाएगा, लेकिन वो भूल जाते हैं। भारत एक विविधताओं से भरा देश है, जहां लोग अलग-अलग जाति, धर्म, समुदाय, क्षेत्र, पेशे और व्यवसाय से जुड़े हैं। यह भारत की अनेकता में एकता, संस्कृति एवं राष्ट्रीयता की भावना है, जो समूचे देश को एकसूत्र में बांधकर रखती है।

● **विनोद बक्सरी**

पहले भी उठती रही जातिगत जनगणना की मांग

भारत का संविधान भी आपको आपका धर्म, व्यवसाय या क्षेत्र बदलने की आजादी देता है, लेकिन सिर्फ आपकी जाति है, जिसे आप संवैधानिक रूप से भी नहीं बदल सकते। आज तकनीकी और डिजिटलाइजेशन का दौर है। अर्थव्यवस्था भी डाटा आधारित है। यही डाटा आज कहीं-न-कहीं लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। ऐसे समय में लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए उनकी सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (सोशियो इकोनॉमिक ऐंड कास्ट सेंसस) आधारित डेमोग्राफिक सूचनाएं एकत्रित करना अति आवश्यक हो जाता है। जातिगत जनगणना भी इसी डेमोग्राफिक सूचना का एक हिस्सा है। हालांकि आजादी के बाद से ही जातिगत जनगणना की मांग उठती रही है और पूर्ववर्ती सरकारों, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई दूसरी पार्टियां विपक्ष में रहते हुए, तो सब इस मांग का पुरजोर समर्थन करती हैं। लेकिन सत्ता में आते ही इन्हें न जाने क्यों सांप सूंघ जाता है। तमाम नेता और उनके सियासी दल इस मुद्द पर मौन पड़ जाते हैं। केंद्र सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति को तो इसमें शामिल करती है, परंतु पिछड़े वर्ग की जातियों को इसमें शामिल नहीं करती, जो उनके साथ एक तरह का सामाजिक अन्याय ही है।

क्या बाजवा का हाल भी मुशर्रफ जैसा होगा?

क्रियाकलापों में काफी समानताएं

जनरल बाजवा और जनरल मुशर्रफ के क्रियाकलापों में भी काफी समानताएं देखी जा रही हैं। कारगिल युद्ध में हार के बाद जनरल मुशर्रफ को जब आभास हुआ कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ उनको बर्खास्त करने वाले हैं तो उसी समय मुशर्रफ ने तय कर लिया था कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा देंगे। रिटायर जनरल शाहिद अजीज ने अपनी किताब ये खामोशी कहां तक में लिखा है कि जनरल मुशर्रफ ने तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा उन्हें बर्खास्त करने की प्रतिक्रिया में मार्शल लॉ नहीं लगाया था, बल्कि जनरल मुशर्रफ ने एक सोची समझी साजिश के तहत पहले ही पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने का मंसूबा बना लिया था। जनरल शाहिद अजीज ने लिखा है कि वे खुद भी जनरल मुशर्रफ के तख्तापलट कारनामे का हिस्सा थे। जनरल शाहिद ने यह किताब 2013 में लिखी थी। उनके बारे में कहा जाता है कि 2018 में एक दिन वे अचानक गायब हो गए और तब से उनकी कोई खबर नहीं है। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इमरान खान ने भी अप्रैल 2022 के पहले सप्ताह में जनरल बाजवा को आर्मी चीफ के ओहदे से हटाकर किसी और को आर्मी चीफ बनाने का फैसला कर लिया था।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा के खिलाफ तत्काल जांच बिठाई जाए। 14 फरवरी को लिखी चिट्ठी में इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बावजा पर आरोप लगाया है कि सेना प्रमुख रहते हुए उन्होंने बार-बार अपने पद का दुरुपयोग किया है। इससे पहले 10 फरवरी 2023 को वॉयस ऑफ अमेरिका चैनल पर प्रसारित अपने साक्षात्कार में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि पीएमएल एन, पीडीएम और फौज एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ वह अकेले हैं। बकौल इमरान जनरल बाजवा ने मीडिया से बातचीत में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने मेरी सरकार गिरवाई। इसलिए जनरल बाजवा के खिलाफ सेना आंतरिक जांच करे।

पाकिस्तान के एक प्रमुख न्यूज एंकर जावेद चौधरी ने अपने कॉलम में बाजवा के हवाले से लिखा है कि चूंकि इमरान खान और उनकी पार्टी के लोग मुल्क के लिए खतरा बन गए थे, इसलिए उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया। बकौल जावेद चौधरी जनरल बाजवा ने यहां तक कहा था कि इमरान खान सत्ता में रहे तो यह मुल्क नहीं बचेगा। दूसरी तरफ जियो न्यूज से जुड़े मशहूर एंकर हामिद मीर ने 12 फरवरी 2023 को खुलासा किया कि इमरान खान अप्रैल 2022 में तब के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को बर्खास्त कर किसी और को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, लेकिन 10 अप्रैल 2022 को उनकी सरकार गिर गई। मीर ने यह भी खुलासा किया कि मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पास इस बात के सबूत हैं कि जनरल बाजवा पाकिस्तान में एक बार फिर मार्शल लॉ लगाना चाहते थे। इसलिए अगर चाहे तो वह भी बाजवा के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दायर कर सकते हैं।

पाकिस्तान में आर्टिकल 6 का मतलब है कि कोई भी शख्स यदि पाकिस्तान के संविधान का उल्लंघन करता है, या उसकी तौहीन करता है तो उसे सजा-ए-मौत या उम्रकैद हो सकती है। इसे मुल्क के साथ गद्दारी के रूप में भी देखा जाता है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार किसी जनरल के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी का मुकदमा 2013 में जनरल मुशर्रफ के खिलाफ चलाया गया था। तब मुस्लिम लीग की सरकार थी, नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में यह मामला दायर कराया था। इस केस की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत का गठन किया गया। इस विशेष अदालत ने जनरल मुशर्रफ के अपने समक्ष हाजिर ना होने पर 19 जुलाई 2016 को भगोड़ा घोषित कर उनके पासपोर्ट को जब्त करने का आदेश सुना दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ का पासपोर्ट बहाल कर दिया और वह पाकिस्तान छोड़कर दुबई चले गए।

17 दिसंबर 2019 को तीन जजों की बेंच ने जनरल मुशर्रफ को संविधान को मुअत्तल करने और मुल्क के साथ संगीन गद्दारी करने के जुर्म में मौत की सजा 2:1 की राय से सुना दी। जनरल मुशर्रफ पर यह मुकदमा 3 नवंबर 2007 को उनके द्वारा संविधान को मुअत्तल कर सुप्रीम कोर्ट के 15 और प्रोविंसियल हाईकोर्ट के 56 जजों को बर्खास्त करने और पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश को नजरबंद करने के जुर्म में चलाया गया था। इसके पहले जनरल मुशर्रफ ने 15 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की सरकार को बर्खास्त कर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया था। जरनल बाजवा के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा आर्टिकल 6 के तहत दायर करा सकते हैं। यह आशंका पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीएमएल एन के नेता शाहिद खक्कान अब्बासी ने जताई है।

फरवरी के दूसरे सप्ताह में पाकिस्तानी टीवी प्रोग्राम दूसरा रूख से बातचीत में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जिस तरह का आरोप जनरल बाजवा के खिलाफ लगाया है वह संविधान के उल्लंघन का मामला बनता है। इससे लगता है कि इमरान खान यह मंसूबा बना चुके हैं कि यदि वह सत्ता में लौटते हैं तो जनरल बाजवा के खिलाफ शदीद गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे। इमरान खान ने पाकिस्तान में अचानक आंतकवादी घटनाओं में हुई बढ़ोतरी के लिए भी जनरल बाजवा को ही जिम्मेदार ठहराया है। खान ने एक विदेशी मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनकी सरकार चाहती थी कि 40 से 50 हजार टीटीपी के आतंकवादियों का पुनर्वास कर दिया जाए ताकि वे लोग बंदूक छोड़कर मुख्यधारा में आ जाएं, लेकिन बाजवा ने साजिश कर उनकी सरकार गिरा दी। आज जो भी पाकिस्तान में संकट उत्पन्न हुआ है उसके लिए जनरल बाजवा और उनकी आर्मी जिम्मेदार हैं।

जनरल बाजवा रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान की लगभग सभी सियासी पार्टियों के लिए विलेन बने हुए हैं। इमरान खान और उनकी पार्टी का मानना है कि जनरल बाजवा ने उनकी सरकार गिरवाई तो पीएमएल एन समेत पीडीएम के सभी जमात यह मानते हैं कि जनरल बाजवा ही थे जिन्होंने नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद से हटाकर इमरान को सत्ता में पिछले दरवाजे से बिठाया और हर मुसीबत से बचाने के लिए डंडे का जोर भी तब के विपक्ष पर दिखाया। अब देखना है कि आर्थिक और सियासी मोर्चों पर उलझा पाकिस्तान जनरल बाजवा के साथ क्या करता है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

चीन से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मोहभंग

चीन से भाग रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लेकर चीन चिंतित है। वह निवेशकों को समझाने में जुट गया है। चीन यह संदेश दे रहा है कि यह समय चीन से जाने का नहीं, बल्कि चीन की आर्थिक प्रगति में शामिल होकर लाभ प्राप्त करने का है। पिछले दिनों चाइनीज पीपुल्स पॉलिटिकल कंसलटेटिव कांफ्रेंस का आयोजन हुआ। इस कांफ्रेंस में शी जिनपिंग समेत तमाम कम्युनिस्ट नेताओं ने भाग लिया।

चीन ने इस कांफ्रेंस के जरिए दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की है कि उसकी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है और अमेरिका के बहकावे में आकर यदि कंपनियां चीन छोड़ रही हैं तो उन्हें आगे बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि चीन कोविड से उबरकर फिर से सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का चीन से भागना शी जिनपिंग की सरकार को कितना अखर रहा है, इसका उदाहरण चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय से लिया जा सकता है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है- अब इसमें तनिक भी शक की गुंजाइश नहीं कि चीन अब आर्थिक प्रगति की राह पर लौट आया है और वह फिर से वैश्विक पटल पर एक चमकते सितारे के रूप में स्थापित हो रहा है, ऐसे में यह देखना विचित्र लगता है कि कुछ विदेशी कंपनियां अपने आर्थिक फैसले, धारा के विपरीत ले रही हैं।

चीन यूं ही परेशान नहीं हो रहा है। इसके पीछे कुछ गंभीर कारण हैं। अमेरिका और यूरोप की कंपनियां ना केवल वहां से पलायन कर रही हैं, बल्कि आर्थिक संगठनों और उनके प्रमुखों की ओर से चीन के आर्थिक माहौल को लेकर गंभीर आरोप और आशंकाएं भी व्यक्त की जा रही हैं। 4 मार्च को अमेरिकन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स इन चीन ने एक सर्वे जारी किया, जिसमें कहा गया है कि चीन में काम करने वाले अमेरिकी बिजनेस हाउस अपने भविष्य को लेकर काफी सशंकित हैं। अधिकतर अमेरिकी बिजनेस हाउस का कहना है अब निवेश के हिसाब से चीन दुनिया के तीन सबसे प्रमुख देशों में शामिल नहीं रहा। इसलिए अधिकतर कंपनियां अपने निवेश की योजना चीन से बाहर बनाने लगी हैं।

अमेरिकन ही नहीं यूरोपियन निवेशक भी चीन से बड़ी तेजी से दूरी बढ़ा रहे हैं। हाल ही में सिटी ग्रुप इंक के यूरोपीय ऑपरेशंस के चीफ एक्जिक्यूटिव डेविड लिविंगस्टोन ने ब्लूमबर्ग टीवी के एक इंटरव्यू में कहा कि उनके ग्राहक चीन से अपनी सप्लाईलाइन को कहीं और ले जा रहे हैं और यह सिलसिला आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगा। यही नहीं लिविंगस्टोन ने यहां तक कहा कि हम एक दशक से यह ट्रेंड देख रहे हैं कि चीन से निकलकर कंपनियां मैक्सिको और वियतनाम आदि देशों में जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वे इलेक्ट्रानिक चिप के बिजनेस को भी चीन से बाहर जाते देख रहे हैं। क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से चीन ने कोविड के दौरान फोन से लेकर कार तक की इलेक्ट्रानिक चिप की आपूर्ति पर रोक लगा दी थी। यह ठीक भी है कि चीन से अब इलेक्ट्रानिक्स चिप की कंपनियां अपना बोरिया बिस्तर समेट रही हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित कंपनी एप्पल ने इस काम को पहले कर दिया। इसके अलावा गूगल, अमेजन, सैमसंग व वोल्वो ने भी चीन से निकलना शुरू कर दिया है। सीएनबीसी के अनुसार चीन इस समय न केवल इलेक्ट्रानिक्स, बल्कि परिधान, फुटवियर, फर्नीचर और ट्रेवल गुड्स का बिजनेस भी खो रहा है। अमेरिकन एंटरप्राइजेज इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो डेरेक स्कीजर्स का कहना है कि कमजोर होती चीनी अर्थव्यवस्था, कोविड के कड़े नियम, बदले की कारवाई के तहत व्यापार संबंधी प्रतिबंध और चीन की कई फ्रंट पर युद्ध जैसी स्थिति के बाद चीन में अब बिजनेस करना काफी कठिन हो गया है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों का चीन से मोह भंग एक दिन में नहीं हुआ है। चीन में मानवाधिकार का हनन, बौद्धिक संपदा की चोरी, व्यापार पर कई प्रकार के प्रतिबंध, बाजार में मनमाफिक घालमेल और कंपनियों के बोर्ड में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का अनिवार्य प्रवेश ये सब बाहर की कंपनियां लगातार झेल रही हैं और अब ये उनको नागवार गुजर रहा है। फिर चीन का लेबर मार्केट सिकुड़ रहा है। चीन का कामगार बुजुर्ग हो रहा है। गरीबी पर काबू पाने के बाद से चीन में मजदूरों का मिलना भी मुश्किल हो रहा है। कठोर लॉकडाउन ने चीनी मजदूरों के पलायन को काफी बढ़ा दिया है। यूरोपीयन चैम्बर्स के वाइस प्रेसिडेंट बेटिना स्कियोन कहते हैं- चीन के बारे में एक ही अनुमान लगा सकते हैं कि उसे लेकर कोई अनुमान नहीं लगा सकते और यह बिजनेस के लिए जहर के समान है। यही कारण है कि यूरोप की कई कंपनियां चीन में अपने निवेश के फैसले पर अभी कोई फैसला नहीं कर रहीं। वे देखना चाहती हैं कि चीन की यह अनिश्चितता कब तक बनी रहती है और उनमें से बहुत सी अपने भविष्य के बिजनेस को किसी और देश में देख रही हैं।

● **कुमार विनोद**

राजनीति ने बिगाड़ा पूरा खेल

अमेरिका और यूरोप के साथ बिगड़ते चीन के रिश्ते भी बाहर की कंपनियों के लिए एक बुरा सबक बन रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कोरिया की कंपनियों को चीन में बुरा समय देखना पड़ा है। जापान और चीन के बीच तनातनी हुई तो चीन में काम कर रही जापानी कंपनियों को बॉयकाट का सामना करना पड़ा। उनके कंटेनर को जबरन पोर्ट पर रोका गया। चीनी उपभोक्ताओं ने उनके उत्पादों का बॉयकाट किया। जिस अनुपात में अमेरिका चीन की कंपनियों पर प्रतिबंध या रोक लगाता है उसी अनुपात में चीन में भी अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लग जाता है। चीन को अब यह लगने लगा है कि यदि व्यापार में वह राजनीति को घुसेड़ता रहेगा तो उसका परिणाम उसे ही भुगतना पड़ेगा। इसीलिए वह चिंतित भी है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि यदि लंबी अवधि के वैश्विक परिदृश्य को देखे तो चीन से ज्यादा संभावना वाला कोई देश नहीं है। असीमित निर्माण क्षमता और सप्लाई चेन की बड़ी आधारभूत संरचना के साथ चीन आगे बना रहेगा। यदि कुछ विदेशी कंपनियों को उसके बाद भी बाजार में कोई गड़बड़ी दिखती है और उपलब्ध संभावनाओं का लाभ नहीं उठातीं और अमेरिका के साथ गठजोड़ में चीन से अलग होती हैं तो यह उनकी समस्या और नुकसान है।

सपनों को पंख लगातीं महिला उद्यमी

राजस्थान के टोंक जिले के दूनी कस्बे की 30 महिलाओं के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बकरी के दूध से जब साबुन बनाया था, उसकी कीमत रखी थी 55 रुपए। महिलाओं ने सोचा नहीं होगा कि उन्हें कोई बड़ा मौका मिलेगा। कुछ समय बाद स्पेन की एक महिला ने उन्हें साबुन की 40,000 टिकियां तैयार करने का ऑर्डर दिया। बकरी का दूध कई बीमारियों के लिए उपयोगी है। इस साबुन को त्वचा के लिए उपयोगी बताया गया। स्टार्टअप की कानूनी प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया जाए, तो देश की जीडीपी में बड़ा योगदान महिला उद्यमियों का होगा। इंडिया स्किल रिपोर्ट-2023 से पता चलता है कि भारत में पुरुषों के मुकाबले कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बेशक 33 फीसदी है। लेकिन महिला प्रतिभा रोजगार क्षमता 5.6 फीसदी है, जो पुरुषों से ज्यादा है। इस दिशा में राजस्थान में रोजगार योग्य महिलाओं का प्रतिशत देश में सबसे ज्यादा 54 फीसदी है। वहीं उप्र 46.51 फीसदी के साथ दूसरे नंबर पर है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि नई पीढ़ी के युवाओं का कौशल विकास एक राष्ट्रीय जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा आधार है। भारत के पास ऐसे युवा हैं जिनमें कौशल, मूल्य, जुनून और कार्य के प्रति ईमानदारी है। कृष्मन सिंह उन्हीं युवा महिला उद्यमियों में से है, जिन्होंने कुछ साल पहले अपना स्टार्टअप शुरू किया था। कृष्मन ने देश से एमबीए (गोल्ड मेडल) करके उच्च शिक्षा के लिए कनाडा की क्वींस यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस (एमआईबी) की पढ़ाई की। कुछ समय के लिए फेलोशिप के साथ अमेरिका भी रहीं। कृष्मन प्रोडक्ट की मार्केटिंग, ब्रांडिंग और बिक्री करना सबकुछ जानती थीं, लेकिन जब स्टार्टअप शुरू किया तो उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते प्रोजेक्ट रोकना पड़ा। बाद में किसी बड़ी कंपनी में नौकरी पाने के बाद उन्हें अपनी टीम का निर्देशन करते हुए तीन राज्यों की सरकारों राजस्थान, उप्र और महाराष्ट्र के साथ सेतु की तरह काम करने का अवसर मिला। राजस्थान में आजीविका मिशन और पंचायती राज के तहत राज्य के स्वयं सहायता समूहों के लिए फील्ड वर्क किया। इसमें महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के अलावा सामान की प्रेजेंटेशन, पैकिंग, ब्रांडिंग और बिक्री आदि के लिए काम किया गया। कृष्मन ने कहा कि राजस्थान सरकार ने सोशल प्लेटफार्म्स के साथ भागीदारी की है। इसके लिए पिछले वर्ष जयपुर में महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राज्य की हजारों महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूहों की ग्रामीण महिला उद्यमियों ने अपने अनुभव साझा किए। उप्र में महिलाएं काफी जागरूक हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच नहीं है। कृष्मन बताती हैं कि उन्होंने लाइवलीहुड मिशन के तहत राज्य के चार जिलों में फील्ड वर्क किया। इसके लिए आपकी दुकान नाम का कॉन्सेप्ट लॉन्च करके ग्रामीण महिला उद्यमियों के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को एक प्लेटफार्म पर लाया गया। इससे कनाडा और अमेरिका के बाजारों में उन्हें काम करने का अवसर मिला।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को हर राज्य तथा शहर में करीब 40 तकनीकी क्षेत्रों में निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। बजट भाषण 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, युवाओं को ऑन जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी और जरूरतों के साथ आधुनिक पाठ्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे। इनमें रोबोटिक्स, मेडट्रॉनिक्स, कोडिंग, एआई आईओटी, प्रिंटिंग, ड्रोन, स्किल्स और 3डी शामिल है। योजना के पहले चरण में 5,000 प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। देश में स्टार्टअप्स की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब महिलाओं के स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए गूगल कंपनी भी आगे आई है। नैसकॉम के अनुसार, महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स वर्ष 2014 में आठ फीसदी बढ़े हैं, जबकि वर्ष 2019 में इनकी संख्या 13 फ़ीसदी रही। भारत की शीर्ष आठ महिला उद्यमियों में फाल्गुनी नायर (नाईका), वंदना लूथरा (वीएलसीसी), सूची मुखर्जी (लाइम रोड), रिचा कर (जीवेम), वाणी कोला (कलारी कैपिटल), प्रांशु पाटनी (हेलो इंग्लिश), उपासना टाकू (मोबिक्विक) शायरी चहल (शीरोज) आदि शामिल हैं। इसके लिए भारतीय महिला बैंक व्यवसाय ऋण, देना शक्ति योजना, उद्योगिनी योजना, महिला उद्यमिता मंच, प्रधानमंत्री मुद्रा आदि योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसे पांच कौशल हैं, जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहने वाली हर महिला के लिए जरूरी हैं। इसमें वित्त कौशल, संचार कौशल, नेतृत्व कौशल, समय प्रबंधन और बिक्री आदि शामिल हैं।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

माइक्रो स्तर की महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना जरूरी

2015 में, भारत सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पहल की शुरुआत की, ताकि लैंगिक असमानता को दूर करते हुए लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। इस पहल के कई सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आए, जिसमें स्कूलों में पंजीकृत लड़कियों की संख्या में उछाल आना और जन्म पर लिंगानुपात में सुधार आना शामिल है। लेकिन ऐसी सफलताओं के बावजूद, लिंग समानता के लिए भारत का संघर्ष एक जटिल मुद्दा है, जिस पर अभी तक पूरी तरह से ध्यान दिया जाना बाकी है। विश्व आर्थिक मंच के हालिया ग्लोबल जेंडर गैप रैंकिंग के अनुसार, भारत 146 देशों में से 135वें स्थान पर है। जिससे साफतौर पर पता चलता है कि इस चुनौती को हल करने के लिए अभी भी काफी प्रयास की आवश्यकता है। इसलिए, भारत की बेटियों को बचाने और उन्हें पढ़ाने के साथ-साथ उनका कमाना भी बहुत जरूरी है। इस तीसरे पहलू, जिसे बेटी कमाओ का नाम दिया जा सकता है, का अर्थ है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें देश के भीतर एक उद्यमी और रोजगार प्रदाता के रूप में बढ़ावा देना।

ANU SALES
CORPORATION
When time matters,
Real 200 t/h throughput
Even with double reagent reactions, the analyzer keeps its speed. Up to 4 volumes can be handled in every cycle.
Dispensation
Aspiration
We Deal in Pathology
& Medical Equipment
BS200
BioSystems
The Highest Flexibility
Address : M-179, Gautam Nagar,
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530
Email : ascbhopal@gmail.com

समय के पदचिन्ह

अनुभव ने लाला मदन लाल को कहा- मुझे बढ़िया से जूते दिखाओ। लाला का नौकर उसे जूते दिखाता गया और वह रेंज बढ़ाता गया। कस्बे की इस दुकान पर सबसे महंगे जूते दस हजार तक के ही थे। उसने कहा - इससे महंगे और भी है जूते? लाला ने इनकार कर दिया। अनुभव ने वे जूते खरीद लिए। पैसे देने के लिए जैसे ही अनुभव लाला मदनलाल के काउंटर पर खड़ा हुआ, लाला मदन लाल ने बिल काटते हुए कहा- बेटा आप कहां से हो? मैंने आपको पहचाना नहीं? अनुभव बोला- लालाजी मैं धर्मनगर से महू का बेटा हूं। फिर लाला ने पूछा क्या करते हो? तो वह बोला- मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में साइंटिस्ट हूं। तब लाला बोला- अच्छा तो आप महू के बेटे हो; महू तो हमारा ही ग्राहक था। अनुभव बोला जी पिताजी आपके ही ग्राहक थे। फिर वह आगे बोला- शायद आपको याद हो न हो लेकिन मुझे तो आज भी बीस बरस पहले की वह सारी घटना याद है। मैं बीमार था मेरे पिताजी मुझे दवाई लेने बाजार आए थे। उनके जूते फटे हुए थे। बारिश लगी थी। बारिश का सारा पानी जूतों में जा रहा था। मैं उस समय दस वर्ष का था। वह आपकी दुकान पर आए और आपसे उधार में जूते मांगे। उन जूतों का मूल्य उस समय दस रुपए था। परंतु आपने उधार में जूते देने से यह कहकर इनकार कर दिया कि यह बहुत महंगे जूते हैं आपकी हैसियत से बाहर हैं। इतने महंगे जूते मैं आपको उधार नहीं दे सकता। आपने दूसरी तरफ रखे हुए जूते दिखाते हुए कहा था कि आपने लेने ही हैं तो ये दो रुपए वाले ले लो उधार में। पिताजी को यह बात चुभ गई। वे उन्हीं फटे जूतों में वापिस घर आ गए। जबकि पिताजी आपके पास ही पूरे परिवार के लिए जूते खरीदा करते थे। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था। फिर वह आगे बोला- ये जूते मैं अपने पापा के लिए ही ले रहा हूं। लालाजी वक्त बदलता रहता है। यह कहकर वह दुकान से बाहर आ गया। अब समय के पदचिन्ह लाला के मानस पटल पर उभर आए थे। वह निरुत्तर सा होकर अनुभव को तब तक देखता रहा जब तक वह अपनी कार में न बैठ गया।

- अशोक दर्द

कम्बल वितरण

बहुत बड़ा और सुंदर मंच सजा हुआ था। मंच के डेकोरेशन से ही पता चल रहा था कि मंच पर ही लाखों का व्यय किया गया है। काजू, बादाम, पिस्ता की प्लेटों के सामने क्षेत्रीय विधायक, सांसद, अध्यक्ष और सत्ताधारी पार्टी के तमाम फध्यक्ष मंच की शोभा बड़ा रहे थे। इसके साथ ही कुछ विशेष लोगों के लिए लजीज खाने की व्यवस्था भी की गई थी। जिनमें प्रमुख थे मंच पर विराजमान गणों के अतिकरीबी, परिवारीजन, विशेष पार्टी पदाधिकारी व रात-दिन एक करने वाले कार्यकर्ता, मीडियाकर्मी। वैसे मीडियाकर्मियों के लिए लिफाफे की व्यवस्था भी की गई थी, जिसका वजन ठीक-ठाक रखा गया था।

मंचासीन महामानवों के सम्मान से कार्यक्रम प्रारंभ होना था, सो माल्यार्पण हुआ, महंगी-महंगी शॉलों को उढ़ाया गया, बड़े-बड़े मोमेंटो भेंट किए गए और कार्यक्रम शुरू।

सस्ते घटिया किस्म के बदबूदार, चूहों के कटे कम्बलों के लिए गरीब-गुरबे लाईन में लग गए। 'मैं न रह जाऊं- मैं न रह जाऊं' के चक्कर में भगदड़ मच गई और पुलिस ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। न जाने कितनों की हड्डियां टूटीं, सिर फूटे।

दूसरे दिन अखबारों में छपा, गरीब व जरूरतमंदों को वितरित किए हजारों-हजार कंबल, परंतु हड्डियां टूटने व सिर फूटने की खबरों का कोई अता-पता नहीं था।

- मुकेश कुमार ऋषि वर्मा

कविता

करीब आने के लिए
वो कहते हैं हमसे
दे जाओ कोई निशानी
बिन तेरे हमको है
अब कुछ दिन बितानी
आई थी जब तो
बीती थी सोलह सावन
संग तेरे ही तो
बीती है सारी जवानी।
अब भी कहते हो
दे जाओ कोई निशानी?
ये दरों दीवारें और
ये आंगन ये चौखट
उन पर स्पर्शों की
सभी तरफ है सिलवट
नरम हाथों से
अपने उसे तुम सेंकना
सुनो कान लगाकर
आएगी वो ही आहट
चाहो तो कर दो शुरू
अभी से आजमानी
अब भी कहोगे
दे जाओ कोई निशानी?
हमें भी तुम बिन है
कुछ दिन गुजारनी
पर पास मेरे हैं
कई यादें रूहानी
सर्दी की गुनगुनी धूप
वो सावन की बूंदे
रखा है समेटे उन
सारे लम्हों की कहानी
तुम ही तो हो
मेरी सारी जिंदगानी
हमारे पास तो है
सहेजी धरोहर पुरानी
पलटती हूं
उन पुराने पन्नों को
तो क्यों मांगू भला
हमें दे दो कोई निशानी...

- सविता सिंह मीरा

> वर्ष 2023 में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अब तक शुभमन गिल के नाम है। उन्होंने इस साल अब तक 5 शतक लगाए हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जेसन रॉय, उस्मान ख्वाजा, डेविड मलान जैसे खिलाड़ी उनसे पीछे हैं।

किसान का बेटा बना भारत का सुपर बैटर

टीम इंडिया को नया सुपर बैटर मिल गया है। यह बैटर भारतीय क्रिकेट टीम का उभरता सितारा शुभमन गिल है। शुभमन ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में 90 दिनों में छठा शतक लगाकर अपनी प्रतिभा का डंका पिटवा दिया है। यह उनके टेस्ट कैरियर का दूसरा शतक है। शुभमन मात्र 23 साल के हैं और वह उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने क्रिकेट के मौजूदा सभी फॉर्मेट्स में शतक लगाए हैं। एक कैलेंडर ईयर में सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले वो भारत के चौथे बल्लेबाज भी हैं। शुभमन टेस्ट क्रिकेट में 2, वनडे में 4 और टी-20 में एक शतक लगा चुके हैं।

शुभमन क्रिकेटर बनें, यह सपना उनके किसान पिता लखविंदर सिंह ने देखा था। लखविंदर पंजाब के फाजिल्का जिले के एक गांव में खेती करते थे। शुभमन को क्रिकेटर बनाने को लेकर पिता का जुनून ऐसा था कि उन्होंने खेतों में ही क्रिकेट ग्राउंड बना दिया था। वह शुभमन को आउट करने वाले बच्चे को 100 रुपए का इनाम देते थे। बेटा प्रोफेशनल क्रिकेटर बन सके, इसलिए लखविंदर सिंह ने गांव छोड़ा और मोहाली आ गए। कुछ दिन तो शुभमन ने स्कूल में ही क्रिकेट की कोचिंग ली और उसके बाद पिता ने उन्हें पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन एकेडमी में दाखिला दिला दिया।

शुभमन बचपन से क्रिकेट के प्रति समर्पित रहे हैं। वर्ष 2018 में जब टीम इंडिया ने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था तो वह टीम के वाइस कैप्टन थे। उससे पहले 2017 में वह पंजाब के लिए रणजी ट्रॉफी में पदार्पण कर चुके थे। उन्होंने रणजी के दूसरे मैच में शतक लगाया था। वर्ष 2014 में पंजाब इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर-16 टूर्नामेंट में शुभमन ने 351 की विशाल पारी खेली थी और निर्मल सिंह के साथ पहले विकेट के लिए 587 रन बनाए थे। वह विजय मर्चेंट ट्रॉफी में पंजाब के लिए दोहरा शतक भी लगा चुके हैं। शुभमन नेशनल अंडर-19 टीम का हिस्सा भी रहे हैं और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ यूथ वनडे सीरीज की चार पारियों में 351 रन बनाए थे और मैन ऑफ द सीरीज रहे थे।

शुभमन की पिछली 10 पारियों की बात करें तो अहमदाबाद में हुए टेस्ट मैच की पहली पारी में 128 रन बनाने के अलावा अहमदाबाद में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 मैच में 126 नाबाद, न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर वनडे में 112 रन, न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद वनडे में 208 रन और तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के खिलाफ वनडे में 116 रन लगा चुके हैं। गुवाहाटी में श्रीलंका के खिलाफ वनडे में उन्होंने 70 रनों की पारी खेली थी।

शुभमन के क्रिकेट कैरियर की बात करें तो उन्होंने टेस्ट में 14 मैचों में 762 रन बनाए हैं और 15वें मैच में शतक लगा चुके हैं। वनडे क्रिकेट में भी उनका बेहतरीन स्कोर है। 21 मैचों में 1254 रन हैं, जिनमें 4 शतक, 5 अर्धशतक और अधिकतम 208 रन हैं। टी-20 के 6 मैचों में उन्होंने 202 रन बनाए हैं और नाबाद 126 रन अधिकतम स्कोर है। एक कैलेंडर वर्ष के सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले शुभमन गिल चौथे भारतीय बल्लेबाज हैं। उनसे पहले यह करिश्मा सुरेश रैना (2010), केएल राहुल (2016), रोहित शर्मा (2017) में कर चुके हैं।

● आशीष नेमा

इस साल सबसे ज्यादा शतक

वर्ष 2023 में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अब तक शुभमन के नाम है। उन्होंने इस साल अब तक 5 शतक लगाए हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जेसन रॉय, उस्मान ख्वाजा, डेविड मलान जैसे खिलाड़ी उनसे पीछे हैं। मात्र 23 साल के शुभमन के आगे लंबा कैरियर है। यदि उनकी यही लय कायम रही तो वो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे महान क्रिकेटरों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे और इनके रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। किसान परिवार से आने वाले शुभमन आज भी खेती में रुचि रखते हैं। उनको अपने गांव और खेतों से बेहद लगाव है, जिसके फोटो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देखे जा सकते हैं।

किसी भी कीमत पर हेमा मालिनी को बनना था फिल्म का हिस्सा

बिना पैसे ही करना पड़ा काम, चौंकाने वाली है वजह

अभिनेत्री हेमा मालिनी फिल्म मीरा में किसी भी कीमत पर काम करना चाहती थीं। एक ऐसी भी वजह रही कि वह इस फिल्म में बिना पैसे ही काम करने को तैयार हो गई थीं। अपने दौर के जाने-माने निर्माता प्रेमजी हेमा मालिनी को अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए काफी उतावले थे। लेकिन हेमा उनकी फिल्म में काम करने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। कई बार हेमा से फिल्म के लिए पूछने पर एक बार उन्होंने प्रेमजी से कहा कि अगर आप मीरा पर कोई फिल्म बनाएंगे तो मैं जरूर करूंगी। हेमा की शर्त पर प्रेमजी काफी खुश हुए, वह तुरंत गुलजार के पास गए और स्क्रिप्ट लिखने को कह दिया। यह रोल खुद हेमा मालिनी ने उन्हें निभाने को कहा था। इस बार हेमा के पास फिल्म ना करने की कोई वजह नहीं थी। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई, लेकिन फिर बजट पर आकर बात अटक गई और फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ गई। ये सब जानने के बाद हेमा मालिनी सीधे प्रेमजी के पास गईं और कहा ये फिल्म में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम, आस्था और श्रद्धा के लिए कर रही हूं। मैं इसके लिए फीस चार्ज नहीं करूंगी। आप श्रद्धा से जो भी मुझे दोगे मैं रख लूंगी। फिल्म की शूटिंग शुरू कीजिए। बता दें कि साल 1979 में हेमा जब इस फिल्म के सेट पर आईं तो प्रेमजी ने भी फैसला कर रखा था कि आते ही उन्हें एक लिफाफा देंगे। उन्होंने ऐसा किया भी आपको जानकर हैरान होगी वो लिफाफा और पैसे आज भी हेमा मालिनी ने संभाल कर रखे हैं।

जब बिना डुप्लीकेट के 3 मंजिल से कूदे अमिताभ

अजय देवगन ने हाल ही में मेजर साब से जुड़ा एक यादगार किस्सा बताया, जिसमें अमिताभ बच्चन उनके साथ तीसरी मंजिल से कूदे थे। एक्शन को लेकर अजय को पुराने दिन याद आ गए। उनका कहना था कि हमारे और अमिताभ बच्चन के समय में एक्शन करना खासा मुश्किल होता था। उस समय नीचे मेट्रेस भी नहीं होती थी, जिससे कई बार चोट लग जाया करती थी। अजय ने साल 1998 में आई फिल्म मेजर साब का इंसीडेंट याद करते हुए कहा कि एक सीन में हमें तीसरी मंजिल से कूदना था। ऐसे में मैंने अमित सर को इसके लिए मना किया क्योंकि यह रिस्की था। मैंने उन्हें डुप्लीकेट से सीन करवाने के लिए कहा लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह हो जाएगा और फिर हम तीसरी मंजिल से कूदे और हमें काफी चोटें भी आईं। मैं उनकी इसी बात का कायल हूं और यही जज्बा पहले के टाइम पर सभी में देखने को मिलता था। फिल्मों की एक्शन की बात की जाए जो हमेशा अजय देवगन का नाम भी आता है। अजय ने अपनी शुरुआती फिल्मों से ही एक्शन हीरो की इमेज बनाई थी। अजय अधिकतर अपने एक्शन खुद ही करना पसंद करते हैं।

जब रानी मुखर्जी ने खोल दी थी करीना की पोल, सन्न रह गई थीं बेबो

अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने भले ही कुछ समय से फिल्मों से दूरी बना रखी है। लेकिन उनके चाहने वालों की संख्या आज भी कम नहीं हुई है। अब काफी समय बाद रानी जल्द ही अपनी अगली फिल्म मर्दानी-3 में नजर आने वाली हैं। रानी के फैंस उनका इस फिल्म में भी बेबाक अंदाज देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। इन दिनों रानी अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। जो उन्होंने बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर खान को लेकर दिया था। किस्सा उस दौरान का है जब रानी मुखर्जी और करीना कपूर खान दोनों ही एक्ट्रेसेस करण जौहर के शो कॉफी विद करण के एपिसोड में नजर आई थीं। दोनों ने शो पर काफी मस्ती की। साथ ही

दोनों के कई सीक्रेट भी रिवील किए। इसी दौरान करण ने रानी से एक ऐसा सवाल किया कि ऐसा क्या है जो करीना के पास है, आपके पास नहीं? रानी मुखर्जी ने भी इस सवाल का जवाब ऐसे अनोखे अंदाज में दिया कि बेबो की आंखें फटी रह गई थीं। हालांकि बाद में जब करीना से पूछा गया तो उन्होंने भी रानी मुखर्जी के कई राज से पर्दा उठा दिया था।

शो कॉफी विद करण में करीना कपूर और रानी मुखर्जी दोनों ही बतौर गेस्ट नजर आई थीं। दोनों ने सेट पर करण के साथ मिलकर काफी मस्ती की। लेकिन सवाल-जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। करण ने रानी मुखर्जी से सवाल किया कि ऐसी कौन सी चीज है जो उनके पास है, लेकिन करीना के पास नहीं? इस सवाल पर रानी बड़े ही बेबाक अंदाज में बिना कुछ सोचे समझे तुरंत कहा- शाहिद कपूर। रानी मुखर्जी का जवाब सुनकर जहां करीना कपूर खान बेहद हैरान थीं, वहीं करण जौहर का मुंह भी खुला ही रह गया था।

कान से ली, जुबान से दी

निंदा रस एक ऐसा रस है, जो मानव मात्र में एक अनिवार्य तत्व की तरह विद्यमान है। भोजन के षट रसों और साहित्य के दस रसों से सर्वथा भिन्न इस रस के स्वामी और ग्राहक को किसी विद्यालय, महाविद्यालय में पढ़ने किंवा प्रशिक्षण लेने अथवा किसी विश्वविद्यालय की उपाधि प्राप्त करने की भी आवश्यकता नहीं है। वास्तविकता यह है कि इससे निंदक की ऊंचाई और गहराई की पड़ताल अवश्य हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह निंदक की अपनी बुद्धि का बैरोमीटर है। उसके अपने स्तर की माप करता है। इसके साथ ही जो निंदा को सुनता है, उसकी माप तो स्वत: ही हो जाती है, क्योंकि निंदक सदैव अपने स्तर के श्रोता को खोजकर ही निंदा-प्रवचन करता है। जैसे दो सासें अपनी बहुओं की निंदा तभी करती हैं, जब श्रोता सास उतना ही रस लेकर उसका आस्वादन करे। बीच-बीच में उसकी जिज्ञासा और प्रश्न तो उसको और दीर्घता प्रदान करते हुए अगणित गुणा रस वृद्धि करते हैं। जैसे- उसके बाद?, फिर क्या हुआ?, फिर उसने भी लौटकर मारा? आदि वाक्यांश उसके रस उद्भव में चार चांद लगा देते हैं। निंदा और निंदक मानव चरित्र की पहचान का पैमाना ही है।

निंदा में कभी भी सच तथ्य को नहीं कहा जाता। झूठ और सच का अनुपात 90-10 या कभी-कभी 100-000 भी रह सकता है। यदि कभी कोई सच बात कह भी दे तो उसे सिद्ध करने के लिए प्रमाण देना भी अनिवार्य हो जाता है। यदि ये कहा जाए कि कल्लू के बेटे की बहू आईएएस हो गई तो कोई भी सहज रूप में विश्वास नहीं कर सकता। उसमें अनेक कैसे? क्यों? कब? कहां? पैदा हो जाएंगे। इसके विपरीत यदि किसी के कान में ये फुसफुसा दिया जाए कि कल्लू के बेटे की बहू देवर के साथ फरार हो गई, तो बिना किसी क्यों? कब? कैसे? के बिना सहज रूप में शत-प्रतिशत बात स्वीकार ही होगी। और वह समाज में ऐसे फैल जाएगी, जैसे पानी के तल पर पड़ी हुई तेल की बूंद।

पूर्व में भी कहा जा चुका है कि निंदक की उपाधि कम या अधिक मात्रा में सबके ही पास होती है, क्योंकि वह जन्मजात है। स्वभावगत है। इसलिए सामान्य नर-नारी, चोर या व्यभिचारी, कर्मचारी या अधिकारी, नेता या मंत्री, मालिक या संतरी, शिक्षक या छात्र, कवि या आलोचक, सास या बहू, अड़ौसी या पड़ौसी, मौसा या मौसी, कहां नहीं है। ऐसा व्यक्ति दिन में भी रोशनी-पुंज लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलने वाला, जो निंदक या निंदा रस लोलुप न हो! यह एक सर्वप्रिय मुफ्त का रस है। इसके लिए किसी साक्ष्य, किसी सौगंध, किसी गंगाजली, किसी गीता पर हाथ रखने आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। निंदा सुनकर कोई कभी प्रश्न नहीं करता, सहज विश्वास ही करता है और प्रचारक बनकर उसे जितना हो सकता है, फैलाने में लग जाता है।

कबीर दास के अनुसार यह एक ऐसा शुद्धक और बुद्धि सुधारक है कि इसके लिए कोई डिटर्जेंट, ईजी या फिनायल, हारपिक क्या पानी की भी आवश्यकता नहीं है। यह निंदक और ग्राहक दोनों को ही शुद्धि प्रदान करने का पुण्य कमाता है। यह अलग बात है कि यह किसी का भाव है तो किसी-किसी का तो स्वभाव ही बन चुका है। जिसका स्वभाव ही निंदा है, वह कदापि नहीं अपने कर्म से शर्मिंदा है। क्योंकि वह तो एक ऐसा उड़ता हुआ परिंदा है कि कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल का वासिंदा है। ऐसा निंदक जब तक जिंदा है, तब तक उसकी जुबान पर अपना आसन जमाए हुए रानी निंदा है। अब चाहे वह मुंबई, कोलकाता हो या भटिंडा है। उसके माथे क्या उसकी सारी देह पर निंदा का बिंदा है।

निंदानंद को कभी क्रय नहीं करना पड़ता। इसको देने और लेने में कोई आर्थिक व्यय या हानि भी नहीं है। जब निंदा रस ही है, तो कष्ट भी क्या होने वाला है? विरस होता तो लेने-देने में आपत्ति भी हो सकती थी। गुणकारी जानकर तो लोग नीम और कुनैन को भी प्रेम से रसनास्थ कर जाते हैं। उदर में जाकर तो गुलाब जामुन और भिंडी की सब्जी का भी एक ही हस्र होता है। इसके विपरीत निंदा सदा आनंदप्रद ही बनी रहती है। अलग-अलग कानों में अलग-अलग मुखारविंदों से निसृत होकर अपना एक नवीन प्रभाव ही भरती है। भर पेट निंदा-रस लेने के बाद भी अपच नहीं होती। दूसरी ओर देने पर यह घटती भी नहीं।

ठलुआ-क्लब में समय व्यतीत करने का इससे अच्छा कोई साधन भी नहीं है। हर्रा लगे न फिटकरी रंग चोखा ही आए। यह घर, बाहर, दफ्तर, सड़क, पनघट, गली का नुक्कड़, घूर-स्थल, सभाकक्ष, जल भरण-थल, गली के नुक्कड़, दुकान, मध्यान्ह-गोष्ठी स्थल, स्वेटर-बुनाई स्थल, विवाह, शादी के उत्सव, परस्पर वस्तु-विनिमय काल आदि अनगिनत स्थान और समय हैं, जब निंदा रस-प्रसार अनवरत और अबाध रूप से होता है।

कबीरदास जी ने जब निंदक को नियरे अर्थात् पास में रखने की पवित्र और नेक सलाह दी, तो मेरा यह सोचना आवश्यक हो गया कि जब हम निंदकों की बस्ती, गली, दफ्तर, बाजार आदि सभी जगह निंदकों का बहुमत पाते हैं तो चाहे या अनचाहे उनसे बच भी तो नहीं सकते। वे तो धुएंदार हवा की तरह सभी जगह पहले से ही विद्यमान हैं। वे तो पहले से ही हमें छुछूंदर की तरह सूंघने में लगे हुए रहते हैं। उन्हें पास में क्या रखना? वे स्वयं हमें अपने पास रखे हुए होते हैं। वे कोई निराश्रित या बेघर तो हैं नहीं जो उनके लिए आंगन में कुटी छवाई पड़े। वे तो बहु मंजिला भवनों, कोठियों और बिना आंगन के भवनों में रहने वाले/वालियां हैं। अब आजकल के आवासों में आंगन बनाने का फैशन ही समाप्त हो गया तो कुटी छवाई भी कहां जाएगी? निंदा तो एक ऐसी 'बू' है जो सुनने और सुनाने वाले के लिए खुशबू है तो जिसकी फैलाई जाए, उसके लिए बदबू है। एक ही वस्तु के उभय गुण। कान से ली और जुबान से दी जाती है, और कभी-कभी तो फुसफुसाहट में ही मैदान पर मैदान पार करती हुई देखी जाती है। वाह री! निंदा और वाह रे! निंदकों/निंदकियो!

● **डॉ.भगवत स्वरूप 'शुभम'**

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दूरदर्शिता से

आत्मनिर्भरता की राह पर मध्यप्रदेश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना है कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाएं, जिसमें हर वर्ग को विकास का लाभ मिल सके। मध्यप्रदेश इस उद्देश्य को पूरा करने में अपना योगदान देने के लिए निरंतर परिश्रम कर रहा है। मध्यप्रदेश शासन ने कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण सेक्टर्स का चुनाव किया है, जो सरकार की 550 बिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था की सोच को साकार करने में सहयोग करेंगे। ये सेक्टर हैं- ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, कृषि, टैक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग, नवकरणीय ऊर्जा, एयरोस्पेस एवं रक्षा क्षेत्र।

'विकसित भारत के निर्माण में मध्यप्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, अध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक एम.पी. अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है।'

- नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

'मध्यप्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। मैं मध्यप्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नये भारत का उदय हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए मैं आप सबके सहयोग से आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाऊंगा।'

- शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

प्रदेश को गति देते प्रमुख सेक्टर

आई.टी.

आई.टी. के मामले में मध्यप्रदेश अब मेट्रो सेंटर्स को टक्कर देने की तैयारी में है। इंदौर सबसे बड़ा सेंटर है, यहां कई बड़ी कंपनियां कारोबार कर प्रदेश के युवाओं को रोज़गार दे रही हैं।

- प्रदेश में 150 से अधिक इंस्टॉलेशन यूनिट और 220 से अधिक आईटी/आईटीईएस यूनिट मौजूद।
- प्रदेश में 4 स्पेशल आईटी इकोनॉमिक ज़ोन, 10 आईटी पार्क, 2 इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर मौजूद।
- इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में प्लग एवं प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर।
- उचित दर पर 24X7 गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति।
- लो रिस्क सीस्मिक ज़ोन के कारण डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए आदर्श स्थान।

टैक्सटाइल-गारमेंट्स

- मध्यप्रदेश 43% भारतीय और 24% वैश्विक जैविक रूई का उत्पादक राज्य है।
- 60 से अधिक टैक्सटाइल यूनिट में 4000 से अधिक लूम्स और 2.5 मिलियन स्पिंडल्स कार्यरत।
- राज्य के टैक्सटाइल सेक्टर में जिनिंग से लेकर बुनाई, गारमेंटिंग की सभी प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित।
- भारत सरकार की पीएलआई योजना में राज्य के टैक्सटाइल सेक्टर को 3513 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त।
- गारमेंट यूनिट के प्लांट एवं मशीनरी में निवेश के 200% तक का पॉलिसी इंसेंटिव।
- 200 से अधिक रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर, इंदौर में अपैरल डिजाइनिंग सेंटर।
- मध्यप्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट एनआईएफटी, एनआईडी भोपाल और आईआईआईटीडीएम जबलपुर जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फैशन डिजाइनिंग में स्किल रिसोर्स प्रदान करने हेतु।

डिफेंस एवं ऐरोस्पेस

- रक्षा उपकरण निर्माण के लिए रणनीतिक स्थान।
- रेयर अर्थ मेटल अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण हेतु भोपाल में रेयर अर्थ और टाइटेनियम थीम पार्क प्रस्तावित।
- 06 रक्षा पीएसयू - जबलपुर में 04, 1 कटनी और 1 इटारसी में।
- भारत की पहली स्माल आर्म उत्पादन हेतु निजी इकाई मालनपुर में स्थित।
- 05 वाणिज्यिक हवाई अड्डे, भोपाल और इंदौर हवाई अड्डे एमआरओ गतिविधि के लिए उपयुक्त, उद्योग/सिविल - हवाई सेवाओं के लिए 28 हवाई पट्टियां।
- इंदौर के पास मेगा इन्वेस्टमेंट क्षेत्र के साथ ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।

फूड प्रोसेसिंग

कृषि मध्यप्रदेश की ताकत है इसलिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए यह आदर्श राज्य है। यही खूबियां इसे देश के अन्य राज्यों से अलग बनाती हैं।

- मध्यप्रदेश को भारत का फूड बास्केट कहा जाता है।
- 45 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि, जो 10 प्रमुख नदियों से जुड़ी है, जिसके कारण राज्य में उत्तम सिंचाई व्यवस्था है।
- मसालों, संतरा, अदरक, लहसुन, दलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य।
- फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को विशेष रियायत के साथ राज्य में 8 सरकारी फूड पार्क, 2 निजी मेगा फूड पार्क मौजूद।
- 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार।

फार्मास्यूटिकल

- इन्दौर, देवास, भोपाल, मंडीदीप, मालनपुर, पीथमपुर स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन में फार्मा क्लस्टर
- 300 फार्मा एवं मेडिकल डिवाइस यूनिट से 1 लाख से अधिक लोगों को मिल रहा रोज़गार।
- विक्रम उद्योगपुरी, उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना
- साल 2021 में राज्य से 10 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक का फार्मा निर्यात।
- कुल 160 से अधिक देशों में राज्य में बनने वाली दवाएं निर्यात हो रही हैं। जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, ब्राज़ील, इटली प्रमुख हैं।

नवकरणीय ऊर्जा

- मध्यप्रदेश नवकरणीय ऊर्जा के सृजन लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। राज्य की नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता साल 2012 की तुलना में 11 गुना बढ़ गई है।
- पर्याप्त सोलर रेडिएशन के साथ राज्य सोलर पॉवर प्लांट स्थापित करने के लिए आदर्श स्थान है।
- तकनीकी रूप से मजबूत नवकरणीय ऊर्जा पॉलिसी बनाकर नवकरणीय ऊर्जा उपकरण मैन्यूफैक्चरिंग और इनोवेशन करने वाला पहला राज्य है।
- नवकरणीय ऊर्जा का मध्यप्रदेश की ऊर्जा क्षमता में 20 प्रतिशत का योगदान है।
- सांची को राज्य की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पार्क में से एक ओंकारेश्वर में प्रस्तावित।
- रीवा सोलर पावर प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसीडेंट अवॉर्ड से सम्मानित।

स्टार्टअप नीति

- मध्यप्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्पाद आधारित स्टार्टअप को विशेष सहयोग की व्यवस्था।
- हर तरह के आर्थिक सहयोग और जानकारी के लिए ऑनलाइन पोर्टल।
- राज्य में 2500 से अधिक डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और 45 से अधिक इनक्यूबेटर।
- महिला उद्यमियों द्वारा 1,100 से अधिक स्टार्टअप संचालित।
- राज्य में 26 लाख से अधिक एमएसएमई। राज्य की जीडीपी में 25.88 प्रतिशत योगदान।

ऑटोमोबाइल

मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय स्तर का टेस्टिंग ट्रेक है इस कारण अब दर्जन बड़ी कंपनियां पहले से यहां पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में हैं। गुड का सतत बढ़ावा सरकार अन्य बड़े उद्योग घरानों को न्यौता दे रही है।

- 10 से अधिक उपकरण मैन्यूफैक्चरर।
- 200 से अधिक ऑटो कंपोनेंट मैन्यूफैक्चरर।
- 2770 से अधिक इंजीनियरिंग मैन्यूफैक्चरर।
- 4500 हेक्टेयर में फैला पीथमपुर औद्योगिक क्लस्टर।
- NATRAX पीथमपुर एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रेक।

लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग

- लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग के लिए बेहतर सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी।
- देश के लगभग मध्य में स्थित होने के कारण लॉजिस्टिक बेहद सुविधाजनक।
- देश की 50% आबादी राज्य के प्रभाव क्षेत्र में होने से प्रमुख उपभोक्ता बाज़ार तक पहुंच।
- 40 एमएमटी की वेयरहाउसिंग क्षमता और 13.2 एमएमटी की कोल्ड स्टोरेज क्षमता।
- भारत सरकार के सहयोग से इंदौर और भोपाल में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण प्रस्तावित।
- स्टील साइलो के निर्माण में अग्रणी राज्य।
- लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग इकाई/पार्क के लिए आकर्षक इंसेंटिव पॉलिसी।

D19879-22

सीएम राइज़ स्कूल
बच्चों का स्वर्णिम भविष्य

उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा हेतु सर्वसुविधा संपन्न
विश्वस्तरीय 9,200 सीएम राइज़ स्कूल

उत्कृष्टता की ओर लंबी छलांग
राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे (एन.ए.एस.) 2021-22

देश में मध्यप्रदेश का पांचवां स्थान

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा त्रि-वार्षिक समयावधि में शैक्षिक गुणवत्ता की परख हेतु राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे (National Achievement Survey) का आयोजन किया जाता है, जिसमें राज्यों की शैक्षिक रैंकिंग निर्धारित होती है। वर्ष 2017 के सर्वे में मध्यप्रदेश देश में 17वें स्थान पर था। कोविड संकटकाल के पश्चात 2021 के सर्वे के बाद मध्यप्रदेश देश में पांचवें स्थान पर आ गया है। यह उपलब्धि प्रदेश में स्कूली शिक्षा के अंतर्गत किए जा रहे अथक प्रयासों का परिणाम है।

अन्य महत्वपूर्ण शैक्षणिक पहल

अनुगूंज
STEAM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और गणित) के जरिए शिक्षा को बढ़ावा देने में अग्रणी राज्य। यह कार्यक्रम बच्चों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का एक मंच प्रदान करता है।

उमंग
एक जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम, जो स्वस्थ मानसिकता को बढ़ावा देने और सही दृष्टिकोण विकसित करने पर केंद्रित है, जिससे बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है।

ई.सी.सी.ई.
(आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ई.सी.सी.ई. प्रशिक्षण)
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण हेतु राज्यस्तरीय प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण और डिजिटल मॉड्यूल द्वारा संचालित मिश्रित व्यक्तिगत प्रशिक्षण मॉडल।

एफ.एल.एन.
(मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान)
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तीसरी कक्षा तक सभी छात्रों में पढ़ने-लिखने और गणित के बुनियादी कौशल विकसित करना।

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

D19879-22